हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2007

खण्ड–1; अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 13 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 28
शोक प्रस्ताव	(3) 56
नियम 64 के अधीन प्रस्ताव	(3) 56
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/वाक आउट	(3) 56
हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी की छात्राओं का अभिनन्दन	(3) 60
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(3) 60

मूल्य : 158

बैठक का स्थगन	(3)61
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)63
बैठक का स्थगन	(3)65
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)68
वैयक्तिक स्पष्टीकरण (परिवहन मंत्री द्वारा)	(3)71
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)72
सदस्यों का नाम लेना	(3)73
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)75
बैठक का समय बढ़ाना	(3)96
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)96
बैठक का समय बढ़ाना	(3)110
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)110

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now Question Hour starts.

Providing Reservation to the Upper Caste

*577. **Ch. Dharampal Singh Malik** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the State Government to provide reservation to those persons who are financially weak belonging to the upper caste of the State ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय स्पीकर सर, हमारी आजादी के बाद से ही कुछ वर्गों को रिज़र्वेशन देने का संविधान में प्रोविजन किया गया और प्रांत की सरकारों ने भी यही प्रोविज़न किया है। सभी ने अपने-अपने तरीके से उस असमानता को खत्म करने की कोशिश की और एस०सीज़० और बी०सीज़० को रिज़र्वेशन दी। स्पीकर सर, हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी ने भी बजट में अदर बैकवर्ड क्लासिज के लिए पैसे का प्रावधान किया है। उन्होंने शिक्षा पर हो रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए उस पर 1 प्रतिशत एडिशनल शिक्षा उपकर लगाने का प्रबन्ध भी किया है। उसी सम्बन्ध में मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं । हमारी सरकार ने उसी तर्ज पर चलकर जो अपर क्लास के लोग थे उनमें और उन लोगों के बीच में जो फर्क था, जो असमानता थी, उस असमानता को खत्म किया था। आज वह असमानता फिर शुरू हो गई है। अपर क्लास के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाईचांस जन्म तो ऊंची जाति में ले लिया है लेकिन आज उन लोगों के हालात बहुत ही खराब हैं। इसका अन्दाजा कोई नहीं लगा सकता है और न ही इन लोगों के लिए आरक्षण देने के लिए कानून में कोई प्रावधान है। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यह सरकार इन अपर क्लास के गरीबों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश करेगी क्योंकि आज मैं समझता हूं कि गरीब और अमीर के बीच में पैदा हो रहे गैप को खत्म करने की आवश्यकता है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय साथी खुद एक काबिल वकील हैं। सर, मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि संविधान में जो आरक्षण देने का प्रावधान है वह धारा 16(4) के अधीन है और यह फंडामैंटल राईट्स के चैप्टर का हिस्सा है। स्पीकर सर, हिन्दुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अनुसूचित जाति

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

और पिछड़े वर्ग के अलावा किसी और के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इकोनोमिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की परिपाटी में नहीं आता, यह बात माननीय सदस्य भी जानते हैं। कई बार इस तरह का आरक्षण विभिन्न स्टेटस ने अपने लैवल पर किया था लेकिन कोर्ट ने उसको स्ट्रकडाउन कर दिया था। माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री के द्वारा जो अदर बैकवर्ड क्लासिज हैं उनके उत्थान के लिए जो आज की यू०पी०ए० की सरकार ने कदम उठाया है, के बारे में चर्चा की। उस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं that Backward Classes are covered under Article 16 particularly Article 16(4) of the Constitution of India. आप उनके लिए स्पैशल प्रावधान कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के अलावा आप इनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी विशेष जाति वर्ग के लिए आप आरक्षण नहीं कर सकते हैं। फिर भी स्पीकर सर, हरियाणा सरकार ने आर्थिक तौर पर जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया है कि अगर किसी के परिवार की पारिवारिक आय 3600 रुपये से कम है तो सरकारी नौकरी में एंट्री के लिए उसको ऐज में पांच साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसके अलावा जो ऐग्जाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या एच०एस०एस०सी० द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उनमें 75 परसैंट फीस तक की रियायत उनको दी जाती है जिनकी फैमली इन्कम 3600 रुपये से कम है। स्पीकर सर, ऐसे सभी वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वह सरकार की दूसरी सभी स्कीम्ज़ जैसे ओल्ड ऐज पैंशन, विडो पैंशन, हैंडीकैप्ड पैंशन और लाडली आदि का भी वे फायदा ले सकते हैं परन्तु इनके लिए आरक्षण देने का प्रावधान संविधान की परिपाटी में नहीं किया गया है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मेरा सवाल सैंट्रल गवर्नमैंट से संबंधित नहीं है। स्टेट सब्जैक्ट के हिसाब से भी हम इस बारे में विचार कर सकते हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट की बात अलग है। यह बात ठीक है कि कांस्टीच्यूशन में केवल एस०सीज० या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही सैंट्रल सर्विसिज में आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन दूसरे अपर कास्ट के गरीब वर्गों के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यह सैंट्रल या स्टेट की बात नहीं है everybody, every State is governed by the constitution. मंत्री जी ने कांस्टीच्यूशन में दिए गए प्रावधानों की बात कही है। वैसे तो आपका रिप्लाई आ गया है लेकिन यदि आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो आप स्पैसिफिक क्वैश्चन ही पूछें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात बिल्कुल सही है लेकिन जब हम कहते हैं कि जाति विहीन, कास्ट विहीन समाज होना चाहिए और हम इस तरह की बात भी करते हैं तथा उस तरफ हम बढ़े भी हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ जगहों पर अपर कास्ट के गरीब वर्ग के लोगों को भी फीस में या ऐज में रिलैक्सेशन दी गयी है, जब हम यहां तक जा सकते हैं तो क्या हम उनके बारे में सर्विस के अंदर, शिक्षा के अंदर या ऐडमिशन के मामले में विचार नहीं कर सकते ? हमें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही गहरा विषय है। जो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब ने जो चिंता जाहिर की है तो यह बात ठीक है कि दूसरे वर्गों में भी बहुत गरीब आदमी हैं। मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा कि हम इनको भी सुविधाएं दे रहे हैं। इस समय जो 3600 रुपये की अपर लिमिट गरीब वर्ग के लोगों के लिए है हम इस लिमिट को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी जो बन रही है उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि इसमें जो कोई भी अपना इंस्टीच्यूट खोलेगा उसमें उसको 25 परसैंट सीट हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रखनी होंगी और उसमें से पांच परसैंट सीटों पर फुल फी कनसेशन देना होगा, दस परसैंट सीटों पर 50 परसैंट फी कनसेशन और बाकी दस परसैंट सीटों पर 25 परसैंट फी कनसेशन देना होगा। अध्यक्ष महोदय, जो गरीब आदमी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्यादा खर्चा ऐफोर्ड नहीं कर सकते वे अब इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात पर बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है कि जो गरीब आदमी हैं उनको शिक्षा मिले चाहे वे किसी भी वर्ग से क्यों न संबंधित हों, इनको ऊपर उठने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार सभी वर्गों के लिए चिन्तित हैं, यह बात अक्सर कही भी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में एक व्यवस्था कायम की गयी थी कि एस०सी०-ए और एस०सी०-बी वर्ग के लिए चाहे वह शैक्षणिक संस्थाओं की बात हो या नौकरियों की बात हो, उनमें दलित वर्ग के हर आदमी को इसका लाभ मिलेगा लेकिन पिछले दिनों अखबारों में यह बात आयी थी और उनमें इस बात का वर्णन नहीं किया गया था कि एस०सी०-ए वर्ग के लिए कितना रिजर्वेशन है और एस०सी०-बी वर्ग के लिए कितना रिजर्वेशन है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस व्यवस्था को खत्म करेगी ? मंत्री जी विस्तार से उस व्यवस्था के बारे में सदन को बतायें कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, वैसे तो इनका यह सवाल मेन प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु फिर भी मैं आपकी अनुमति से इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एस०सी०-ए और बी वर्ग का आरक्षण अलग-अलग था लेकिन कुछ लोगों ने इसको चुनौती दी थी और हमारे अपने उच्च न्यायालय ने इसको क्वैश कर दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है जिस प्रकार का निर्णय वह करेगी, वह हम लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि वे खड़े होकर आपकी अनुमति से प्रश्न पूछें और सदन की गरिमा का ध्यान रखें। ये बहुत ही सुलझे हुए, बुद्धिमान और अच्छे पार्लियामैंटेरियन हैं लेकिन गलत पार्टी के अंदर हैं। आज तो इनको भय भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आज इनके नेता भी नहीं आए हैं इसलिए खुलकर बोलें। ये बैठे-बैठे सवाल पूछ रहे है लेकिन फिर भी मैं इनको बता देता हूं। हरियाणा सरकार की मौजूदा नीति के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें शिडयूल्ड कास्टस की 20 परसैंट क्लास 1 और 2 पोस्टों में रिजर्वेशन हैं और इसी तरह क्लास 3 और 4 में भी रिजर्वेशन है। जिसमें से 10 परसैंट ब्लॉक ए के लिए और 10 परसैंट ब्लॉक बी के लिए हैं। पिछड़े वर्गों के लिए क्लास 1 और 2 में 10 परसैंट और क्लास 3-4 में 27 परसैंट रिजर्वेशन है जिसमें से 16 परसैंट ब्लॉक ए में और 11 परसैंट ब्लॉक बी में है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्लास 1 और 2 में 5 परसैंट रिजर्वेशन है। फिजिकली हैण्डीकैप्ड के लिए क्लास 1 और 2 में 3 परसैंट है और फिजिकल हैंडीकैप्ड क्लास 3 और 4 के लिए 3 परसैंट रिजर्वेशन है। एक परसैंट रिजर्वेशन ब्लाईंड व्यक्तियों के लिए है और एक परसैंट रिजर्वेशन हियरिंग इम्पेयरमैंट के

लिए है। इसके अलावा एक परसैंट लोकोमोटर्स डिसैबल्ड व सैरीब्रल पैल्सी के लिए भी रिज़र्वेशन है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने कानूनी संवैधानिक पहलुओं पर काफी संतोषजनक जवाब दिया है लेकिन अध्यक्ष महोदय देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार क्या संविधान में संशोधन का कोई प्रोविजन नहीं है, यह मैं जानना चाहता हूं ? जहां तक रिज़र्वेशन का उद्देश्य था वह यह था कि जो गरीब, पिछड़े, अभावग्रस्त व आर्थिक तौर पर एक वर्ग विशेष पीछे रह गया था उसके लिए रिज़र्वेशन आवश्यक था। आज भी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई इसलिए इसमें संशोधन आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। स्टेट गवर्नमैंट या विधान सभा देशकाल के अनुरूप उस वर्ग विशेष में यह स्थिति पैदा न हो उसके लिए क्या गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को रिकमंड कर सकती है, क्या उसके लिए व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया है। अब आप बैठ जाएं। आप काफी सीनियर मैंबर हैं। मंत्री भी रह चुके हैं। कांस्टीच्यूशन में संशोधन के लिए जो बात आई है उसके लिए this house is not competent.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केशव नंद भारती और इंदिरा साहनी केसों के बारे में 16 जजिज की खंडपीठ में देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। इन निर्णयों के बाद यह बात बिल्कुल क्लीयर हो गई है कि जो संविधान में फंडामैंट्ल राइट्स का चैप्टर है उसमें संशोधन करने के लिए देश की दो-तिहाई प्रान्तों की विधायिकायें व उससे पहले संसद के दोनों सदन बहुमत से कानून पास करें। उसके बाद भी इसमें यह बात होनी चाहिए कि यह संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टीच्यूशन की थ्यूरी है उस को वॉइलेट न करता हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बात संभव है जो संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया है उसके अलावा संविधान को तरमीम करने का न किसी विधायिका को अधिकार है और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं शायद उसके बाद संसद और सारी विधानसभाओं को भी इसका अधिकार नहीं है।

Status of Industry to Agriculture Sector

***585. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give status of Industry to Agriculture Sector; if so, the time by which the above said proposal is likely to be implemented; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the Agriculture Sector more developed and effective, so that the farmers' community can earn more ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) :

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी, कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा न मिलने से हालात यह पैदा हो गए हैं कि अगर हम दिल्ली से निकल कर जयपुर तक चले जायें तो रास्ते में आपको कोई किसान नहीं मिलेगा, खेत नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। पूरी सड़क पर आपको चार दीवारी बनाने की होड़ मिलेगी क्योंकि आज किसान को यह चिन्ता हो गई है कि मेरे पास जो जमीन है पता नहीं यह कब चली जायेगी, पता नहीं कब यह जमीन किसी बड़ी कम्पनी के पास होगी और क्या सरकार इस जमीन को किसान के पास रहने देगी या नहीं ? पता नहीं कब सरकार इस पर कब्जा कर लेगी, कब किसी कम्पनी को या किसी पूंजीपति को यह जमीन सरकार द्वारा दे दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, किसान जो खेती करता है, फसल उगाता है और उसके पास जो खेत और खतौनी है उसके लिए वह चिन्तित है कि पता नहीं यह खेत और खतौनी उसके पास रहेगी या नहीं। उद्योगपतियों को तो सुविधाएं दी जाती हैं, लोन दिया जाता है, बिजली की, पानी की सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन किसान के पास जो दादालाई जमीन है उसके लिए उसके पास कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि जो जमीन उसके पास है वह बच जायेगी या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि किसानों की जो खेत और खतौनी है वह उनके पास बच जायेगी ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी सप्लीमैंट्री क्वेश्चन में प्रश्न के 'ए' और 'बी' भाग का प्रश्न मिक्स कर दिया। 'ए' का प्रश्न है कि क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने जा रही है। इसके जवाब में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया गया तो किसानों पर इन्कम टैक्स लगना शुरू हो जायेगा, किसान को कोई कन्सैशन नहीं मिलेंगे, उनको मिलने वाली बिजली का रेट उद्योग की तरह बढ़ जायेगा। जिसके कारण उनका खर्चा और बढ जायेगा और इससे किसानों को ज्यादा दिक्कत आयेगी। इसलिए इसको उद्योग का दर्जा देना ठीक नहीं रहेगा। यादव साहब ने डिवैल्पमैंट की दूसरी बात कही है। जहां तक डिवैल्पमैंट की बात है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ये कहते कुछ हैं और इनके दिल में कुछ और ही बात होती है। हुड्डा साहब की सरकार ने इन दो सालों में किसानों की भलाई के जितने कार्य किए हैं उतने पहले किसी ने नहीं किए। सरकार ने लैंड रिक्लेमेशन के लिए 923 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बनाया है। इस सरकार ने 45750 एकड़ भूमि को रिक्लेमेशन करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार बी०टी० कॉटन की फसल जो पिछले साल एक लाख एकड़ में बोई गई थी, इस साल 8 लाख एकड़ में बीजने का लक्ष्य बनाया है। इसी प्रकार पैडी हाईब्रीड जो पिछले साल एक लाख एकड़ में थी, इस साल दो लाख एकड़ में लगाने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार सॉयल हैल्थ को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मन्जूरी दी है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसमें इरीगेशन और रेवेन्यू दोनों विभागों द्वारा गिरदावरी की जाती है। हर साल दो विभाग गिरदावरी करते हैं। सरकार ने यह आदेश दिए हैं कि ये दोनों विभाग हरियाणा की हर

[सरदार एच०एस० चट्ठा]

जमीन की सॉयल को देखें और उसका रिकार्ड अपने दफ्तर में रखें कि किस गांव की जमीन में कौन सा तत्व कम है और किसान को कौन सी फसल बोने के लिए क्या करना चाहिए। हरियाणा में तकरीबन 6 हजार गांव हैं एग्रीकल्चर के दफ्तर में हर गांव की जमीन का रिकार्ड मौजूद है कि कौन से गांव में कैसी जमीन है। पिछली सरकार ने किसानों को 25 प्रतिशत सबसिडी दी थी और एक बार बड़ी बहादुरी करके एक सरकार ने 50 प्रतिशत सबसिडी दे दी थी लेकिन हुड्डा साहब की सरकार ने तीन हजार क्विंटल ढैंचा जमीदारों को देने का निर्णय किया है और अगले साल 6 हजार क्विंटल ढैंचा जमींदारों को देने की योजना है। शूगर केन की प्रोडक्शन के बारे में मैं सदन को एश्योर करता हूं कि शूगर केन की प्रोडक्शन अगले साल डबल हो जायेगी। जमीन उतनी ही होगी लेकिन शूगर केन की पैदावार डबल होगी। इसके लिए हमने नया तरीका निकाला है। सरकार ने इसके लिए किसानों को कन्सैशन दिया है। शूगर मिलों ने और सरकार ने नई तकनीक से शूगर केन लगाने के लिए मशीनें खरीदी हैं और वे मशीनें किसानों को दी जा रही हैं। इसी तरह से स्पीकर सर, होर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत से तरीके अपनाये गये हैं। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चैम्बर बनाये गये हैं ताकि लोगों की सब्जी आदि को स्टोर किया जा सके। इसके अलिरिक्त राई में बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट बनाई जा रही है। ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है कि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने कीनू एक्सपोर्ट किया है। ये सभी कार्य हरियाणा के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी भलाई के लिए ही किए जा रहे हैं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अपने प्रदेश का किसान अपनी जमीन बेचकर राजस्थान में जमीन खरीद कर वहां प्लायन कर रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कोई ठोस कदम उठा रही है ? सरकार को प्रदेश के किसानों का प्लायन रोकने के लिए इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि हमारे प्रदेश के किसानों को अपने अनाज का मूल्य स्वयं निर्धारित करने का हक हो।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि हर किसान चाहता है कि उसकी जमीन डबल हो जाये, तीन गुणा हो जाये या चार गुणा हो जाये। मैं स्वयं किसान हूं, मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूं यदि मेरी जमीन तीन-चार गुणा हो जाये। इसमें हर्ज की क्या बात है ? यदि हमारे प्रदेश का किसान अपने यहां जमीन बेचकर दूसरे प्रदेश में तीन-चार गुणा अधिक जमीन खरीद लेता है और वहां पर खेती करता है तो इसमें क्या बुराई है ? जो किसान अपने यहां से जाता है वह अपने प्रदेश का बेटा है यदि वह कहीं और जाकर तरक्की करता है तो यह हमारे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। स्पीकर सर, हम तो हर तरह से प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सालों में किसानों पर बड़े अत्याचार हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी इस समय सदन में नहीं बैठे। उनके समय में जिन किसानों ने अपने खून-पसीने की कमाई से 15-20 सालों से जो मकान बना रखे थे, उनको तोड़ा गया था। उस समय कई गांवों में चौटाला जी को लोगों ने बुलाया और उन्हें मालायें भी डालीं। लोगों ने उनसे कहा कि हमारे मकान न तोड़े जायें। उस समय पता नहीं चलता था कि कब रात के समय जे०सी०बी० की मशीन आ जाये और उनके मकान तोड़ कर चली जाये। इस तरह का

माहौल उस समय बन गया था। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यह सब बंद करवा दिया है। (विघ्न) जहां तक किसानों की जमीन बेचने का जिक्र किया गया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अब किसान को पूरी छूट है कि वह पूरे दामों पर अपनी जमीन बेचे। एस०ई०जैड० के लिए जो 25000 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है वह जमीन खारे पानी की है। उसकी कीमत 8 लाख रुपये से अधिक की नहीं थी लेकिन सरकार उसकी कीमत 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। किसी भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं की गई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री नरेश यादव जी ने जो चिंता किसानों के बारे में व्यक्त की है उस बारे हम पूरी तरह से सचेत हैं। सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले दस साल तक जितनी हमारी टोटल जमीन है उसके एक प्रतिशत से ज्यादा जमीन इण्डस्ट्रीज के लिए यूज नहीं की जायेगी। प्रदेश की टोटल एक करोड़ 9 लाख एकड़ भूमि है जिसकी 99 प्रतिशत जमीन ऐग्रीकल्चर और रिहायशी परपज के लिये यूज की जायेगी और एक प्रतिशत से अधिक जमीन इण्डस्ट्री के लिए नहीं होगी।

Construction of Boundary Wall of Grain Market in Nangal Chaudhary

***592. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time limit by which the construction work of boundary wall and sheds of the grain market of Nangal Chaudhary is likely to be started ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, the boundary wall of grain market at Nangal Chaudhary already exists except a few gaps which will be completed after the removal of encroachments and making suitable drainage system of rain water. There is no proposal to construct a shed yet.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। माननीय मंत्री जी को गलत जवाब देकर अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हमने मौके पर देखा है कि यह बिल्कुल थोड़ी बहुत भी नहीं बनी हुई है। मैं तो यह चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी को प्रिविलेज कमेटी के सामने बुलाना चाहिए और इस कमेटी को मौके पर जाकर देखना चाहिए। मैं और श्री नरेश यादव हम दोनों ने वहां पर जाकर देखा है। शैड और चारदीवारी न होने के कारण हमारी सरसों की सारी फसल गल गई है। मैं तो माननीय मंत्री जी को केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि उन्होंने वायदा किया हुआ है कि शैड बनायेंगे, चारदीवारी बनायेंगे। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमको टाईमफ्रेम बता दीजिए कि कितने समय में यह बन जायेगी ?

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह बाऊंडरी वाल टोटल 1645 गज में है। इसमें से 266 गज इन्क्रोचमैंट है। हम वह इन्क्रोचमैंट हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वह इन्क्रोचमैंट हट जायेगी उसी वक्त यह बन जायेगी। हम इसको जल्द से जल्द कम्पलीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी कोसली मण्डी में इसी तरह की समस्या है। मुझे इस मण्डी की चारदीवारी के बारे में पूछना है जो कि इस समय इनकम्पलीट है। कोसली

[श्रीमती अनिता यादव]

मण्डी के व्यापारियों ने इसके लिए पैसा भी दे रखा है लेकिन कोसली मण्डी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इसमें कितना समय लगेगा और कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, अगर बहन जी मेरे को अलग से नोटिस दे दें तो मैं बता दूंगा और ठीक जवाब दे दूंगा।

Agreement for Purchasing of Electricity

***597. Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state the name of the company with which an agreement was made for purchasing of electricity to meet out the demand of the state during the current year, togetherwith the rate and quantum thereof ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, A statement is laid on the Table of the House.

Statement

In order to meet the long term electricity demand of the State, the Government has entered into long term agreements for 25/35 years with M/s PTC India Ltd. for supply of power from various projects. Further, to meet with demand of the State during the current year, short term bilatral agreements have been made for purchase of power through licensed traders or directly from surplus power States.

Detailed information regarding long term power agreements and short term bilateral agreements for purchase of power is given below :

(A.) Details of the projects where State Government has entered into agreement with M/s PTC India Ltd. for procurement of Power on long term basis for a period of 25/35 years :

Name of the Project	Capacity (MW)	Company with whom HPGCL has entered into an agreement	Developer of the Project	Quantum of Power being contracted (MW)	Levelised Rate (in Rs./Unit)	Period of contract in Years)
Teesta Stage-III Hydro Electric Project in Sikkim	1200	M/s PTC India Ltd., New Delhi	Teesta Urja Power Ltd.	200	Around 2.25	35
Karcham Wangtoo Hydro Electric Project in Himachal Pradesh	1000	M/s PTC India Ltd., New Delhi	Jaypee Group	200	Around 2.25	35
Coal based Amarkantak Project (Phase-II) in Chhatisgarh	3000	M/s PTC India Ltd., New Delhi	Lanco Group	300	2.32	25
Budhil Hydro Electric Project in Himachal Pradesh	70	M/s PTC India Ltd.,New Delhi	Lanco Group	70	2.21	35

(B.) Short Term Bilateral Arrangements made during current year to meet with the seasonal/day to day demand :

For 2006-07 :

Sr. No.	Name of Traders/ Suppliers	Project/Source of power	Quantum & type of power	Rate (Rs./KWH)	Period From	To
1	2	3	4	5	6	7
1.	Reliance Energy Trading Ltd. (RETL)	WDSEB power	30 MW off peak 0200 to 0700 hrs	2.66	1-07-06	30-09-06
2.	NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NVVN)	Tripura power	25 MW peak 1700 to 2300 hrs	4.10	1-04-06	30-06-06
3.	WBSEB	WBSEB power	100 MW off peak	(i) 3.955 for April, 06 (ii) 3.965 for May, 06 (iii) 3.975 for June, 06	April, 06	June, 06
4.	NVVN	KSEB power	50 MW off peak 18 hrs.	3.65	April, 06	April, 06
5.	Reliance Energy Trading Ltd.	CPP in Andhra Pradesh	28 MW RTC	4.19 for peak 3.79 for off peak	July, 06	Sept., 06
6.	PTC India Ltd. (PTC)	Gridco	150 MW peak	4.80	April, 06	June, 06
7.	NVVN	KSEB power	50MW off peak 18 hrs.	4.29	May, 06	June,06
8.	PTC	HP Govt. power	(i) 101 MW RTC (ii) 111 MW RTC	(i) 4.65 April, 06 4.70 May-Oct. 06 (ii) 4.45 April, 06 4.50 May-Oct., 06	(i) 1-04-06 (ii) 1-4-06	(i) 31-10-06 (ii) 31-10-06
9.	PTC	HP Govt. power	40-50 MW RTC	5.81	22-05-06	30-09-06
10.	PTC	JSWEL	100 RTC	peak-4.3981 off peak-4.2273	01-07-06	01-09-06
11.	Tata Power Trading Ltd. (TPTL)	WBSEB power	100MW off peak	5.255	15-07-06	31-07-06
12.	NVVN	Tripura power	25MW peak	4.69	01-07-06	31-07-06
13.	NVVN	KSEB	100MW off peak	4.29	01-07-06	31-07-06
14.	RETL	CPP in Andhra Pradesh	40MW RTC	(i) 4.85 peak (ii) 4.65 off peak	01-07-06	31-08-06
15.	TPTL	MPSEB power	150MW RTC	(i) 5.357 peak (ii) 5.206 off peak	16-07-06	15-09-06
16.	Maruti Udyog Ltd. (MUL)	Maruti Udyog	20MW RTC as and when available	4	12-5-06	27-5-06
17.	NVVN	Tripura power	25MW peak	4.69	01-08-06	30-09-06
18.	TPTL	MPSEB	200MW off peak 18 hrs.	5.26	01-08-06	31-08-06

[Capt. Ajay Singh Yadav]

1	2	3	4	5	6	7
19.	M/s.TPTL	WBSEB power	200MW off peak 17 hrs.	5.255	01-09-06	30-9-06
20.	NVVN	KSEB	50MW off peak	4.34	01-08-06	30-08-06
21.	NVVN	ASEB	50MW off peak day ahead	4.29	01-07-06	31-07-06
22.	NVVN	KSEB	50MW	4.39	01-09-06	30-09-06
23.	NVVN	KPTCL	200MW RTC day ahead basis	peak 4.6980 off peak 3.4460 RTC 3.7590	01-06-06	31-07-06
24.	TPTL	WBSEB power	40 MW off peak	2.97	16-06-06	30-06-06
25.	NVVN	J&K	100 MW off peak 5 hrs. on day ahead basis	4.015	01-07-06	31-08-06
26.	Adani Enterprises Ltd. (AEL)	GUVNL	100MW RTC on day ahead basis	peak 3.04 off peak 2.54	01-07-06	04-08-06
27.	AEL	GUVNL	100MW RTC on day ahead basis	peak 3.30 off peak 2.90	05-08-06	31-08-06
28.	NVVN	KPTCL	150 MW peak & off peak day ahead basis	off peak 3.446 peak 4.698	01-08-06	30-09-06
29.	NVVN	KPTCL	100MW peak & off peak	off peak 3.698 peak 4.698	01-10-06	31-12-06
30.	NVVN	APPCC	100MW peak & off peak on day ahead basis	off peak 4.29 peak 4.69	01-08-06	30-09-06
31.	NVVN	APPCC	100 MW off peak 4 hrs & 6 hrs peak day ahead basis	off peak 4.29 peak 2.79	5-08-06	15-08-06
32.	NVVN	APPCC	100MW 4 hrs. off peak & peak	off peak 4.29 peak 4.69	01-10-06	31-12-06
33.	NVVN	KSEB power	50MW 18 hrs. off peak	4.39	01-10-06	31-10-06
34.	AEL	APPCC	100MW hrs. off peak	4.39	01-11-06	31-12-06
35.	RETL	CESC	60MW off peak 9 hrs.	4.04	01-10-06	31-10-06
36.	RETL	CESC	40MW 9 hrs. Sunday & Holiday	4.04	01-10-06	31-10-06
37.	NVVN	J&K	10MW off peak (0000-0500)	4.04	15-09-06	30-09-06
38.	M/s. PTC	AP	100MW peak 100MW off peak	4.32 4.04	20-09-06	30-09-06
39.	AEL	DVC	100MW 18 hrs. off peak	5.69	01-01-07	31-03-07
40.	AEL	DVC	50MW 18 hrs. off peak day ahead	5.69	01-01-07	31-03-07
41.	AEL	DVC	150MW 18 hrs. off peak day ahead	5.55	01-11-06	31-12-06
42.	AEL	Gridco	100MW 6 hrs. peak day ahead	5.76	01-12-06	31-12-06

1	2	3	4	5	6	7
43.	AEL	Gridco	200MW 18 hrs. off peak day ahead	5.66	01-12-06	31-12-06
44.	NVVN	Gridco	200MW peak & off peak day ahead	peak 5.76 off peak 5.78	01-11-06	30-11-06
45.	AEL	Gridco	200MW peak & off peak day ahead	peak 5.88 off peak 5.78	01-01-07	20-02-07
46.	AEL	Gridco	200MW peak & off peak day ahead	peak 5.68 off peak 5.58	01-03-07	31-03-07
47.	HPSEB	Banking	40MW off peak	—	01-12-06	31-08-07
48.	RETL	ER	upto 100MW off peak on day ahead basis	off peak 4.04	14-12-06	31-03-07

For 2007-08 :

Sr. No.	Name of Traders/ Suppliers	Project/Source of power	Quantom & type of power	Rate (Rs./KWH)	Period From	Period To
1	2	3	4	5	6	7
1.	RETL	ER	30MW off peak (0000-0930 & 2300-2400)	3.54 (0000-0930) 3.04 (2300-2400)	01-07-07	30-09-07
2.	RETL	SR	50MW 18hrs. off peak	3.89	01-07-07	30-09-07
3.	ISW Power Trading Co. (JSWPTC)	WBSEB	25MW (0500 to 1100)	6.50	01-05-07	31-05-07
			25MW (0400-1000)	6.52	01-06-07	30-06-07
4.	JSWPTC	Karnataka	50MW RTC	5.29	01-05-07	30-09-07
5.	Karam Chand Thapar & Bros. Ltd. (KCT)	WBSEB	30MW (0500 to 1100)	6.50	01-05-07	31-05-07
			30MW (0400-1000)	6.52	01-06-07	30-06-07

डॉ सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य की बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकारें अक्सर बिजली पैदा करती हैं, खरीदती हैं और दीर्घकालीन या अल्पकालीन समझौते कर प्रदेश की बिजली की कमी को पूरा करती हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने जवाब में कहा है कि इन्होंने दीर्घकालीन और अल्पकालीन समझौते भी किये हैं और इन समझौतों के अनुसार ही बिजली पूरी कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इन एग्रीमैंट के हिसाब से जो हम वर्तमान में बिजली पैदा करते हैं और जो बिजली हम खरीद रहे हैं उसके रेट में कितना अन्तर है? इसके अलावा क्या बिजली खरीदने के लिए परचेज एग्रीमैंट की हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन से अप्रूवल ले ली गई है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त स्टेट की स्थिति है तो यह बात बिल्कुल सही है कि स्टेट में पावर शोर्टेज है और खास तौर पर जो पीक आवर्ज हैं उनमें 1200 से 1500 मैगावाट की शोर्टेज है और ऑफ आवर्ज में 800 से 1000 मैगावाट की शोर्टेज है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली जो सरकार थीं उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 500 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया है। 6 माह तक एक

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

प्लांट बन्द रहा। जब वर्तमान सरकार पावर में आई उस वक्त टोटल जनरेशन की कपैसिटी 1587 मैगावाट थी और टोटल डिमांड 4 हजार से लेकर 5 हजार मैगावाट थी। इस सरकार ने, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मंत्री ने इस चैलैंज को लेते हुए यह कहा कि हम यह कोशिश करेंगे कि 10.00 बजे तकरीबन 5 हजार मैगावाट बिजली हम अपने कार्यकाल के अन्दर पैदा कर सकें। 600 मैगावाट का यमुना नगर का थर्मल पावर प्लांट बनना है। इस पावर प्लांट का 300 मैगावाट का पहला यूनिट मई, 2007 तक तैयार हो जाएगा जबकि 300 मैगावाट का जो दूसरा यूनिट है वह फरवरी, 2008 तक तैयार हो जाएगा। स्पीकर सर, जब से हरियाणा बना है तब से ले कर आज तक इन लोगों ने बिजली जैसी महत्वपूर्ण चीज़ को अनदेखा किया था जबकि हमारी सरकार ने उसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसके साथ ही साथ 1200 मैगावाट का एक कोल बेस्ड पावर प्लांट हिसार में लगना है जिसका अवॉर्ड जनवरी, 2007 में दिया गया है। दिसम्बर, 2009 में यह पावर प्लांट तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1200 मैगावाट बिजली इस प्लांट से प्राप्त होगी। वहां पर 600-600 मैगावाट के दो यूनिट लगाये गये हैं। इसके साथ ही साथ 1500 मैगावाट का पावर प्लांट ज्वायंट वैंचर में दिल्ली के साथ एन०टी०पी०सी० के द्वारा लगाया जाएगा। इसमें 750 मैगावाट बिजली का शेयर हरियाणा प्रदेश का होगा जबकि इसमें हरियाणा स्टेट की टोटल इक्विटी मात्र 300 करोड़ रुपये ही है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजैक्ट तैयार हो जाने के बाद 750 मैगावाट बिजली प्रदेश को प्राप्त होगी। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और ठोस सोच का ही परिचायक है कि स्टेट को इतना बड़ा फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए लौंग टर्म और शॉर्ट टर्म एग्रीमैंट हमने किए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने एक यह बात रखी है कि हरियाणा रैगुलेटरी कमीशन से कोई परमीशन ली है या नहीं ली गयी है, क्या उसने अपनी स्वीकृति प्रदान की है या नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सरकार ने बाकायदा उनसे एप्रूवल ली है और हमारे जितने भी इस तरह के प्रोजैक्टस हैं हम उनकी एप्रूवल सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन से लेते हैं। रेट्स के बारे में इन्होंने जो कहा है, यह आपने खुद देख लिया है कि रिप्लाई में 2.25 रुपये के आस-पास रेट इसमें दर्शाये गये हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में बिजली तकरीबन 4.80 रुपये, 4.29 रुपये, 5.25 रुपये के रेटस पर हमें 48 बार खरीदनी पड़ी। आप सभी जानते हैं कि जब बिजली की कमी होती है तो उस वक्त जो बिजली खरीदी जाती है उस पर खरीद रेट्स ज्यादा देने पड़ते हैं। तकरीबन 644.2 करोड़ रुपये की शॉर्ट टर्म के लिए हमें बिजली लेनी पड़ी है। इसके अलावा जो बिजली हमें आगे के लिए यानी वर्ष 2007-2008 के लिए आवश्यक होगी उसका प्रबन्ध भी हमने किया है। गर्मियों के दिनों की जो समस्या हमें रहेगी उसके लिए भी हमने शॉर्ट टर्म समझौते किए हैं जिसके लिए रेट साढ़े छः रुपये के हिसाब से भी हमें देना होगा। गर्मियों के सीजन के दौरान बिजली की दिक्कत न रहे इसके लिए हमने शॉर्ट टर्म और लौंग टर्म के लिए भी बिजली जरूरत के मुताबिक खरीदने के लिए एग्रीमैंट किए हैं। स्पीकर सर, पता नहीं इनको क्या अन्देशा हो जाता है। इनके श्रीमान नेता जी तो आज हाउस में नहीं आए हैं। विपक्ष के नेता तो वे वैसे ही नहीं है जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है। स्पीकर सर, मैं हाउस में डिप्टी लीडर रहा हूं लेकिन जब इनका राज था तो मुझे पीछे बिठा कर रखा था और मुझे यह कहते हुए फख होता है कि हमारे नेता की यह फ्राखदिली है कि विपक्ष का नेता न होते हुए भी उनको यहां पर बिठा कर रखा है। यह फर्क है हमारी और इनकी सरकार की वर्किंग में। फिर भी जिस प्रकार से हम सरकार चला रहे हैं

इन्हें हमेशा यह अन्देशा रहता है कि कहीं कोई घोटाला हो रहा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, सच बात तो यह है कि हो सकता है कि इनके नेता को अपने किए हुए कामों पर शर्म आ गई हो जिसके कारण वे आज हाउस में नहीं आए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब माननीय कप्तान साहब ने दिया है लेकिन इन्दौरा साहब इनका रिप्लाई सुनने की बजाएं टोका-टाकी में लगे हुए थे। स्पीकर सर, ये कानून के जानकार हैं और हम इन्हें बुद्धिमान भी मानते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि सारे पावर परचेज एग्रीमैंट जो हैं they are subject to approval of the Regulatory Commission. No power purchase agreement is possible without the approval of the Regulatory Commission. Speaker Sir, he should not ask such type of question, as this is a part of the established law.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न जो मैंने माननीय मन्त्री महोदय से किया था कि क्या जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उस रेट से कम या ज्यादा रेट पर बिजली हम खरीद रहे हैं ? उस सवाल का मन्त्री जी ने जवाब नहीं दिया है। इस बारे में मैं फिर से सप्लीमैंट्री पूछ लेता हूं (विघ्न) क्या इस एग्रीमैंट पर कोई ऑब्जैक्शन्ज़ लगे है और अगर लगे हैं तो क्या-क्या लगे हैं और लिन्को ग्रुप से जो बिजली खरीद रहे हैं वह कैसे खरीद रहे हैं? क्या यह सच है कि इन्होंने जिस कम्पनी से बिजली ली है वह कम्पनी यू०पी० को बिजली 1.91 पैसे प्रति यूनिट में दे रही है और वही कम्पनी हमें 2.25 पैसे या 2.35 पैसे बिजली प्रति यूनिट के हिसाब से दे रही है? (विघ्न) स्पीकर सर, क्या यह भी सच है कि 25 या 35 साल में इस प्लांट की जो डैप्रीसिएशन होगी वह जीरो के बराबर हो जाएगी यानि कि 25 या 35 साल में डैप्रीसिएशन इतनी हो जाएगी कि इस प्लांट की कीमत पूरी हो जाएगी ? उसके बाद का एग्रीमैंट सरकार ने क्या किया है क्या वह बिजली फ्री में दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपको सब कुछ पता है तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, यह सब पूछने का हमारा हक बनता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को क्लैरीफिकेशन देना चाहूंगा कि किसी भी सरकार में कोई भी पॉवर परचेज की जाती है तो यह पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के थ्रू की जाती है, यह स्टेचुटरी बॉडी है। यह परचेज एग्रीमैंट विद इन रूल्ज हुआ है और यह सबजैक्ट टू एप्रूवल ऑफ स्टेट रैगुलेटरी कमीशन है और यह आपके सवाल का जवाब है।

Construction of Cargo Airport in the State

***651. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the State Government has taken up the matter with the Government of India for the construction of Cargo Airport in the State; if so, the details thereof ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. A proposal for setting up of an International Airport which will also handle Cargo in Tehsil Bahadurgarh has been sent to the Ministry of Civil Aviation, Govt. of India, New Delhi. This proposal is under consideration of Govt. of India, New Delhi.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय कारगो एयरपोर्ट के लिए भिवानी को कंसीडर किया गया था या नहीं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिलावाईज नहीं बन सकता है। स्पीकर सर, यह बहुत ही खुशी की बात होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हरियाणा में किसी भी जिले को मिले तो यह स्टेट के लिए भी गौरव की बात होगी। स्पीकर सर, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पूरी दुनिया में एक ही टवीन एयरपोर्ट कन्सैप्ट है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट पहले ही है और कायदे के अनुसार उसके नजदीक ही दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है, उसकी पैराफेरी में ही यह बनना चाहिए ताकि दोनों में तालमेल आसानी से बैठ सके। हमारी कोशिश है कि उसी परिधि के अन्दर दूसरा एयरपोर्ट बनना चाहिए, उसके लिए हमें अपनी भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि हम ज्यादा उन्नति कर सकें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, करनाल में एक फ्लाईंग क्लब है जहां पर हमारे लड़के और लड़कियां पायलट बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। वहां पर एयर क्राफ्टस की कमी रहती है जिसकी वजह से हमारे हरियाणा के बच्चे दूसरी स्टेटस में या विदेशों में पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार वहां पर एयर क्राफ्ट परचेज करने के बारे में विचार करेगी ताकि हमारे बच्चे दूसरी जगहों पर ट्रेनिंग लेने के लिए न जाएं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार से पहले किसी भी सरकार ने ट्रेनिंग के लिए एयर क्राफ्ट परचेज नहीं किए थे लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया और दो नए सैसना एयर क्राफ्ट अमेरिका से खरीदे गए हैं तथा उनकी पेमैन्ट कर दी गई है। वे एयर क्राफ्ट सीप के थ्रू चल पड़े हैं और अगले एक महीने में आ जाएंगे। स्पीकर सर, यह जो नए एयर क्राफ्ट खरीदे हैं इनमें सारा ग्लास कॉकपिट होगा। अब हम अपने छात्र और छात्राओं को यहीं पर ट्रेनिंग दे सकेंगे।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले यह बात चर्चा में थी कि भिवानी जिले में कारगो इन्टरनैशनल एयरपोर्ट बनेगा। अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिला अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए जो-जो नार्मज होते हैं उनको पूरा करता है। अगर कहीं पर भी इन्टरनैशनल एयरपोर्ट बनाना हो तो उसके बनने वाले इन्टरनैशनल एयरपोर्ट की दूरी से दूसरे इन्टरनैशनल एयरपोर्ट की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर की होनी चाहिए। भिवानी जिला इस नार्म को भी पूरा करता है। वहां की जमीन रेतीली और बंजर होने की वजह से एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अगर वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दिल्ली से उसकी कनैक्टिविटी भी अच्छी हो सकती है। जैसा महेन्द्रा जी ने कहा है कि अगर इस बारे में विचार किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने बता दिया है लेकिन मैं भी इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहूंगा कि हमने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा है और अनुमति मांगी है कि हरियाणा सरकार यहां एक कारगो एयरपोर्ट बनाना चाहती है इसलिए इसकी अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी हमें इसके लिए अनुमति मिले हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यह नैचुरल बात है कि इसका लाभ तभी सबसे ज्यादा मिलेगा जब यह दिल्ली के नजदीक होगा। जहां पर भी हमें इसके लिए परमिशन मिलेगी चाहे वह भिवानी हो या चाहे करनाल हो, हम जरूर विचार करेंगे। असौदा जो बहादुरगढ़ के साथ है वहां हमने इसके लिए प्रपोज्ड किया है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी वहां एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप थी। अध्यक्ष महोदय, मै सदन की इंफोर्मेशन के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इस एयर स्ट्रिप को मेरे पिता जी ने ही ब्लास्ट किया था। दिल्ली के नजदीक होने के कारण ही इस जगह का चयन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि वहां पर एयर स्ट्रिप रह चुकी है इसलिए हम चाहते हैं कि हरियाणा को इस जगह का लाभ मिले। अब यह डिपैंड करता है कि हमारे को कहां के लिए अनुमति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा इस बारे में कम्पीटीशन है इसलिए हमने दिल्ली के नजदीक जगह चुनी थी क्योंकि अखबारों में आया था कि नोएडा में कारगो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अगर नोएडा में कारगो एयरपोर्ट बनाने की बात है तो हम दिल्ली के नजदीक ही जमीन देने के लिए प्रपोज्ड कर सकते थे ताकि यह नोएडा में न जाकर हमारे हरियाणा को मिल जाए।

तारांकित प्रश्न संख्या 614

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Up-gradation of P.H.C. to C.H.C. at Pundri

***610. Shri Dinesh Kaushik :** Will the minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade Primary Health Centre to Community Health Centre at Pundri, District Kaithal; and

(b) if so, up to what time it is likely to be up-graded ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समय सीमा नहीं दी जा सकती।

स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि पुंडरी की पी०एच०सी० को सी०एच०सी० में बदलने की सैद्धांतिक स्वीकृति सरकार जारी कर चुकी है लेकिन इसके लिए दूसरी कई चीजों की भी आवश्यकता होती है इसलिए इस समय इसके लिए समय सीमा यहां पर नहीं दी जा सकती।

प्रो० दिनेश कौशिक : स्पीकर सर, जैसे इन्होंने क्वैश्चन के जवाब में कह दिया कि time limit could not be given. जब सैद्धांतिक मंजूरी इसको दी जा चुकी है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से इसको सी०एच०सी० नहीं बनाया जा सकता ? वहां पर भवन भी है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है लेकिन उस शहर की 80 हजार की आबादी होने के बावजूद भी अभी तक वहां पर सी०एच०सी० की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है जबकि वहां पर 100 बैड का होस्पीटल डिजर्व करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह दस साल पुरानी मांग है। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में कोई न कोई समय सीमा जरूर निर्धारित की जाए।

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, वैसे तो अगले फाईनैंशियल ईयर में यह सी०एच०सी० बन जाएगी लेकिन इसके लिए नये भवन की भी आवश्यकता होगी, नए वार्ड भी चाहिए,एक्सरे रूम भी चाहिए, मैडीकल और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए क्वार्टर भी चाहिएं। इसका नक्शा मुख्य वास्तुकार से बनवाया जाता है और इसके लिए टैंडर भी कॉल किए जाते हैं। इसके बाद पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एंड आर०) वाले इसको बनाते हैं इसलिए समय सीमा देने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि दो महीने लगेंगे या चार महीने लगेंगे और कितना समय लग जाएगा ? लेकिन मैं इनको यह आश्वासन देना चाहती हूं कि इस साल में इनकी पी०एच०सी० सी०एच०सी० में बदल जाएगी क्योंकि उसके कई कारण हैं वहां पर आउटडोर पेशैंटस की संख्या भी ठीक है इसलिए हमें लगता है कि वहां की जनसंख्या को इसकी आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो ये महाशय सामने बैठे हुए हैं इन्होंने पी०एच०सी० को सी०एच०सी० में बदलने के लिए सब जगह स्वीकृति तो दे दी थी लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। इस पी०एच०सी० को सी०एच०सी० में बदलने के लिए भी 2004-05 में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी लेकिन एक कौड़ी भी इसके लिए इन्होंने नहीं दी। डेढ़ साल बाद लोगों ने इनकी सरकार को निकाल दिया। स्पीकर सर, इन्होंने माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र को एक कौड़ी भी नहीं दी। जब सरकार बदली तो हैल्थ मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि एक करोड़ रुपये से अधिक जो पैसा हैल्थ के लिए खर्च किया जाएगा तो उसमें से हम इसके लिए भी पैसा देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : इन्दौरा साहब, यह तो हकीकत है कि बहुत सारी चीजों में इन प्रिंसिपल तो दिया हुआ है लेकिन वास्तव में एक पैसा भी आबंटित नहीं हुआ है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनके नेता यहां से भाग गए हैं तो इनको बात सुननी पड़ेगी। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, क्वैश्चन परटेनिंग टू हैल्थ है इसलिए इस पर बात हो सकती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की एक कमेटी बनाइए और डॉ० इन्दौरा को उसमें बैठाइए। ये देखें कि क्या यह बात दुरुस्त है या नहीं कि वर्ष 2004-05 में कई स्कीमों में चौटाला जी ने बजट की सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकृति दे दी थी लेकिन एक पैसा भी बजट का आबंटित नहीं किया ? मैं फ्लोर ऑफ दि हाउस आपसे डिमांड करता हूं कि आप इस बात की जांच करवाइए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सरकार एक कन्टीनुअस प्रोसेस होती है जो चीजें अधूरी रह जाती हैं उनको पूरा करना अगली सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

Clubbing various offices of Social Welfare Department into one office

***661. Shri Tejendera Pal Singh Mann :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for clubbing various offices into one office and under one officer; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken in this regard ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, सोशल वैल्फेयर एक महत्वपूर्ण महकमा है इसका संबंध बहुत गरीबों में गरीब आदमी के साथ है। इसको किसी के मरने पर कम्पनसेशन देना होता है और किसी को बच्चे की शादी के लिए सहायता देनी होती है। एक अधिकारी कहीं बैठा है और दूसरा उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर बैठता है। गरीब आदमी जिसके पांव में जूती तक नहीं है, वह यदि एक जगह जाए और उसके सारे काम बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यह मेरा सुझाव भी है। वैसे भी सरकार की नीति और नीयत गरीब आदमी को इमदाद करने की है। तीनों चारों दफ्तर एक ही छत के नीचे होने चाहिए। इसमें बहुत सा पैसा जिन फंक्शनरीज को मिलता है वह उसका दुरुपयोग भी करते हैं इसलिए इस सारे महकमें का गठन करके एक छत के नीचे इसको बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि क्या सरकार आगे के लिए कुछ सोचेगी और सारे महकमें एक छत के नीचे लाकर गरीब आदमियों को राहत देने का काम करेगी ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि लगता है कि इन्होंने डिपार्टमैंट की वर्किंग पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। हमारे सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट में दो विंग बन गई हैं। एक तो वैल्फेयर ऑफ एस०सीज० बी०सीज० और दूसरा

[बहिन करतार देवी]

सोशल जस्टिस एंड इम्पौवरमैंट का विंग है। वह स्टाइपैंड और पैंशन वगैरह के वितरण का काम देखता है और जो हमारा सोशल वैल्फेयर का विंग वह केवल एस०सीज० और बी०सीज० के लोगों के वैलफेयर का काम देखता है। स्टेट लैवल पर काफी समय से दोनों विभागों का डायरैक्टर व कमिश्नर भी एक ही है और ऊपरले स्तर पर इसलिए एक ही है ताकि विभाजन होने के कारण रिसपौंसिबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत न हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जितने प्रावधान इस विभाग में हुए हैं उतने शायद किसी में नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 2004-05 में केवल 16.75 लाख रुपये का बजट में प्रावधान था और 2005-06 में 40 लाख का प्रोविजन किया गया था लेकिन बीच में मुख्य मंत्री जी ने इन्टरवीन करके 76 करोड़ का प्रावधान किया और अगले बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अभी पीछे इन्टरनैशनल वीमैंस डे मनाया गया था। इस बारे में मेरा कहना यह है कि अब जिन औरतों के पास सिर्फ लड़कियां हैं पैंशन के लिए उनकी आयु को 55 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है और उनकी पैंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। स्टाईफंड से लेकर एस०सी० और बी०सीज० की श्रेणियों का बैकलॉग पूरा करने के साथ ही सारी स्कीमों का दोबारा से अध्ययन करके उनके जो जनहित के प्रावधान थे, वे सभी किए गये हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार द्वारा बहुत प्रयास किये जा रहे हैं और बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन मेरा यही तो एक सुझाव है कि इन सारी चीजों को एक आफिस में इकट्ठे लाकर एक सीनियर अधिकारी को इनका इन्चार्ज लगा दिया जाए ताकि लोगों को जो राहत सरकार से मिलती है और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह की सरकार की आम जनता की मदद करने की जो नीति और नीयत है, उसमें कोई बाधा न पड़े। इसके लिए हम तो स्वयं भुगतभोगी हैं। अगर सरकार वाकई गरीब आदमियों की मदद करना चाहती है तो सरकार को मेरे सुझाव पर गौर करना चाहिए। उन अधिकारियों से हमको ही रास्ता नहीं मिलता तो आम आदमी क्या करेगा ? कई प्रकार के अधिकारी हैं उनके हाथ में उनकी हैसियत से काफी ज्यादा पैसा होता है।

Setting up of Industrial Units in the State

***631. Shri Gian Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state the detail of new industrial units set up in the State during the period from 1st April, 2005 to 31st December, 2006 ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) : Sir, during the period from 1-4-2005 to 31-12-2006, 2417 new industrial units with an investment of Rs. 2290 crore have been set up in the State.

श्री ज्ञान चन्द ओढ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन यूनिटस में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और सरकार को कितना फायदा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : ज्ञान चन्द जी, आपने प्रश्न तो यूनिट स्थापित करने के बारे में किया था।

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर इन यूनिट्स में दिए गए रोजगार के बारे में सूचना चाहते हैं तो मैं इनको और सदन को विस्तार से इस बारे में बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय,.....

1. राज्य में स्थापित बड़े तथा मध्यम औद्योगिक इकाईयों की संख्या 1966 में 162 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1290 है। इसके अतिरिक्त राज्य में 80,000 लघु औद्योगिक इकाईयां है। इन इकाईयों में तथा इनके विस्तार में किये गये पूंजीनिवेश को मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजीनिवेश हुआ है।

2. वर्तमान सरकार की अवधि में 19000 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से 40,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करते हुए निम्नलिखित औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं :—

   (i) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा पी०एक्स०/पी0टी0ए0 परियोजना में 5200 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है। इस परियोजना में सितम्बर, 2006 से उत्पादन आरम्भ हो चुका है।

   (ii) पानीपत में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन ने रिफाईनरी के विस्तार में 4300 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया है, जिसमें उत्पादन जून, 2006 से आरम्भ हो चुका है।

   (iii) राज्य में 108 औद्योगिक झापन क्रियान्वित करने में 1027.58 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हुआ है।

   (iv) 63 बड़ी एवं मध्यम इकाईयों और 2354 लघु इकाईयों में 2290 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है।

   (v) 1499.88 करोड़ रुपये का सीधा विदेशी पूंजीनिवेश किया गया है।

   (vi) मारूति उद्योग एवं इसकी सहायक इकाईयों के विस्तार कार्यक्रम में 2000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है।

   (vii) 1008 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में किया गया है। इन विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 2005 की उद्योग नीति के अनुसार उद्योग का दर्जा दिया गया है।

   (viii) राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु विभिन्न निर्माताओं द्वारा 2935 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है।

3. 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के पूंजीनिवेश से निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं :—

   (i) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की नाफ्था क्रेकर परियोजना 12000 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से।

   (ii) जिन 12 कम्पनियों को 10-10 एकड़ के प्लाट मानेसर में तथा 2 कम्पनियों को 25-25 एकड़ के प्लाट राई में अलाट किए गए हैं । उन द्वारा सूचना प्रौद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 4106 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश होने का अनुमान है।

[श्री लक्ष्मन दास अरोड़ा]

(iii) जिन 71 प्रस्टीजियस इकाईयों को प्लाट अलाट किए गए हैं, उन के द्वारा 4000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश करने का अनुमान है।

(iv) मारुति उद्योग, हीरो होण्डा, होण्डा मोटर्स एवं मारुति की अनेकों सहायक इकाईयों के विस्तार में 10,000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश होने का अनुमान है।

(v) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जिन 1425 उद्यमियों को प्लाट अलॉट किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 4400 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश होने की संभावना है।

(vi) भारत सरकार को 390 उद्यमियों द्वारा हरियाणा में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं इन ज्ञापनों से 5995 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश होने की संभावना है।

(vii) जिन 98 अप्रवासी भारतीयों को प्लाट अलॉट किए गए हैं उनके द्वारा 421 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश करने की संभावना है।

(viii) 10,000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में किया गया है। इन परियोनाओं को वर्ष 2005 की उद्योग नीति के अनुसार उद्योग का दर्जा दिया गया है।

4. माननीय मुख्य मंत्री महोदय की हाल की यूरोप यात्रा के दौरान यूरोप की विख्यात कम्पनियों द्वारा 12000 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश करने का आश्वासन मिला है। डच हरियाणा फाऊण्डेशन के साथ 11000 करोड़ रुपये की लागत से यूरोपीयन टैक्नोलोजी पार्क स्थापित करने हेतु एम०ओ०यू० भी किया गया है।

5. राज्य में अब तक 8200 करोड़ रुपये विदेशी पूंजीनिवेश किया गया है। जिसमें से 1499.88 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजीनिवेश वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किया गया है।

6. राज्य से वर्ष 2005-06 में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का सामान का निर्यात किया गया।

7. राज्य सरकार ने सरकार का विभिन्न विभागों से समयबद्ध स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने हेतु हरियाणा उद्योग संवर्धन अधिनियम, 2005 लागू किया है। इसके साथ ही स्वयं प्रमाणन एवं आऊट सोर्सिंग योजना भी लागू की गई है।

8. राज्य में निर्यातोन्मुख इकाईयों की बड़ी संख्या में स्थापना करने हेतु राज्य सरकार ने हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बनाया है।

9. राज्य में 1,75,000 करोड़ के पूंजीनिवेश से 72 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो कि देश में अधिकतम हैं, इनमें से 49 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देश में सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना रिलायंस इण्डस्ट्री, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से गुड़गांव एवं झज्जर जिला में कर रही है।

10. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पब्लिक एवं प्राईवेट सांझेदारी नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित मैगा परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(i) रिलायंस इण्डस्ट्री द्वारा जिला झज्जर तथा गुडगांव जिले में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश से बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना (25000 एकड़ भूमि पर)।

(ii) डी०एल०एफ० यूनिवर्सल लि० द्वारा अम्बाला में 1950 करोड़ रुपये की लागत से बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना (2500 एकड़ भूमि पर)।

(iii) डी०एल०एफ० यूनिवर्सल लि० द्वारा गुड़गांव में 26,000 करोड़ रुपये की लागत से बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना (20000 एकड़ भूमि पर)।

(iv) रायपुर रानी में 2000 करोड़ रुपये की लागत से नैनो सिटी की स्थापना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Kundli-Manesar-Palwal Express Highway

***639. Shri Ishwar Singh Plaka :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the details of work done on Kundli-Manesar-Palwal Express Highway togetherwith the amount spent thereon during the period from 1st April, 2005 to till date; and

(b) the time by which the work on the above said Highway is likely to be completed ?

उद्योग मंत्री, (श्री लछमण दास अरोड़ा) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे पर किये गये कार्य का ब्यौरा और खर्च की गई राशि निम्न है :—

1. मै० के०एम०पी० एक्सप्रैस लिमिटिड को एक्सप्रैस-वे के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है और हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं संरचना निगम ने इस कम्पनी से दिनांक 31-1-2006 को एक समझौता भी किया है।

2. निर्माण कम्पनी ने 8-1-2007 को इस प्रोजैक्ट पर होने वाले खर्चे का वित्तीय प्रबन्ध कर लिया है।

[श्री लछमन दास अरोड़ा]

3. राईट आफ वे के लिए सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव व फरीदाबाद जिले में कुल 3331 एकड़ भूमि अधिकृत की गई है और इसका कब्जा निर्माण कम्पनी को दे दिया गया है।

4. वन एवं पर्यावरण मंन्त्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है।

5. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं संरचना निगम ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग हरियाणा को स्वीकृति देने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने यह मामला भारत सरकार के चण्डीगढ़ स्थित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया है। इस योजना के लिए वन विभाग की स्वीकृति जल्दी ही मिल जाएगी।

6. एक्सप्रैस वे के डिजाईन, इंजीनियरिंग, निर्माण व विकास के निरीक्षण के लिए एक स्वतन्त्र सलाहाकार की नियुक्ति की गई है।

7. निर्माण कम्पनी ने भूमि सम्बन्धित होने वाला कार्य शुरु कर दिया है और कार्य प्रगति पर है। निर्माण कम्पनी ने बताया है कि इस एक्सप्रैस वे के निर्माण कार्य के लिए उन द्वारा 28-2-2007 तक 148.88 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

8. उपरोक्त परियोजना पर 1-4-2005 से अब तक 588.00 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ख) निर्माण समझौते के अनुसार कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस वे परियोजना का निर्माण 30-7-2009 तक होने की सम्भावना है।

Problems Facing by the Green Field Colony, Mewla Maharajpur

***604. Shri Mahender Partap Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is a green field colony approved by the Government on the mountain of Mewla Maharajpur (Faridabad);

(b) whether it is also a fact that plot holders in the said colony are facing a problem in constructing their houses on account of obstruction caused by Police and Mining Department; and

(c) if so, what steps are being taken by the Government to solve the problem of such plot holders ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(ए) हां श्रीमान जी।

(बी,सी) इस कॉलोनी में भवनों का निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 6-5-2002, आई०ए० नं० 1785, रिट पटीशन (सिविल) नं०-4677 ऑफ 1985 से प्रभावित है। यह आदेश खनन प्रक्रिया, जिसमें आकस्मिक खनन प्रक्रिया भी शामिल है, को निषेध करता है, जोकि भवनों की नींव एवम् बेसमैंट की खुदाई से पैदा होती है।

Minimum Wages to contract Labourers

*635. **Sh. Ramesh Kaushik :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the contract labourers are getting minimum wages or not in the State; and

(b) is there any check on the factory owners in respect of extra working hour of labourers ?

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हां, श्रीमान

(ख) हां, श्री मान

Milk Plant at Bhiwani

*648. **Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that Milk Plant at Bhiwani is not functioning in full swing; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken for running the said Milk Plant in full functioning ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : महोदय,

(क) दुग्ध संयंत्र, भिवानी 1986 में बन्द कर दिया गया था। इस समय वहां एक शीतकरण केन्द्र चल रहा है।

(ख) शीतकरण केन्द्र पूरी क्षमता से चल रहा है।

Arts and Science Colleges and Schools Convert into Vocational Institutions

*667. **Sh. S.S. Surjewala :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to convery the Arts and Science Schools and Colleges into Vocational Institutes imparting education in various disciplines, such as Mass Communication, Bio-technology, Food Processing, Business Administration (BBA/MBA), Bio-informatics, Neno Technology, Computer Application (BCA/MCA), Dressing Designing, Interior Decoration etc., if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान् जी।

Repair/Reconstruction of Old Civil Hospital, Ambala Cantt.

*673. **Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any proposal is under consideration of the Government to re-construct the building of Old Civil Hospital of Ambala Cantt. Which is in defected/deteriorated condition at present ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : जी नहीं, श्रीमान, यद्यपि 25 बिस्तरीय अतिरिक्त खण्ड का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Widen/Repair of Badli-Rohad Road

*678. **Shri Naresh Kumar Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen/repair of Badli-Rohad Road; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be completed ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यह कार्य मार्च, 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

Land released by H.S.I.D.C.

*653. **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any land has been released by the H.S.I.D.C. after starting the process/ issuing of notification for acquisition of land in the State during the period from 1st April, 2005 to 31st December, 2006; if so, what are the reasons thereof ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : श्री मान् जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा है।

नियम 45 (1) के अधीन संसद की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर

क्र० सं०	औद्योगिक सम्पदाओं का नाम	(एकड़/कनाल/ मरला) में क्षेत्र	सैक्शन 4 की तिथि	सैक्शन 6 की तिथि	ए.के.एम.में क्षेत्र	5ए के अन्तर्गत छोड़ा गया क्षेत्र	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना के पश्चात् छोड़ा गया क्षेत्र (एकड़-कनाल-मरला) में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सैक्टर 34-35 गुड़गांव में औद्योगिक सम्पदा के लिए भूमि का अभिग्रहण	389-4-17.79	15.11.02	12.11.03	341-1-05	48-3-17.29	1) हाई पावरड कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 42-1-11 भूमि को पूर्णतया तथा सेवाओं की इन्टीग्रेशन के लिए लगभग 22 एकड़ सशर्त रिलीज करने का निर्णय लिया है। 2) इसके पहले की समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लगभग 8 एकड़ भूमि रिलीज करने का निर्णय लिया है।	दिनांक 18-11-05 को अवार्ड घोषित किया गया।
2.	विशेष आर्थिक जोन, गुड़गांव	1779-3-4.25	29.1.03	28.1.04	1715-3-5.5	63-7-18.75	हाई पावरड कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लगभग 114 एकड़ भूमि रिलीज करने का निर्णय लिया है।	दिनांक 27-1-06 को अवार्ड घोषित किया गया।
3.	उद्योग विहार चरण-4 गुड़गांव में बची हुई पाकिटस का अभिग्रहण	15-4-13	13.5.02	8.05.03	15-4-13	शून्य	मन्त्री स्तर की समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लगभग 3-4-8 भूमि रिलीज करने का निर्णय लिया है।	दिनांक 3-2-04 को अवार्ड घोषित किया गया।
4	आई०एम०टी०मानेसर ग्राम लखनौला नाहरपुर, मानेसर तहसील एवं जिला गुड़गांव में आवासीय मनोरंजन तथा अन्य जनसाधारण उपयोगिताओं के लिए भूमि का अभिग्रहण	912-0-7	27.8.04	25.8.05	688-3-12	223-4-15	शून्य	दिनांक 23-12-05 को धारा 7 के अन्तर्गत आदेश जारी किये।

क्र० सं०	औद्योगिक सम्पदाओं का नाम	(एकड़/कनाल/ मरला) में क्षेत्र	सैक्शन 4 की तिथि	सैक्शन 6 की तिथि	ए.के.एम.में क्षेत्र	5ए के अन्तर्गत छोड़ा गया क्षेत्र	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना के पश्चात् छोड़ा गया क्षेत्र (एकड़-कनाल-मरला) में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	तहसील एवं जिला गुड़गांव के मानेसर, खोह, कासन गांवों में औद्योगिक, आवसीय मनोरंजनात्मक एवं अन्य जनसाधारण उपयोगिताओं के लिए एक सम्पूर्ण कम्पलैक्स के लिए योजनाबद्ध एवं विकसित किया जाने वाला आई०एम०टी० मानेसर की स्थापना करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना	163-3-15	25-11-05	24.11.06	162-3-14	1-0-1	शून्य	दिनांक 19.1.07 को धारा 7के अन्तर्गत आदेश जारी किया।
6	आई०एम०टी०मानेसर, चरण-5, जिला गुड़गांव के लिए भूमि अधिग्रहण	956-5-18	17.09.04	27.10.04	956-5-16	शून्य	6-4-5 (भूमि गांव की आबादी से सटी आवासीय घरों के अन्तर्गत है)	दिनांक 9-3-06 को अवार्ड घोषित किया
	सोनीपत							
7	तहसील एवं जिला सोनीपत की गांव नंगलकलां, अटरेना, सेरसा की राजस्व सम्पदा में श्रमिकों के आवास के लिए आवासीय सैक्टर 59 एवं 60 के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण	885-0-3	6-10-05	4-10-06	824-5-0	60-3-3	शून्य	दिनांक 4-1-07 को धारा 7 के अन्तर्गत आदेश जारी किए
8	तहसील एवं जिला सोनीपत में गांव रसोई, बाथ, मालिक, पीतमपुरा गांवों की राजस्व सम्पदाओं में सैक्टर-39	487-7-4	30.06.05	5.706	380-2-16	107-4-8	शून्य	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।

	(जनसाधारण और जनसाधारण) को विकसित करने के लिए भूमि का अभिग्रहण							
9	तहसील एवं जिला सोनीपत के गांव कुण्डली एवं खेरसा में औद्योगिक सैक्टर 53, 54, 55 तथा 56 के विकास के लिए भूमि अभिग्रहण **पानीपत (पैट्रोकैमिकल हब)**	714-1-8	21-12-05	29-12-06	636-2-8	77-7-0	शून्य	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
10	गांव बेगमपुर तहसील घरौंडा जिला करनाल में पैट्रोकैमिकल हब विकसित करने के लिए भूमि का अभिग्रहण **रोहतक**	108-3-3	25.01.06	7.11.06	103-2-16	5-0-7	शून्य	दिनांक 14-12-06 को धारा 7 के अन्तर्गत आदेश जारी किया जाए
11	गांव कुटाना, तहसील एंव जिला रोहतक में औद्योगिक सम्पदा रोहतक के लिए भूमि अभिग्रहण	159-0-4	25.01.06	5.10.06	152-4-8	6-3-16	शून्य	5-2-07 को अवार्ड घोषित किया गया।
12	खेड़ी साध तथा बलियाना तहसील एवं जिला रोहतक में आई०एम०टी० रोहतक के लिए भूमि का अभिग्रहण	878-5-6	8.8.06	11.1.07	871-4-11	7-0-15	शून्य	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।
	साहा							
13	जी०सी०साहा, चरण-2, जिला अम्बाला के लिए भूमि का अभिग्रहण	31-3-17	20.06.05	28.08.06	14-0-14	17-3-3	शून्य	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।
14	जी०सी०साहा, चरण 2, जिला अम्बाला के लिए भूमि का अभिग्रहण	276-4-1	23.12.05	29.12.06	274-4-18	1-7-5	शून्य	धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई।

Widen Road from Hansi to Jind

***682. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the State Highway from Hansi to Jind ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Pontoon Bridge on Nagli Ghat at Yamuna River

***674. Shri Rakesh Kumboj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a pontoon bridge on Nagli Ghat at Yamuna River in District Karnal; if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी, क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है, अतः कोई सीमा नहीं दी जा सकती।

Development of Industrial Township

***578. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Minister for Industries be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government of Haryana to develop Industrial Model Township at Gohana and Kharkhoda, District Sonipat; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) हां, श्रीमान् जी। खरखौदा, जिला सोनीपत में औद्योगिक माडल नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रस्ताव है। परन्तु गोहाना, जिला सोनीपत में औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत खरखौदा, जिला सोनीपत में औद्योगिक माडल नगर क्षेत्र के विकास हेतु भूमि चयन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण तथा अधिसूचना के प्रारुप की तैयारी कार्य प्रगति पर है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Waving Off Outstanding Electricity Bills

50. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise details of waved off amount of the outstanding electricity bills of domestic as well as agriculture consumers benefited from the waving scheme ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान जी,

ग्रामीण घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में माफी स्कीम के अन्तर्गत माफ की गई बकाया राशि का जिलाबद्ध विवरण निम्न अनुसार है :--

राशि करोड़ों में

क्र० सं०	जिले का नाम	श्रेणी		योग
		ग्रामीण घरेलू	कृषि	
1.	अम्बाला	3.09	2.77	5.86
2.	पंचकूला	1.51	0.16	1.67
3.	यमुनानगर	10.93	6.41	17.34
4.	कुरुक्षेत्र	11.68	11.51	23.19
5.	कैथल	73.77	36.42	110.19
6.	करनाल	25.25	36.90	62.15
7.	पानीपत	13.48	13.24	26.72
8.	सोनीपत	27.38	5.49	32.87
9.	जीन्द	153.59	64.24	217.83
10.	रोहतक	91.07	3.32	94.39
11.	झज्जर	36.40	5.32	41.73
12.	फरीदाबाद	22.73	3.63	26.36
13.	गुड़गांव	23.08	8.68	31.76
14.	मेवात	8.43	0.60	9.02
15.	महेन्द्रगढ़	47.38	30.00	77.78
16.	रेवाड़ी	11.96	4.61	16.57
17.	भिवानी	166.96	119.42	286.38
18.	हिसार	49.68	5.30	54.98
19.	फतेहाबाद	40.96	6.74	47.70
20.	सिरसा	7.35	6.68	14.03
योग	821.77	376.34	1198.11	

Registered Gift of Agriculture Land

55. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Revenue be pleased to state the details of gift deeds of Agricultural land registered alongwith the stamp duty realized district-wise and year-wise in the State by the Government since April, 2001 till date ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, वांछित सूचना अनुबन्ध 'क' पर रखी है।

Amount spent on renovation of Haryana Civil Secretariat

67. Dr. Sushil Indora : Will the Chief Minister be pleased to state the details of amount spent by the State Government on the repair/renovation of Haryana Civil Secretariat and the residences of the Ministers in Chadigarh and Panchkula during the period from 1st April, 2005 to 31st December, 2006 ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : राज्य सरकार द्वारा 1-4-2005 से 31-12-2006 तक की अवधि के दौरान हरियाणा सिविल सचिवालय में 297.76 लाख रुपये तथा चण्डीगढ़ और पंचकूला में मंत्रियों के निवास स्थानों की मरम्मत/नवीकरण पर 366.64 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

Permission for Bio-Products in the State

56. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the State Government has permitted the Department of Agriculture for the sale of Bio-Products in the State during the last three years since 2004-2005 till date;

(b) if so, under which Act/Rule such permission was granted;

(c) whether any Lab. facility for the testing of their quality is available in the State; and

(d) whether any sample of Bio-Products has been taken by the quality control wing of the Agriculture Department during the period referred to in part (a) above ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) :

(क) यद्यपि कृषि विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत थोड़ी मात्रा में जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशी एवं जैव कारक किसानों को उपलब्ध करवाये जाते हैं, परन्तु विभाग निजी कम्पनियों द्वारा विपणन किये जाने वाले अन्य बायो-उत्पादों को व्यवस्थित करता है।

(ख) चूंकि जैविक उर्वरक एवं आरगैनिक उर्वरक के अतिरिक्त बायो-उत्पादों की बिक्री, मूल्य व गुणवत्ता उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 अथवा किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते, अतः राज्य सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा विभाग को इन बायो-उत्पादों की बिक्री व्यवस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। ऐसे बायो-उत्पादों के 14 नमूने लिये गये हैं जो उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत नहीं आते।

Irrigated Area under Bhakra Command Area and West Yamuna Command Area in the State

71. Dr. Sita Ram : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the details of area under Bhakra Command Area and West Yamuna Command Area alongwith the details of canals by which such area are irrigated ?

अनुबन्ध 'क'

रजिस्टर्ड कृषि भूमि के उपहार विलेखों तथा सरकार द्वारा राज्य में अप्रैल, 2001 से आज तक जिलावार तथा वर्षवार वसूल की गई स्टाम्प ड्यूटी का ब्यौरा

क्र०	जिला	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006 till date		आज तक	आज तक
		उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों की संख्या	स्टाम्प ड्यूटी	उपहार विलेखों कुल जोड़	स्टाम्प ड्यूटी का कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	पंचकूला	129	1173596	146	857093	123	1924490	241	3166705	261	4764333	178	6933803	1078	18820019
2.	करनाल	210	2871562	316	4474568	498	7914604	741	8913985	267	3937575	275	3578980	2307	31691284
3.	कुरुक्षेत्र	356	3410627	397	3263069	268	3700864	602	5989431	254	4399290	247	4429745	2124	25193026
4.	नारनौल	189	1230460	222	1862152	256	2345701	425	2873870	158	1231430	332	3217740	1560	12761353
5.	फतेहाबाद	280	2883344	318	3763412	425	5944107	450	3424613	83	1078713	248	8436362	1804	25430541
6.	हिसार	203	1404785	230	1523620	453	4177717	567	7180157	283	2863861	235	3541230	1971	20691370
7.	रोहतक	227	1841392	438	4930581	658	7546969	1022	7638707	552	4351371	499	5970320	3398	32879380
8.	सिरसा	215	1177685	626	4119194	710	3309903	1042	7028755	155	1684331	197	1782847	2945	19102715
9.	रिवाड़ी	148	1702844	326	5335291	398	5510833	628	6190908	122	2429775	221	4727200	1843	25796851
10.	यमुनानगर	196	1820265	239	4019902	412	4899704	836	8873191	463	6550130	269	7238474	2415	33399666
11.	जीन्द	178	2980335	296	3326875	353	3659835	547	5241055	331	3265288	242	3006501	1947	21481859
12.	झज्जर	243	924207	157	1165766	222	1497071	237	1202721	185	2000247	197	2994855	1241	9784867
13.	मेवात	96	1251917	82	713658	100	804355	158	654712	157	1110680	145	1759940	738	6285262
14.	गुड़गांवा	80	1460047	93	2411012	82	1289401	154	3119083	201	5124618	209	7949585	819	21353746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	भिवानी	538	9184197	461	5183763	564	7880202	960	21985555	326	2563664	576	4250126	3425	51047497
16.	सोनीपत	119	297389	207	1788114	190	2138024	371	1029283	364	919082	254	989755	1605	7161647
17.	पानीपत	139	974645	178	1457734	310	3082978	273	1751906	47	456210	79	1478960	1026	9212423
18.	अम्बाला	252	2446665	250	3340260	338	6496328	399	4521837	413	4921562	252	4011281	1904	25737933
19.	कैथल	230	2037735	229	1961648	336	4044881	463	5320298	283	3784235	162	1700753	1893	18849550
20.	फरीदाबाद	81	539190	41	562909	64	1270557	173	3500109	94	1232029	82	1950845	535	9065839
	कुल	4089	41612886	5252	55050611	6760	79336514	10289	106606891	4997	59278424	4839	79949282	36276	425846608

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : भाखड़ा कमांड और पश्चिमी यमुना कमांड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित है—

1. भाखड़ा कमांड -- 12,53,000 हैक्टेयर
2. पश्चिमी यमुना कमांड -- 15,97,000 हैक्टेयर

(इसमें लिफ्ट कैनाल तथा गुड़गांव/आगरा कैनाल कमाण्ड भी सम्मिलित है)

मुख्य नहरों की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

(i) भाखड़ा कमाण्ड की नहरें :--

क्रम सं०	चैनल का नाम	पूर्ण जल आपूर्ति क्यूसिक्स में
1	2	3
1.	नरवाना ब्रांच	4022
2.	बी एम एल-बरवाला लिंक	1725
3.	बरवाला ब्रांच	1460
4.	सिरसा ब्रांच (आर०डी० 88000 पर)	2750
5.	बालसमंद सब ब्रांच	660
6.	भाखड़ा मेन ब्रांच	4077
7.	फतेहाबाद ब्रांच	2025
8.	सुरबरा डिस्ट्री०	43.92
9.	कोथकलां डिस्ट्री०	30.11
10.	नारा डिस्ट्री०	48.25
11.	सोठा डिस्ट्री०	11.60
12.	बधवार डिस्ट्री०	64.30
13.	पनीहारी डिस्ट्री०	42.00
14.	डाटा डिस्ट्री०	24.00
15.	खरखरी डिस्ट्री०	42.86
16.	राना डिस्ट्री०	258.00
17.	हिसार मेजर डिस्ट्री०	35.00
18.	भाखड़ा सिवानी लिंक	300.00
19.	देवा डिस्ट्री०	166.00
20.	शुदकान डिस्ट्री०	372.00
21.	तितराम डिस्ट्री०	32.00

1	2	3
22.	धमतान डिस्ट्री०	300.00
23.	सिरसा समानान्तर डिस्ट्री०	33.00
24.	धारसूई डिस्ट्री०	31.25
25.	रतिया ब्रांच	630.00
26.	सग्घर डिस्ट्री०	32.00
27.	रतनगढ़ डिस्ट्री०	51.27
28.	बादलगढ़ डिस्ट्री०	33.00
29.	समेरखेड़ा डिस्ट्री०	381.00
30.	कलुआना डिस्ट्री०	262.00
31.	केवल डिस्ट्री०	42.00
32.	मुसा लिंक	15.00
33.	कालुआना लिंक चैनल	28.25
34.	सिद्धमुख फीडर	266.00
35.	सिथरी डिस्ट्री०	96.00
36.	डबवाली डिस्ट्री०	147.00
37.	मौजगढ़ डिस्ट्री०	39.00
38.	जंडवाला डिस्ट्री०	40.00
39.	धौंटाला डिस्ट्री०	57.00
40.	तैजाखेड़ा डिस्ट्री०	57.00
41.	लोहगढ़ डिस्ट्री०	16.00
42.	रोड़ी ब्रांच	640.00
43.	बोहा डुडल लिंक	212.00
44.	जहांगीर डिस्ट्री०	42.00
45.	फागू डिस्ट्री०	27.00
46.	सिधमुख फीडर	266.00
47.	आदमपुर डिस्ट्री०	72.00
48.	गिगोरानी डिस्ट्री०	50.00
49.	शेरांवाली डिस्ट्री०	200.00
50.	बिगर डिस्ट्री०	17.00
51.	सिरसा मेजर डिस्ट्री०	225.17
52.	धमतान लिंक चैनल	39.15
53.	धनोरी फीडर	125.00

1	2	3
54.	पिरथला डिस्ट्री०	78.00
55.	सिमैन डिस्ट्री०	53.00
56.	फतेहाबाद डिस्ट्री०	229.00
57.	पाबरा लिंक चैनल	131.00
58.	गोरखपुर डिस्ट्री०	54.00
59.	दोहमान डिस्ट्री०	26.00
60.	कजूरी डिस्ट्री०	39.00
61.	न्यू दोहमान लिंक चैनल	19.50
62.	मोहम्मदपुर डिस्ट्री०	21.00
63.	नोहर फीडर	226.00
(ii)	**पश्चिमी यमुना कमाण्ड की नहरें :--**	
1.	डब्ल्यू० जे०सी० लिंक चैनल	25,000
2.	मेन लाईन अपर	16,000
3.	मेन लाईन लोअर	20,000
4.	डब्ल्यू० जे०सी० मेन ब्रांच	11,000
5	गुड़गाँवा फीडर	2242,
6.	गुड़गाँवा कैनाल	1960
7.	डिच चैनल	99.0
8.	1-आर डिस्ट्री०	27.0
9.	2-आर डिस्ट्री०	55.0
10.	जेघरी डिस्ट्री०	112.0
11.	जूण्डला डिस्ट्री०	180.0
12.	नरदक डिस्ट्री०	583.9
13.	चौटांग फीडर	486
14.	चौटांग डिस्ट्री०	134.5
15.	रम्बा डिस्ट्री०	109.35
16.	राक्षी डिस्ट्री०	89.25
17.	धरथाल डिस्ट्री०	148.53
18.	गोली डिस्ट्री०	76.24
19.	खेड़ी डिस्ट्री०	19.78
20.	बुढ़ाखेड़ा डिस्ट्री०	18.98
21.	आगमैन्टेशन कैनाल	4500

1	2	3
22.	बजीदा डिस्ट्री०	213
23.	पैरलल दिल्ली ब्रांच	5545
24.	गोहाना डिस्ट्री०	481
25.	इसराना डिस्ट्री०	188.00
26.	चमराड़ा चैनल	19.88
27.	नारायणा डिस्ट्री०	49.50
28.	हुलाना डिस्ट्री०	163.44
29.	हुलाना माईनर	9.17
30.	दिल्ली ब्रांच	1783
31.	समालखा डिस्ट्री०	54
32.	1-एल समालखा डिस्ट्री०	43
33.	गनोर डिस्ट्री०	26.50
34.	राजपुरा डिस्ट्री०	172.34
35.	सरदाना डिस्ट्री०	41.32
36.	जुंआ डिस्ट्री०	129.50
37.	सोनीपत डिस्ट्री०	35.57
38.	पाई डिस्ट्री०	204.65
39.	हरसाना डिस्ट्री०	36.88
40.	बी०डब्ल्यू०एस० चैनल	35.0
41.	जी०डब्ल्यू०एस० चैनल	135.0
42.	नलगीमाल डिस्ट्री०	37.37
43.	नाहरी डिस्ट्री०	11.50
44.	बवाना डिस्ट्री०	131
45.	दिल्ली सब ब्रांच	112.9
46.	छांयसा डिस्ट्री०	514
47.	रामपूर डिस्ट्री०	615
48.	सिकरी डिस्ट्री०	168
49.	सिकरोना डिस्ट्री०	329
50.	हरचंदपूर डिस्ट्री०	20
51.	धतीर डिस्ट्री०	636
52.	उटावर डिस्ट्री०	850
53.	मंडकोला डिस्ट्री०	498
54.	पुण्डरी डिस्ट्री०	417

1	2	3
55.	मलआली डिस्ट्री०	303
56.	गंगोला डिस्ट्री०	282
57.	नूंह सब ब्रांच	210
58.	इन्द्री डिस्ट्री०	562
59.	नूंह डिस्ट्री०	211
60.	उलेटा डिस्ट्री०	303
61.	उज्जीना डिस्ट्री०	988
62.	कलंजर डिस्ट्री०	207
63.	एफ०पी० के० झिरका डिस्ट्री०	742
64.	बनारसी डिस्ट्री०	148
65.	राजस्थान लिंक	1037
66.	हाँसी ब्रांच	7000
67.	बुटाना ब्रांच	3622
68.	जींद डिस्ट्री० नं० 3	337
69.	जींद डिस्ट्री० नं० 1	58.70
70.	जोशी डिस्ट्री०	22.00
71.	सिवाना मल डिस्ट्री०	21.95
72.	सुंदर सब ब्रांच	2611
73.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 4	87.80
74.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 5	60.00
75.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 6	37.50
76.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 6ए	29.00
77.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 7	31.15
78.	जीन्द डिस्ट्री० नं० 8	12.76
79.	मुआना डिस्ट्री०	69.15
80.	मसुदपुर डिस्ट्री०	80.00
81.	नारनौंद डिस्ट्री०	35.00
82.	हिसार मेजर डिस्ट्री०	300.00
83.	पेटवाड डिस्ट्री०	336.00
84.	लोहारू फीडर	1379
85.	लोहारू कैनाल	1189
86.	बधवाना डिस्ट्री०	176
87.	किटलाना डिस्ट्री०	105

1	2	3
88.	अटेला डिस्ट्री०	36
89.	धुधीवाला डिस्ट्री०	42.50
90.	कुराल डिस्ट्री०	78.50
91.	पिचोपा डिस्ट्री०	18.50
92.	रिहरोदी डिस्ट्री०	32.25
93.	गोकल डिस्ट्री०	86.76
94.	लाढ़ावास डिस्ट्री०	171
95.	सोरा डिस्ट्री०	205.25
96.	झूपा डिस्ट्री०	128.25
97.	दमकोरा डिस्ट्री०	73
98.	लोहारू डिस्ट्री०	72
99.	पाटूवास डिस्ट्री०	124
100.	जखाला डिस्ट्री०	37
101.	जे०एल०एन०-फीडर	3664
102.	रतनथल डिस्ट्री०	65.95
103.	जे०एल०एन०-रतनथल लिंक चैनल	156.40
104.	पटौदी डिस्ट्री०	94.85
105.	पाल्हावास डिस्ट्री०	59.70
106.	झज्जर डिस्ट्री०	218
107.	एस्केप चैनल	385
108.	साल्हावास लिफट चैनल	166
109.	महेन्द्रगढ़ कैनाल	1590
110.	सतनाली फीडर	292
111.	माधोगढ़ ब्रांच	149
112.	माधोगढ़ डिस्ट्री०	40.60
113.	उलांट डिस्ट्री०	81
114.	चिरया डिस्ट्री०	66
115.	जाइवा डिस्ट्री०	31.50
116.	बास डिस्ट्री०	14.85
117.	रामगढ़ डिस्ट्री०	23.50
118.	रामपुरी डिस्ट्री०	45
119.	खेड़ी डिस्ट्री०	31
120.	बसी डिस्ट्री०	72

1	2	3
121.	महेन्द्रगढ़ डिस्ट्री०	114
122.	नारनौल ब्रांच	773
123.	नांगल डिस्ट्री०	75.50
124.	भोजवास डिस्ट्री०	46.50
125.	रामबास डिस्ट्री०	33.50
126.	रता डिस्ट्री०	30.50
127.	मोहम्मदपुर डिस्ट्री०	37
128.	नोलपुर डिस्ट्री०	177
129.	नारनौल डिस्ट्री०	234.25
130.	दोचाना डिस्ट्री०	74.50
131.	हसनपुर डिस्ट्री०	64.50
132.	शाहबाजपुर डिस्ट्री०	81.25
133.	जखाला डिस्ट्री०	37
134.	जे०एल०एन० कैनाल	927
135.	शादीपूर डिस्ट्री०	20.50
136.	सुमाखेड़ा डिस्ट्री०	39
137.	भुरथल डिस्ट्री०	40
138.	नया गांव डिस्ट्री०	38.75
139.	अटेली डिस्ट्री०	311
140.	दिवाना डिस्ट्री०	273.50
141.	बालावास डिस्ट्री०	67.40
142.	लाडूवास डिस्ट्री०	38.50
143.	जीतपूर डिस्ट्री०	29.30
144.	निखरी डिस्ट्री०	27.90
145.	रलियावास डिस्ट्री०	27.53
146.	रजिका डिस्ट्री०	43
147.	जलालपुर डिस्ट्री०	23.50
148.	बावल डिस्ट्री०	29
149.	सांजरवास डिस्ट्री०	48.25
150.	धरानपूरा डिस्ट्री०	66.50
151.	तनकरी डिस्ट्री०	43.20
152.	निगाना फीडर	100
153.	निगाना कैनाल	25

1	2	3
154.	निगाना सिवानी लिंक	30
155.	बालावास डिस्ट्री०	67.40
156.	जूई फीडर	755
157.	बहल डिस्ट्री०	62.50
158.	जूई कैनाल	357
159.	सुन्दर सोरखी लिंग	31.55
160.	सुन्दर डिस्ट्री०	413
161.	मिथाथल फीडर	330
162.	सिवानी फीडर	311
163.	गरानपूरा डिस्ट्री०	80.92
164.	सिवानी कैनाल	425
165.	ढाणी मिरान डिस्ट्री०	28.50
166.	गदवा डिस्ट्री०	28.50
167.	शेरपुरा डिस्ट्री०	36.50
168.	मोतीपुरा डिस्ट्री०	103.50
169.	गुढ़ा डिस्ट्री०	25.90
170.	संघवा डिस्ट्री०	55
171.	इसरवाल डिस्ट्री०	68
172.	हसन डिस्ट्री०	35
173.	मिथी डिस्ट्री०	71.31
174.	सलीमपुर डिस्ट्री०	42.50
175.	भिवानी सब ब्रांच	883
176.	काहनोर सब ब्रांच	364
177.	भालोट सब ब्रांच	2052
178.	रोहतक डिस्ट्री०	118.2
179.	भालोट डिस्ट्री०	79.25
180.	बोहर डिस्ट्री०	35
181.	झज्जर सब ब्रांच	520
182.	दूलहेड़ा डिस्ट्री०	430
183.	बूटाना डिस्ट्री०	154
184.	भैंसवाल डिस्ट्री०	100
185.	इसराना डिस्ट्री०	58.40

Selection of Lady Constables

58. Sri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the category-wise names and addresses of candidates recruited/selected for the post of Lady Constables in the State during the year 2006-2007 ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, वांछित विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

सामान्य वर्ग

क्र०	प्रार्थियों का नाम	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	पता
1	2	3	4
1.	सुदेश रानी	ललजी राम	गांव धारनी, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
2.	अनीता कुमारी	ओमप्रकाश	गांव व डा० ललोढा, तह० टोहाना, जिला फतेहाबाद
3.	सुमन देवी	बदन सिंह	गांव व डा० फरीदपुर, तह० व जिला हिसार
4.	सुमन रानी	सुरज मल	गांव व डा० समैन, तह० टोहाना, जिला फतेहाबाद
5.	दर्शन कुमारी	जय प्रकाश	गांव महराना, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
6.	मंजु बाला	रामनिवाश	गांव व डा० प्रेम नगर, जिला भिवानी
7.	सुदेश कुमारी	रामचन्द्र	गांव व डा० गोरखपुर, तह० व जिला, फतेहाबाद
8.	अल्का	देवी लाल	गांव व डा० रमसारा, जिला फतेहाबाद
9.	सन्तोष देवी	बलवान सिंह	गांव सुलखानी, डा० बुगना, तह० व जिला हिसार
10.	अन्नु बाला	मंगत राम	गांव व डा० खेड़ीजला, जिला हिसार
11.	अनील देवी	राजपाल सिंह	गांव चार डा० संधलाना, तह० व जिला हिसार
12.	सरीता	धूप सिंह	गांव नौसवा डा० चिड़िया, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
13.	सुशीला देवी	आसराम	गांव व डा० बहारीवास, तह० तोशाम, जिला भिवानी
14.	नीलम देवी	आजाद सिंह	गांव सुल्तानपुर, तह० हांसी, जिला हिसार
15.	सुनीता	करतार सिंह	गांव हसन, तह० हांसी, जिला हिसार
16.	सुदेश कुमारी	रामचन्द्र	गांव व डा० कुम्हा, तह० हांसी, जिला हिसार
17.	सुमन देवी	तारा चन्द	गांव बहोदीया बीसनोईयां, तह० आदमपुर, जिला हिसार

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
18.	पूनम गिल	शीशराम	मकान नं० 839/3, आजाद नगर बैंक साईड बस स्टैण्ड, टोहाना, जिला फतेहाबाद
19.	मतेरी देवी	बीर सिंह	मतेरी पत्नी राजेन्द्र सिंह, गांव सीसार, डा० खरबाला, तह० हांसी, जिला हिसार
20.	फूलवती	महासिंह	गांव सीरसाली, डा० आडू, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
21.	सन्तोष	सुभाष चन्द्र	गांव व डा० मोडी, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
22.	विनोद देवी	आजाद सिंह	गांव व डा० उमरा, तह० हांसी, जिला हिसार
23.	पूनम कुमारी	सुखबीर सिंह	पूनम पत्नी राजेश, गांव व डा० गरनावथी, जिला रोहतक
24.	मीना कुमारी	रतन सिंह	गांव व डा० खरक कलां, जिला भिवानी
25.	उरमीला देवी	बलराज सिंह	गांव व डा० जुगलान, जिला हिसार
26.	राजबाला	राम कुमार	गांव व डा० सरहेडा, तह० बरवाला, जिला हिसार
27.	सुमन देवी	कर्मबीर सिंह	गांव व डा० दाता, तह० हांसी, जिला हिसार
28.	मीनू	हवा सिंह	गांव व डा० नीमरी, तह० बोदकलां, जिला भिवानी
29.	सुनीता देवी	कृष्ण सिंह	सुनीता पत्नी अंग्रेज पाल, गांव व डा० दबलैब, तह० नरवाना, जिला जीन्द
30.	बिमला रानी	बलदेव सिंह	गांव व डा० मांडीकलां, थाना उचाना, जिला जीन्द
31.	रोजी रानी	सतपाल	मकान नं० 87, वार्ड 16, नरवाना, जिला जीन्द
32.	गीता रानी	प्रकाश चन्द	गीता पत्नी राजेश, गांव व डा० बडहान, तह० व जिला जीन्द
33.	सुमन रानी	अंगद सिंह	गांव जटोली, थाना होडल, जिला फरीदाबाद ग्रामीण
34.	सोभा	योगिन्द्र सिंह	मकान नं० डी-792, तीरखा कालोनी, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद
35.	सुनीता बाई	महीपाल	गांव बहोरी, डा० गुजरवास, जिला महेन्द्रगढ़
36.	मोनीका	कर्ण सिंह	गांव व डा० दयालपुर, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
37.	कमलेश	लुहीराम	गांव परीथला, तह० पलवल, जिला फरीदाबाद ग्रामीण
38.	सोनीका	राजबीर सिंह	गांव कन्होरी, डा० कन्होरा, जिला रेवाड़ी
39.	रश्मी कुमारी	पत्नी संजयकुमार	गांव गदाईपुर, डा० पहाडी, जिला गुड़गांव
40.	पूनम	पत्नी प्रवीण कुमार	गांव औरंगाबाद, तह० होडल, जिला फरीदाबाद
41.	रेनू देवी	शील चन्द	गांव मंडवाली, डा० तिगांव, जिला फरीदाबाद
42.	मोनिका	सुरेन्द्र सिंह	गांव व डा० डहीना, तह० व जिला रेवाड़ी
43.	सपना	लालचन्द	मकान नं० 1264/5 पटेल नगर, गुडगांव
44.	पिंकी रानी	रतन सिंह	गांव रोजूवास, डा० रोहडाई, जिला रेवाड़ी
45.	कवीता रानी	राजपाल सिंह	गांव बोहराकलां, पट्टी गामा, जिला गुड़गांव
46.	मुनेश देवी	दलबीर सिंह	गांव टोटाहेरी, डा० करोता, तह० नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़
47.	प्रमीला	रमेश चन्द	गांव बीगोपुर, डा० धुलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़
48.	विजेता	विजय पाल	गांव व डा० जयनाबाद, थाना खोल, जिला रेवाड़ी
49.	गीता कुमारी	पत्नी राजेन्द्र कुमार	गांव डा० चीलरो, थाना नागल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़
50.	पूनम	पत्नी नरेश कुमार	गांव व डा० बराही, थाना सदर बहादुरगढ़, जिला झज्जर
51.	बीना	हुकम चन्द	गांव उशमापुर, डा० मंदोला, जिला महेन्द्रगढ़
52.	रूबी	बीजेन्द्र सिंह	गांव व डा० नयागांव जटोवाला, तह० झज्जर, जिला झज्जर
53.	सीमा	पत्नी सुरेन्द्र सिंह	गांव धाना, डा० साहलावास, तह० झज्जर, जिला हिसार
54.	शकुन्तला	पत्नी संदीप कुमार	गांव व डा० डाकला, जिला झज्जर
55.	नीशा	रणजीत सिंह	गांव मोहल्ला, डा० गाडपुरी बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद
56.	ममता	भूप सिंह	गांव व डा० पूंशीका, जिला रेवाड़ी
57.	मीना कुमारी	समयराम	गांव व डा० शीवाणा, तह० नराही, जिला झज्जर
58.	रीतू कुमारी	सुरेश सिंह	गांव व डा० महराणा, कीलोरपाना, जिला झज्जर

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
59.	नीलम	रणधीर सिंह	गांव दड़ोली जाट डा० दड़ोली अहीर, जिला महेन्द्रगढ़
60.	रवीनता	जयलाल	गांव धोषगढ, डा० जमालपुर, जिला गुड़गांव
61.	सीमा	वीरेन्द्र सिंह	मकान नं० 9, एन०एच०-3, राहूल कालोनी, नजदीक सैन्ट्रल ग्रीन एन०आई०टी०, जिला फरीदाबाद
62.	सुमन कुमारी	भूप सिंह	गांव व डा० गंडाला तह० बहरोड़ जिला अलवर (राजस्थान)
63.	पूनीत यादव	पत्नी पवन कुमार	गांव व डा० पालरा, तह० बेरी, जिला झज्जर
64.	सरोज कुमारी	सुरेश कुमार	गांव मुडियाखेड़ा, डा० दौंगडा अहीर, तह० नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़
65.	सुन्दर देवी	शुभराम	गांव व डा० सुलखा, तह० बावल, जिला रेवाड़ी
66.	अन्जु बाला	वेद प्रकाश	गांव व डा० पयोड़ा, सदर कैथल, जिला कैथल
67.	अमरजीत कौर	बलबीर सिंह	गांव मोरथला, सदर थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र
68.	जगजीत कौर	राजिन्द्र सिंह	गांव व डा० फतेहपुर, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर
69.	रीता देवी	जोगिन्द्र सिंह	गांव व डा० फतेहगढ़ तुम्बी, थाना मढौरा, जिला यमुनानगर
70.	रजनी बाला	बीर सिंह	गांव व डा० खरींडवा, थाना शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र
71.	कोमल	पवन कुमार	गांव व डा० बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र
72.	अनीला रानी	स्वरूप सिंह	न्यू प्योडा रोड, नजदीक चुंगी, शहर कैथल, जिला कैथल
73.	लखबीर कौर	दरबारा सिंह	गांव फौजी कालोनी, बनूर (पंजाब)
74.	सनवारी	सीताम सिंह	मकान नं० 288/10, कच्चा घर थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र
75.	सवीता देवी	मोहिन्द्र सिंह	गांव व डा० मानपुरा, शहर थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र
76.	अमनदीप कौर	इकबाल सिंह	गांव व डा० खूकन्नी, इन्द्री, करनाल
77.	अमरजीत कौर	रामपाल	गांव व डा० तारागढ़, सदर कैथल, जिला कैथल
78.	सोनिया रानी	ज्ञानचन्द	गांव व डा० भगवानपुर, बबैन, जिला कुरुक्षेत्र

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
79.	सर्बजीत कौर	जसविन्द्र सिंह	गांव व डा० रामसर बीटना, थाना पिंजौर, जिला पंचकुला
80.	कर्मजीत कौर	गुरचरण सिंह	गांव व डा० पंजटौ, शहजादपुर, अम्बाला
81.	सिवानी भल्ला	बी० के० भल्ला	मकान नं० 2/745, विश्वकर्मा कालोनी, पिंजौर, जिला पंचकुला
82.	मीना देवी	बारू राम	गांव व डा० ढिल्लोवाली पाडला, पिंजौर, जिला पंचकुला
83.	रीना देवी	हवा सिंह	गांव व डा० बरसाना, सदर कैथल, जिला कैथल
84.	राजन	मोहन सिंह	गांव व डा० बालू बाता, जिला कैथल
85.	कुलविन्द्र कौर	दारा सिंह	मकान नं० 115 बेकसाईड सिकरैट हर्ट हाई स्कूल, मजीठा रोड, अमृतसर मजीठा, अमृतसर (पंजाब)
86.	कान्ता देवी	रामचन्द्र	सी/ओ, भरत सिंह पुत्र लक्ष्मण, गांव व डा० शिमला, कलायत, जिला कैथल
87.	अनीता रानी	विक्रम सिंह	गांव सिंहपुरा डा० बोहरेशदान पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र
88.	कुसुम लता	रामपाल	गांव खानपुर राजपूतान, नारायणगढ़, जिला अम्बाला
89.	रीना रानी	जगीर सिंह	गांव सराली, नारायणगढ़, जिला अम्बाला
90.	डिम्पल	रामरतन	गांव व डा० संगौर, बबैन, जिला कुरुक्षेत्र
91.	रजीया खान	बाबू खान	गांव बाहम्मोली, बिलासपुर, जिला यमुनानगर
92.	सुमन रानी	मान सिंह	गांव व डा० तोपडाकलां, रादौर, जिला यमुनानगर
93.	पूनम देवी	प्रीतम दत्त	गांव व डा० सारसा, पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र
94.	हरविन्द्र कौर	छिन्द्र सिंह	गांव शार (रामदासपुर), सीवन, कैथल
95.	रीटा देवी	कृष्ण चन्द	गांव बहानीप्रहल्लादपुर, बबैन, जिला कुरुक्षेत्र
96.	रीना रानी	रामप्रताप	गली नं० कल्याण नगर, नजदीक एल०एन० जे०पी० अस्पताल, कुरुक्षेत्र
97.	मलजिन्द्र कौर	हरभजन सिंह	आर०/ओ० मुश्तफाबाद छप्पर, यमुनानगर
98.	कविता	राजेन्द्र सिंह	गांव व डा० इन्द्रगढ़, थाना महम, जिला रोहतक
99.	अनीता कुमारी	दिलदार सिंह	गांव व डा० छारा, बहादुरगढ़, जिला झज्जर
100.	नमना	जयपाल सिंह	गांव व डा० खरखडा, तह० महम, जिला रोहतक
101.	मुकेश	रनपत सिंह	गांव व डा० सांघी, तह० व जिला रोहतक

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
102.	सरोज देवी	कृष्ण लाल	गांव व डा० खार, तह० इसराना, जिला पानीपत
103.	रानी	ओमप्रकाश	गांव व डा० रूड़की, थाना सांपला, जिला रोहतक
104.	इंदू बाला	बलवान सिंह	गांव व डा० खाडवाली, जिला रोहतक
105.	सुधमा	महाबीर सिंह	गांव व डा० निडाना, तह० महम, जिला रोहतक
106.	सुदेश	रामफल	गांव व डा० साल्हावास, तह० मातन, जिला झज्जर
107.	सीमा	रणधीर सिंह	गांव व डा० बहु अकबरपुर, जिला रोहतक
108.	सुमन लता	मोहिन्द्र सिंह	गांव व डा० गढ़ी बल्लाह, कलानौर जिला रोहतक
109.	रेनू बाला	राज सिंह	गांव व डा० छारा, टोलाउनीयन, झज्जर
110.	मीनाक्षी	जगत सिंह	मकान नं० 16/99, कच्चा बाग, नजफगढ़ रोड, बाहदूरगढ, जिला झज्जर
111.	राजेश रानी	सतपाल	गांव व डा० भालोट, थाना सदर, रोहतक
112.	पूनम	महाबीर	गांव व डा० ब्राहमणवास, थाना सदर, रोहतक
113.	मुकेश कुमारी	रामफल	गांव व डा० मोखरापाना छाजाण महम, जिला रोहतक
114.	सोनिया	नफेसिंह	गांव व डा० बहु अकबरपुर, रोहतक
115.	स्वीटी	महजेन्द्र	गांव व डा० चूलियाना, थाना सांपला, जिला रोहतक
116.	बबली देवी	अत्तर सिंह	गांव व डा० महावती, तह० समालखा, पानीपत
117.	रेखा कुमारी	गोपी राम	गांव व डा० चिड़िया, तह० बरखी दादरी, जिला भिवानी
118.	सुमन कुमारी	रणसिंह	गांव व डा० सेहलंग, डा० बरखी दादरी, जिला झज्जर
119.	नीलम	रत्ती राम	गांव व डा० दुबलधन (बीडहन), तह० बेरी, जिला झज्जर
120.	पिंकी	जय भगवान	गांव व डा० चमनिया, रोहतक
121.	गीता	सतीश कुमार	मकान नं० 308/6, गली नं० 8, चोउ राम कलोनी, सुखपूरा चौंक, रोहतक
122.	नीलम	राजबीर सिंह	गांव व डा० बालंद, तह० रोहतक, जिला रोहतक
123.	राजबाला	अमरजीत	गांव व डा० भाजरा दुबलधन, त० बेरी, जिला झज्जर

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
124.	रीना	नारायणदत्त	गांव व डा० लाजपुर, तह० बापोली, जिला पानीपत
125.	ममता	प्रदीप सिंह	गांव व डा० सांघी, पाना असराव, तह० रोहतक, जिला रोहतक
126.	धनपती	रतनसिंह	गांव व डा० माजरा दुबलधन, तह० धेरी, जिला झज्जर
127.	कविता	कहयाली राम	विध्या नगर, महम रोड, सुभाष मार्ग गली, भिवानी
128.	राखी	बलराज	मकान नं० 1601/311, शास्त्री कालोनी, गली नं० 4 जिला सोनीपत

अनुसूचित जाति श्रेणी-ए

1.	सुमन बाला	रामस्वरूप	गांव व डा० डरबी, तह० व जिला सिरसा
2.	उषा रानी	पालू राम	मकान नं० 550, न्यू माडल टाउन, जिला हिसार
3.	सुरेश कुमारी	बस्ती राम	गांव व डा० काकरोली सरदार, जिला भिवानी
4.	सुमन	सतबीर	गांव खेरी बतर, डा० खेरीबुरा, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
5.	बबीता	सुरेश	मकान नं० 132/1 गावरिया का मोहल्ला पीछे गणपत राज अस्पताल, भिवानी
6.	सुमन कुमारी	ललसिंह	पत्नी सुशील कुमार गांव व डा० पूर तह० बवानी खेरा, जिला भिवानी
7.	रेखा कुमारी	श्रामसिंह	गांव व डा० चावा, तह० कोसली, जिला रेवाड़ी
8.	लखबीर कौर	भगूराम	गांव व डा० सन्थली, तह० नरवाना, जिला जीन्द
9.	शकुन्तला	टमरसिंह	मकान नं० 522/129, गुड़गांव, जिला गुड़गांव
10.	मंजू बाई	धर्मपाल	गांव व डा० नगवान, जिला महेन्द्रगढ़
11.	बबीता	चत्तर सिंह	मकान नं० 1424/8 बीसवा, गांव, गुड़गांव जिला गुड़गांव
12.	उषा बाई	जय सिंह	गांव व डा० बलवाड़ी, थाना खोल, जिला रेवाड़ी
13.	मोनिका	राज बहादूर	गांव आजमनगर, डा० धरसू, तह० नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
14.	पूनम	स्वर्गीय प्रभूदयाल	वार्ड नं० 15, नजदीक राजबीर आखों का हस्पताल, झज्जर, जिला झज्जर
15.	सुनीता	सुबे सिंह	गांव व डा० ज्योंधी, थाना झज्जर, जिला झज्जर
16.	अनीता कुमारी	जगमाल सिंह	मकान नं० 486, सैक्टर-6, जिला पंचकुला
17.	सीमा	तिलक राज	गांव चंदाना, सदर कैथल, जिला कैथल
18.	रेखा देवी	किताब सिंह	गांव आढोपटी, कलायत, जिला कैथल
19.	सरीता	श्यामसिंह	गांव मोखरा, थाना महम, जिला रोहतक
20.	सिमरनजीतकौर	गुरविन्द्र सिंह	गांव किशनगढ, जिला कुरुक्षेत्र
21.	सुनीता रानी	गोकुल चन्द	गांव थीगढ, जिला फतेहाबाद
22.	नीता कुमारी	धर्मपाल	वार्ड 6 गांव व डा० मोहल्ला बड़ा पाना, थाना कलानौर, जिला रोहतक
23.	शशि बाला	पदम राम	गांव व डा० तरावड़ी, जिला करनाल
24.	लता रानी	श्राजसिंह	गांव व डा०, खुबारू, तह० गन्नौर, जिला सोनीपत
25.	कमलेश देवी	नाथू राम	गांव व डा० भिन्नी भैरो, तह० महम, जिला रोहतक
26.	पिंकू	बिजेन्द्र सिंह	गांव व डा० सिलोना, गोरार रोड़ सोनीपत
27.	कविता	चन्द्र सिंह	एल०आई०जी० मकान नं० 7/49, मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई, जिला सोनीपत
अनुसूचित जाति श्रेणी - बी			
1.	सुमन देवी	ओम प्रकाश	गांव व डा० पनीहारी, बरवाला, जिला हिसार
2.	कविता देवी	गुरदयाल सिंह	गांव व डा० रामसरा, भट्टू, जिला फतेहाबाद
3.	मुकेश रानी	चन्द्र पाल	गांव व डा० कट्वाल, अलेवा, जिला जीन्द्
4.	कान्ता रानी	शेर सिंह	गांव व डा० गारनपुरा कलां तोशाम जिला भिवानी
5.	पिंकी रानी	रामदीया	मकान नं० 336, वार्ड 21, भगत सिंह कलोनी, नरवाना, जिला जीन्द
6.	सुनीता रानी	ओमप्रकाश	गांव व डा० खानपुर, हांसी, जिला हिसार
7.	नीलम कुमारी	कंवर लाल	गांव कापरीवास, डा० धमलपुरा, जिला रेवाड़ी

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
8.	सुमन बाई	मूलचन्द	गांव झाड़ली, डा० चिजरोली, तह० कनीना, जिला महेन्द्रगढ़
9.	मधु बाला	हंसराज	गांव भोठरा मोहलाबाद, डा० पाली, थाना सैक्टर-55, जिला फरीदाबाद
10.	रेनू	रामफल	गांव व डा० भापरोदा तह० बहादूरगढ़ जिला झज्जर
11.	मीनाक्षी	मेहर चन्द	गांव व डा० घोरी, तह० पलवल, थाना चांदहट, जिला फरीदाबाद ग्रामीण
12.	जवाला देवी	विक्रम	गांव रेहनवा बराहेडी, थाना पटौदी, जिला गुड़गांव
13.	गुरविन्द्र कौर	नसीर सिंह	गांव पंजोखरा साहब, जिला अम्बाला
14.	सीमा देवी	रोशन लाल	गांव खान, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर
15.	मनीषा रानी	राम कुमार	गांव व डा० फरल, थाना पूंडरी, जिला कैथल
16.	रजनीश कौर	फूलचन्द	गांव कूलपूर, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर
17.	सरला रानी	मांगे राम	मकान नं० 322, वार्ड 13, लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र
18.	सुदेश कुमारी	सुरजन सिंह	गांव करसा रोड, थाना नीलोखेडी, जिला करनाल
19.	मेवा रानी	सर्वण राम	गांव जोगी माजरा, थाना शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र
20.	अनीता रानी	ओम प्रकाश	इ०एस०आई० हस्पताल कैम्पस जगाधरी, जिला यमुनानगर
21.	सबीता	श्रामसिंह	आनन्द नगर, मेन झज्जर रोड, नजदीक जलघर, रोहतक
22.	टाशा रानी	सुरजमल	गांव व डा० गोयलकलां, तह० बहादुरगढ़, जिला झज्जर
23.	सीमा देवी	सूरत सिंह	गांव व डा० नाहरा, जिला सोनीपत
24.	प्रिति	परमानन्द	गांव व डा० चिड़ि, तह० महम, जिला रोहतक
25.	नीलम सबरवाल	कर्ण सिंह	मकान नं० 2329-30, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सै०-1 थाना सिविल लाईन, रोहतक
26.	रामभतेरी	ओमप्रकाश	गांव व डा० जहाजगढ़, जिला झज्जर
27.	रीना	सतपाल	गांव व डा० सिंहपुरा कलां, रोहतक

पिछड़ा वर्ग श्रेणी - ए

1	2	3	4
		(सर्वश्री)	
1.	सीमा रानी	कर्म चन्द्	गांव व डा० ढाणी 400, डा० झोरावली, जिला सिरसा
2.	सरोज रानी	दलीप सिंह	गांव व डा० बीराना, जिला फतेहाबाद
3.	मंजू	भगवाना राम	गांव व डा० हीडोल, जिला भिवानी
4.	मीना देवी	धर्मपाल	गांव व डा० खानक, तह० तोशाम, जिला भिवानी
5.	इंदू बाला	हरी ओम	गांव व डा० बरसाना, तह० दादरी, जिला भिवानी
6.	मनीता देवी	सरूप सिंह	गांव व डा० ढाणी टेक सिंह, तह० नरवाना, जिला जीन्द
7.	निर्मला	महाबीर	दीनोद गेट गांधीनगर, गली नं० 1, भिवानी
8.	पुष्पम	मनफूल	गांव पडाना, जिला जीन्द
9.	निर्मला	प्रभुराम	गांव व डा० मंडाना, जिला भिवानी
10.	रेखा देवी	राम किशन	गांव व डा० कादमा, जिला भिवानी
11.	लक्ष्मी	वेदप्रकाश	गांव व डा० धानसू, जिला हिसार
12.	बबीता	लखीराम	गांव रोहटा पट्टी होडल, थाना होडल, जिला फरीदाबाद ग्रामीण
13.	मीनेश कुमारी	रमेश कपिल	वार्ड नं० 23, नई सराय, थाना शहर नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़
14.	पुष्पांजली	जयभगवान	गांव भूतल ठेठर, थाना रोहडाई, जिला रेवाड़ी
15.	अनीता वर्मा	बिशनलाल	मकान नं० 151 वार्ड 2 अहीरवाडा, थाना शहर बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद
16.	सुमन कुमारी	घनश्याम सिंह	रेलवे स्टेशन, कोसली, जिला रेवाड़ी
17.	सुमन देवी	बाबुलाल	गांव दुजाना, थाना बेरी, जिला झज्जर
18.	पूनम देवी	सुलतान सिंह	गांव व डा० खुंगर, थाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी
19.	ममता	सुनीलाल	गांव व डा० बेवल, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़
20.	बीना बाई	महाबीर प्रसाद	गांव महासर, थाना अटेली, जिला महेन्द्रगढ़
21.	मैना कुमारी	राजबीर सिंह	गांव व डा० करणावास, तह० व जिला रेवाड़ी
22.	रीता देवी	जानकी प्रसाद	मकान नं० 164 सै०-25, कुम्हार मण्डी, कच्चा बाजार, अम्बाला कैन्ट
23.	राजबीर कौर	दर्शन सिंह	जुरासी खुर्द, डा० भूथानी, थाना पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
24.	नीशा देवी	सोमनाथ	गांव तीगरी, डा० उरनाई, थाना पेहवा, जिला कुरूक्षेत्र
25.	सिमरनजीतकौर	गुरबच्चन सिंह	कोरवाकलां, शहजादपुर, अम्बाला
26.	बलजीत कौर	कश्मीर सिंह	गांव बचहकी, थाना झांसा, जिला कुरूक्षेत्र
27.	बलजीत कौर	बलिसिंह	गांव व डा० बकहाली, प्लाट नं० 4, पेहवा थाना पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र
28.	सीमा रानी	पूर्ण सिंह	गांव व डा० दादहोट, सतनाली, महेन्द्रगढ
29.	मीना देवी	जीजूदीन	मकान नं० 22 वार्ड 16, विकास नगर, यमुनानगर थाना फरकपूर, यमुनानगर
30.	सुमन लता	नरेश कुमार	गांव झाकवाला, इस्माईलाबाद, कुरूक्षेत्र
31.	सावित्री	रामकुमार	गांव बबयाल, महेश नगर, अम्बाला
32.	वाहिदा रहमान	साहिद अहमद	गांव कोटार, डा० दलकोर, सदर जगाधरी, यमुनानगर
33.	सुमन	शीशपाल	गांव व डा० नूनामाजरा, तह० बहादुरगढ, जिला झज्जर
34.	रेनू	चन्दर सिंह	गांव जीन्दराम, डा० खिडवाली, थाना सदर, रोहतक
35.	पूजा रानी	सोमनाथ	मकान नं० 3783, शिव कलोनी, थाना शहर करनाल, जिला करनाल
36.	सुशीला	सतबीर सिंह	गांव व डा० मकडोलीकलां, थाना सदर रोहतक
37.	अमनदीप	दयाल चन्द	गांव व डा० शाम्भी डेरा सौदापुर, थाना निसिंग जिला करनाल
38.	सरगो देवी	ओम प्रकाश	गांव व डा० भूराबास, जिला झज्जर
39.	अंजू बाला	पतिया राम	गांव व डा० जुंडला, थाना सदर, करनाल
40.	सुशीला देवी	बलबीर सिंह	गांव व डा० किलाजफगढ, थाना जुलाना, जिला रोहतक
41.	मीनाक्षी	धर्मपाल	गांव व डा० टीटोली, थाना सदर रोहतक, जिला रोहतक
42.	सरला	रामनिवास	वार्ड 1, उजाला नगर, थाना महम, जिला रोहतक

पिछड़ा वर्ग श्रेणी-बी

1	2	3	4
		(सर्वश्री)	
1.	राकेश	सज्जन सिंह	गांव व डा० चांगरोड, चरखी दादरी, भिवानी
2.	सुनीता कुमारी	हंस राज	गांव व डा० मिलकपुर, बवानी खेड़ा, जिला भिवानी
3.	मीना कुमारी	मनफूल सिंह	गांव व डा० हट, सफीदो, जिला जीन्द
4.	वीना कुमारी	शिव शंकर	गांव व डा० गुवानी, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़
5.	सुनीता देवी	राम सिंह	बहादुरगढ़, जिला झज्जर
6.	पींकी	धर्मबीर	गांव सेहलगा, जिला महेन्द्रगढ़
7.	निधी यादव	कर्ण सिंह	गांव खरखड़ा, तह० धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी
8.	प्रीती यादव	धर्मसिंह	गांव बांसलाम्बी, तह० फरूखनगर, जिला गुड़गांव
9.	रीना कुमारी	विजेन्द्र सिंह	गांव व डा० कोथलकुर्द, जिला महेन्द्रगढ़
10.	पुष्पा रानी	कमल सिंह	मकान नं० 1244 ए-ब्लॉक डबुआ कलोनी, एन०आई०टी० फरीदाबाद
11.	मुकेश कुमारी	पत्नी सही राम	गांव गोमला, डा० भोजावास, जिला महेन्द्रगढ़
12.	रिन्कू कुमारी	जगदीश	गांव व डा० खेड़ा पटौदी, जिला झज्जर
13.	कुशुम रानी	रणजीत सिंह	गांव सबगा, डा० पसियाला, अम्बाला
14.	मनजीत कौर	कुलदीप सिंह	मकान नं० 118/8, मोहल्ला पुराना डाकखाना, शाहबाद, कुरूक्षेत्र
15.	मनीषा	प्रेम चन्द	गांव भैणी, सदर थानेसर, कुरूक्षेत्र
16.	रजनी	ओमप्रकाश	गांव सुन्दरपुर, सदर थानेसर, कुरूक्षेत्र
17.	सुदेश कुमारी	कर्म सिंह	गांव व डा० सालेपुर, सदर यमुनानगर, जिला यमुनानगर
18.	निर्दोष सैनी	रान कुमार	गांव मोने माजरा, थाना नारायणगढ़, अम्बाला
19.	किताबो	लहरी सिंह	गांव व डा० गढ़ी उजले खान, थाना सदर गोहाना, जिला सोनीपत
20.	सरीता	रामेश्वर	गांव व डा० शीशरखास, थाना महम, जिला रोहतक
21.	किरण बाला	प्रेम सिंह	गांव व डा० बालंद, थाना असंध, जिला करनाल
22.	सन्तोष देवी	श्री किशन	गांव व डा० हसनगढ़, थाना सांपला, जिला रोहतक
23.	पूनम कुमारी	अभय सिंह	गांव व डा० गोरिया, थाना साहलावास, जिला झज्जर
24.	प्रेम लता	वेद पाल	गांव व डा० खातीवास, थाना झज्जर, जिला झज्जर

खेल कोटा

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
1.	रेखा कुमारी	जय भगवान	गांव व डा० झोझू कलां, जिला भिवानी
2.	प्रमिला	गोपी राम	गांव भोडी, तह० चरखी दादरी, जिला भिवानी
3.	बिमलेश	सुबे सिंह	गांव व डा० कारोली, तह० कोसली, जिला रेवाडी
4.	संगीता	सुरेन्द्र	मकान नं० 220, कृष्ण नगर, थाना माडल टाउन, रेवाडी
5.	मनीता	धर्मपाल	गांव ब्रहमपुर डा० गुड़यानी, तह० कोसली, जिला रेवाड़ी
6.	निशा	दलेल सिंह	गांव व डा० अमीन, थाना कुरूक्षेत्र, जिला कुरूक्षेत्र
7.	रजनी	पूर्ण चन्द	मकान नं० 67, राजीव गार्डन, कांसापुर रोड थाना सदर, जगाधरी, जिला यमुनानगर
8.	प्रमिला देवी	राजबीर सिंह	गांव व डा० खरखोदा तह० महम, जिला रोहतक
9.	मीना देवी	सत्यवान	गांव व डा० सामन तह० महम, जिला रोहतक

भूतपूर्वक सैनिक (सामान्य)

		(सर्व श्री)	
1.	सुनीता कुमारी	महासिंह	गांव व डा० बीरही कलां, चरखी दादरी, जिला भिवानी
2.	कर्मवती	प्रताप सिंह	गांव व डा० आश्रम कलोनी, जीन्द रोड़, बरवाला, जिला हिसार
3.	कल्पना यादव	सुबे सिंह	गांव व डा० नांगल सिरोही, जिला महेन्द्रगढ़
4.	कमलेश कुमारी	कर्ण सिंह	गांव व डा० कलीरावण, आदमपुर, जिला हिसार
5.	उषा	सुरेश कुमार	गांव व डा० जयवन्ती, जुलाना, जिला जीन्द
6.	अनूप देवी	महाबीर सिंह	गांव व डा० पेंटावास, चरखी दादरी, जिला भिवानी

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
7.	रेनू देवी	बहादुर सिंह	सिरसा, गोगरा, जिला भिवानी
8.	रूबी	धर्मबीर सिंह	माडल टाउन सी-125, एक्सटेंशन, जिला हिसार
9.	सुनीता बाई	बनवारी लाल	गांव बडरोना, तह० बावल, जिला रेवाड़ी
10.	सुनील देवी	जोगिन्द्र सिंह	गांव सहराला, डा० धतीर, तह० पलवल, जिला फरीदाबाद ग्रामीण
11.	पूनम	भोलू राम	गांव ब्रहमपुर भड़गी, डा० धारण, जिला रेवाड़ी
12.	सुषमा यादव	अभय सिंह	मकान नं० 543, यादव नगर, रेवाडी, जिला रेवाडी
13.	नवजीत कौर	सुखविन्द्र सिंह	प्लाट नं० 9, कमलनगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला
14.	रजनी	देश राज	गांव व डा० छप्पर, मुलाना, अम्बाला
15.	बलजिन्द्र कौर	पाल सिंह	मकान नं० 95 राणा कम्पलैक्स अम्बाला कैन्ट, अम्बाला
16.	अंजू कुमारी	राम चन्द्र	मकान नं० 50 ए, देवीस नगर, नजदीक बब्याल पावर हाउस, महेश नगर, अम्बाला
17.	सरस्वती	प्रीतम सिंह	मकान नं० 34, दुर्गियाणा कलोनी, महेश नगर, अम्बाला
18.	नीलम	ईश्वर सिंह	मकान नं० 608/18, गीता कलोनी, महम रोड, गोहाना, सोनीपत
19.	सोनिया देवी	राम नारायण	गांव व डा० सुन्धाना, थाना कलानौर, रोहतक
20.	सुशीला	जागे राम	गांव व डा० दुबलधन, थाना झकयान, झज्जर
21.	सोनू रानी	सतपाल सिंह	गांव व डा० थारू, ओल्डपुर, तह० सोनीपत, जिला सोनीपत
22.	सीता	हरी सिंह	गांव व डा० निडाना, थाना महम, रोहतक
23.	राजबाला	ईश्वर सिंह	गांव डा० निडाना, थाना महम, रोहतक

भूतपूर्वक सैनिक (अनुसूचित जाति श्रेणी-ए)

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
1.	रजो	मोहर सिंह	गांव ढाकिया, डा० खतवाली, जिला रिवाड़ी
2.	मंजू रानी	अजीत राम	मकान नं० 4041, दलीपगढ़, महेश नगर, जिला अम्बाला
3.	मंजू	प्रीत राम	गांव रैया, डा० डावला, तह० व जिला झज्जर

भूतपूर्वक सैनिक (अनुसूचित जाति श्रेणी-बी)

1.	पूनम	बलदेव सिंह	गांव व डा० धीण, तह० बराड़ा, जिला अम्बाला

भूतपूर्वक सैनिक (पिछड़ा वर्ग श्रेणी-ए)

1.	मीना कुमारी	हनुमान सिंह	गांव व डा० भोजावास, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ
2.	शकुन्तला	दयानन्द	गांव दवारिका, चरखी दादरी, भिवानी
3.	सुमन बाला	कृष्ण लाल	गांव मुलाना, थाना मुलाना, अम्बाला
4.	कुसुम रानी	नफे सिंह	गांव व डा० जोंधनकलां, तह० इसराना, जिला पानीपत
5.	पूनम	प्रीतम दत्त	गांव व डा० सारसा, कुरुक्षेत्र

भूतपूर्वक सैनिक (पिछड़ा वर्ग श्रेणी-बी)

1.	राखी	कृष्ण	गांव व डा० मीरपूर, जिला रेवाड़ी
2.	अनीता देवी	पत्नी स्व० सुरेश कुमार	गांव व डा० जैनाबाद, थाना सदर रिवाड़ी, जिला रेवाड़ी
3.	कमलेश कुमारी	बृजमोहन	गांव मुलाना, थाना मुलाना, जिला अम्बाला
4.	सन्तोष कौर	बन्ता सिंह,	गांव साहा, थाना मुलाना, जिला अम्बाला
5.	रीषा	सुभाष चन्द्र	गांव व डा० भूथला, तह० कोसली, रिवाड़ी

भूतपूर्वक सैनिकों पर आश्रित अनुसूचित जाति वर्ग

1	2	3	4
		(सर्व श्री)	
1.	आशा देवी	विजय सिंह	गांव व डा० पलड़ी, चरखी दादरी, जिला भिवानी
2.	शकुन्तला	दनेश कुमार	गांव व डा० रूपगढ़, जिला भिवानी

शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के समक्ष शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह सदन संयुक्त पंजाब विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री करनैल सिंह के 11 मार्च, 2007 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 मई, 1916 को हुआ। वे 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्य मंत्री महोदय जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है और दिवंगत आत्मा के प्रति जो विचार प्रकट किये हैं मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। श्री करनैल सिंह, भूतपूर्व सदस्य, पंजाब विधान सभा, बहुत अच्छे व्यक्ति थे उनके निधन पर मुझे भी गहरा शोक है। उन्होंने देश और समाज की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की। उनकी समाज के लिए की गई सेवा के योगदान को हम भुला नहीं सकते। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। शोक संतप्त परिवार तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों से खड़ा होने का अनुरोध करता हूँ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, परसों और कल रात को सूचना आई है कि भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश में खास तौर से पलवल, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, मेवात, भिवानी और अम्बाला जिलों के कुछ हिस्सों में बहुत नुकसान हुआ है। कल रात को ही हमने आदेश दे दिये हैं कि विशेष गिरदावरी की जाए। सरकार नार्म्स के हिसाब से किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/वाकआउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, भैरा और सढौरा साहब का एक कालिंग अटैंशन मोशन regarding poor supply of power in the State था, उसका फेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, वह डिसअलाऊ हो गया है और इस बारे में आपको सूचित भी कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरे दो साथियों ने एक और कालिंग अटैंशन नोशन regarding increasing problem to common man due to rising prices था उसका अब क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, वह नोशन भी डिसअलाऊ हो गया है और इसके बारे में भी आपको सूचित कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा और मेरे दो साथियों का एक और कालिंग अटैंशन मोशन regarding increasing of atrocities on dalit community था, उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब यह भी डिसअलाऊ हो चुका है और इसके बारे में भी आपको सूचित कर दिया गया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ये सारे मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको इन कालिंग अटैंशन मोशंज को एडमिट करना चाहिए था ताकि लोगों की दिक्कतें हम सदन के नोटिस में ला सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded (interruptions and noises) डॉ० साहब, कल जब आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन एक्सैप्ट किया था तब भी आप हाउस से चले गए थे। (शोर एवं व्यवधान) आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन को रिजैक्ट करने के बारे में स्पैसिफिक रीजन्ज दिये गये हैं (शोर एवं व्यवधान) 54 मिनट का समय आपकी पार्टी के मैम्बर्ज के बोलने के लिए बनता था लेकिन करीब डेढ़ घण्टे का समय आपके नेता ने बोलते समय ले लिया। इस डेढ़ घण्टे के समय में उन्होंने कोई बात नहीं कही। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब, अब आप बजट पर बोल लेना आपको पूरा समय देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और आपने हमारे कालिंग अंटेशन मोशंज भी डिसअलाऊ कर दिए हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं। **(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)**

प्रो० छतरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के सदस्यों की तो वाकआउट करने की आदत हो गयी है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रान्त में कल जहां-जहां भी ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि के कारण जहां जहां पर भी किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के बारे में सरकार ने कदम उठाए हैं और गिरदावरी करवाने के लिए आर्डर किये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कई जिलो का जिक्र किया है लेकिन शायद जिला हिसार के बारे में सूचना उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। वहाँ पर मेरे विधान सभा क्षेत्र और दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि हुई है और फसलों की तबाही हुई है। मेरे हल्के के काफी गांव इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, सदन के नेता की तरफ से जो ब्यान दिया गया है क्या वह आपने नहीं सुना था ?

प्रो० छतरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कुछ गांव हैं जो इस ओलावृष्टि से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उन विलेजिज़ को मैं इन्कलूड करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता ने नये सिरे से गिरदावरी करवाने की बात कही है इसलिए गिरदावरी के दौरान आप अपने गांवों के नाम इन्कलूड करवा सकते हैं। जहां-जहां भी नुकसान हुआ है नई गिरदवारी करवा कर किसानों को मुआवजा देने की बात उन्होंने कही है इसलिए आप अब बैठें।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बारे में स्टेटमैंट हाउस के अन्दर दे दी है इसलिए इस तरह की बात की जरूरत नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे फाईनैंशियल कमिश्नर ने सभी डी०सीज़० को लैटर फैक्स कर दिया है और यह लिख कर भेजा है कि स्टेट में जहां भी ओलावृष्टि हुई है वहां पर तुरन्त स्पैशल गिरदावरी करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आश्वासन देना चाहूंगा कि यह सरकार हर वर्ग के लोगों पर चाहे वे किसान हों, चाहे मजदूर हों या चाहे दूसरे किसी भी वर्ग के लोग हों, पूरा ध्यान देगी और किसानों का जो भी नुकसान हुआ है चाहे वह पलवल के किसान हों अथवा हिसार के किसान हों, उनको उनके नुकसान का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण रिवाड़ी जिले में भी नुकसान हुआ है तथा भिवानी जिले में भी नुकसान हुआ है। मैं यहां पर हाउस में यह कहना चाहूंगा कि जहां भी ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है हमने जो लेटैस्ट रिवाईज़्ड नॉर्म्ज़ फिक्स किए हैं उसके मुताबिक किसानों को कम्पनसेशन दिया जाएगा।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में जो आश्वासन दिया है वह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सरकार द्वारा मामले में तुरन्त कार्यवाही की गई है लेकिन मेरी सोच में एक बात और भी है। यहां पर केवल ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की ही बात कही जा रही है लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से भी फसलों की बहुत जबरदस्त तबाही हुई है और जो सर्वे किया गया है वह भी बहुत पहले हो चुका है। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इसका सारे का सारा सर्वे इस वक्त दोबारा से करवाया जाए क्योंकि अब फसल पानी की वजह से भी बिल्कुल तबाह हो गई है। इस समय तो पानी की वजह से भी नुकसान हुआ है और एक किस्म से हालत फ्लड जैसी हो गई है इसलिए इसका पूरा सर्वे दोबारा से करवाया जाना चाहिए। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप जानते हैं कि यह ज़ीरो आवर है और इस समय कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। (विघ्न) क्या वे जनहित के मुद्दे न उठाएं ? (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इससे इम्पोर्टैन्ट कोई और मैटर हो सकता है, क्या प्रदेश के अन्दर जो भीषण तबाही हुई है उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ये विद दि परमिशन ऑफ दि चेयर बोल रहे हैं और जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये जनहित के मुद्दे न उठाएं ? (विघ्न) Dr. Indora, I warn you, please take your seat. (interruptions).

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आनन्द सिंह डांगी जी ने जो बात कही है मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉ इन्दौरा जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (विघ्न) इन्दौरा जी, आप बिना परमिशन के बोलने के लिए नहीं खड़े होंगे। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बात आनन्द सिंह डांगी जी ने कही है मैं उस बारे में सदन में जवाब देना चाहता हूं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, यह सदन 90 मैम्बर्ज का है। क्या आप 9 सदस्यों ने ही सदन में बोलने का अधिकार ले लिया है ? (विघ्न) आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, ये अभी अन्दर लॉबी में गए थे और वहां से पढ़ कर आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने जो जो सप्लीमैंट्री पूछी है उसका भी जवाब दिया गया है और आपने जो जो सवाल दिए थे वे भी लगे हैं । फिर भी आप इस तरह से सदन में बिहेव कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) गवर्नर एड्रैस की डिस्कशन पर आपकी पार्टी का 54 मिनट का समय बोलने के लिए बनता था और आपके नेता 1.30 घंटे बोले हैं। (विघ्न) अब आपको बजट डिस्कशन पर बोलने के लिए समय मिलेगा। आप उस समय बोल लेना। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी की छात्राओं का अभिनन्दन

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए हिन्दू गर्ल्ज कालेज, जगाधरी की छात्राएं दर्शक दीर्घा में बैठी हुई हैं मैं सदन की तरफ से उन सभी छात्राओं का अभिनन्दन करता हूँ। डॉ० सीता राम जी, आप पढ़े लिखे सदस्य हैं। आप सदन में ठीक तरह से बिहेव करें। (विघ्न) कालेज की ये बच्चियां आपके बिहेव से क्या सीख कर जाएंगी और क्या आपकी पार्टी के बारे में लोगों में इम्प्रैशन जाएगा ? आप इस तरह से सदन में बिहेव न करें। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : इनकी कुछ भी बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) आप सभी सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन का समय बर्बाद न करें। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। यह बहुत ही जरूरी मुद्दा है और मंत्री जी इस बारे में जवाब देना चाहते हैं। आप उनको पहले जवाब दे देने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मेरे सवाल के बाद मंत्री जी इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, अभी आप बैठे।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for the suspension of Rules 231, 233, 235 and 270 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move–

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes;

for the year 2007-2008 be suspended.

Sir, I also beg to move—

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2007-2008, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2007-2008 be suspended.

and

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2007-2008, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Questions is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertaking ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2007-2008 be suspended.

and

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2007-2008, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

बैठक का स्थगन

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप दूसरा बिजनैस शुरू करें मैं सबसे पहले आपसे एक सबमिशन करना चाहता हूं। कल तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया था, कन्कलूड करने की तो दूर की बात है।

श्री अध्यक्ष : क्या कल आपने बोलना शुरू नहीं किया था ? कल तो आप अपनी बात कन्लूड कर चुके थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपको चेयर की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए।

Mr. Speaker : What do you mean ? चेयर की गरिमा से आपका क्या मतलब है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि मैं इस सदन का सदस्य हूं और मुझे हर बात कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : दो साल से हाउस चल रहा है तब आप कहां थे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल जो आपका तौर तरीका था क्या वह सही था ?

Mr. Speaker : What do you mean by ''तौर तरीका''? अगर आपका चेयर में विश्वास नहीं है तो आप सदन में मत आइये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है, मैंने आपको कह दिया था लेकिन यह आपका कोई तरीका नहीं है। यह हाउस आपकी जागीर नहीं है। आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : क्या अधिकार है आपका ? क्या आपको सदन की गरिमा गिराने का अधिकार है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। यह आपका कोई तरीका थोड़े ही है। आपने हाउस को तमाशा बना दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य हाउस की वैल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruptions) क्या आप सब रात को सोचकर आए हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आप कल तो ऐसा नहीं बोले।

(शोर एवं व्यवधान) I warn you. Please go to your seats.

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, ** ** **

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ** ** **

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इनकी यह तानाशाही नहीं चलेगी, इसलिए इन तानाशाहियों को हरियाणा की जनता ने निकाल दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठें और अपनी सीटों से ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठें और अपनी सीटों से ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान) रात-रात में आपको क्या पढ़ा दिया है ? आप बैठ जाएं। सदन की गरिमा को बनाए रखें। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हैं या अपनी जो भी बात कहनी हैं उसके लिए पहले आप अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं और जो भी बात कहनी है अपनी सीटों से कहें। आपको अपनी बात कहने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned for 10 minutes.

*10.54 Hrs. (The Sabha then *adjourned at 10.54 hours and re-assembled at 11.04 hours.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now the discussion on Governor's address will resume.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने कल गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए मुझे 54 मिनट दिए थे। आप असैम्बली की कार्यवाही उठाकार देख लीजिए कि मैंने कितने समय बोला है और कितने समय में मैं अपनी बात कह पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपने बोलते हुए कोई ऐसा प्वायंट उठाया होगा जिससे दूसरे सदस्य को कोई इरीटेशन हुई होगी। आपने जो शब्द कहे to put the record straight, "any member has a right to demand for the point of order". यह जनरल प्रैक्टिस रही है कि जो सदस्य बोलता है उसी के समय में वह समय काउंट होता है। उसमें चाहे जितनी इन्ट्रप्शन हो। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर बहस के दौरान मेरे भाषण में अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो वह सदस्य अपनी बात कहते हुए उसका उल्लेख कर सकता है या वह माननीय सदस्य उस बात को अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कह सकता है। कल गवर्नर महोदय, के अभिभाषण पर बहस के समय तो ऐसा तरीका अपनाया जा रहा था जैसे बहस की बजाए भाषण हो रहा हो। कल तो कोई भी सदस्य प्वायंट ऑफ आर्डर की आड़ लेकर पूरा भाषण देना शुरू कर देता था।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपने उस समय कोई भी बात को प्वायंट आउट नहीं किया। डेमोक्रेटिक नार्म्स हैं और उन्हीं की परव्यू में यह हाउस चल रहा है। Nobody pointed out. आपका बड़ा भारी तजुर्बा है, हर चीज का बड़ा भारी तजुर्बा है और चारों तरफ का बड़ा भारी तजुर्बा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बोलने के लिए समय दें, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सदन के हर सदस्य को बात कहने का अधिकार है। चेयर की तरफ से भी सभी सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, सभी सदस्यों को बोलने का पूरा अधिकार है और पूरा अधिकार मिल भी रहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के कितने सदस्य हैं, उन एक-एक सदस्य को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि आखिर वे भी तो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा अधिकार मिलेगा और मिल भी रहा है। Irrespective of the party, irrespective of the region and caste, every member has a right to speak and he will speak.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में अगर कोई गलत बात आती है तो आप उसको कटवा सकते हैं या बाद में बता सकते हैं। कल तो जब कोई भी सदस्य खड़ा होकर अपने प्वायंट ऑफ आर्डर की आड़ लेकर भाषण देना शुरू कर देता था तो आपने उस समय किसी को बीच में नहीं टोका, आपने उस समय किसी सदस्य को कुछ नहीं कहा। प्रस्तावक महोदय ने कितनी किस्म की गलत ब्यानी की लेकिन हम इसलिए सुनते रहे कि जब हमारे को बोलने का समय मिलेगा तो हम अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैंने तो हर सदस्य को प्वायंट आउट किया है कि आपको बोलते हुए 15-20 मिनट हो गये हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने इन 15-20 मिनट के समय में अपने हल्के की एक भी बात नहीं कही जबकि आप दो साल बाद इस सदन में आये हो। रोड़ी विधान सभा क्षेत्र के लोगों की क्या दो साल में कोई समस्या नहीं है जो आपने अभी तक नहीं उठाई है ? अगर आप कुछ और बात बोलना चाहते हैं तो आप अपने बजट भाषण में बोल लेना। अब आप बैठ जाईये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक हल्के की नहीं समूचे हरियाणा की बात कर रहा हूं। मैं गवर्नर एड्रैस पर ही बोलूंगा, यह मेरा अधिकार है और हम अपने अधिकार को हासिल करेंगे। आप तो अपने ब्यान से मुकरते जा रहे हैं आपने मुझे बोलने के लिए चौप्पन मिनट दिए थे। आप इस दौरान की विधान सभा की प्रोसिडिंग्स देख लीजिए कि मैं कितने समय बोल पाया हूं ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, उस समय आपने हमारे नेता को बोलने का समय ही नहीं दिया, बीच में दूसरे सदस्य इन्ट्रप्ट करते रहे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. इन्दौरा साहब, आपको देखना चाहिए कि आपके लीडर सदन में खड़े हैं। कम से कम इतनी तो इज्जत करो, आपको इतनी तो सैंस होनी चाहिए। चौधरी साहब, बोलिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चौप्पन मिनट बोलने का समय दिया था लेकिन मैं कितनी मिनट बोल पाया हूं यह आप चैक कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह चौप्पन क्या है ? 54 मिनट हैं न की चौप्पन।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इतने समय में से देख लीजिए कि मैं कितने समय बोला हूं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है कि मैंने कोई गलत बात कही है। स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बातें दोहराता हूं। अगर मेरी कल की बातों में कोई बात गलत हो तो आप उसे कन्डैम करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर है ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पढ़ा करते थे उस समय ये रेलगाड़ी में सफर करते हुए बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये थे और इनको जुर्माना देना पड़ा था। जब ये खेतों में पानी लगाते थे तो इन्होंने किसी दूसरे किसान के हिस्से का पानी काट लिया था तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद ये घड़ियों की चोरी में पकड़े गये। इन पर एक इल्जाम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन की वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे)

बैठक का स्थगन

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा और भी कई इल्जाम चौटाला साहब पर हैं जो मैंने सदन में नहीं बताये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। इस तरह से सदन की वैल में खड़े होकर नारे-बाजी न करें। (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग भी प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री ज्ञान चंद ओढ़ : अध्यक्ष महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री शाहीदा खान : अध्यक्ष महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, शाहीदा खान जी, रेखा राणा जी, सढौरा जी, प्लीज आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, ने चौटाला जी से कुछ जानकारी चाही है कि उन पर पानी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था या नहीं हुआ। उनको जवाब देना चाहिए। आप लोगों को इस तरह से सदन की वैल में खड़े होकर नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें क्योंकि आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ये लोग सदन की वैल में आकर सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल जी ने तो इनसे तीन बातें कहीं हैं कि बिना टिकट भौटाला जी ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े गये थे या नहीं, पानी की चोरी और घड़ियों की चोरी इन्होंने की थी या नहीं। ये लोग बे-वजह शोर क्यों मचा रहे हैं ? इनको दलाल साहब की बातों का जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (interruptions).

श्री ज्ञान चंद ओढ़ : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान

श्री शाहीदा खान : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप सभी सदन की कार्यवाही को चलने दें।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ये लोग इस तरह से सदन का समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे करेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि घड़ी चोर, पानी चोर और बिना टिकट सफर करने वाले लोग सदन में नहीं चलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, मेरा भी प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप लोग मेरी बात तो सुनें। मैं आपके हित की बात ही कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये लोग तो सही हैं लेकिन ये लोग भर्ती गलत जगह हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह बरवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी पवाइंट ऑफ आर्डर है। प्लीज, आप इन लोगों को अपनी-अपनी सीटों पर बैठायें। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से इनको सदन का समय बर्बाद करने का हक नहीं है। इस तरह का व्यवहार यहां करके ये क्या साबित करना चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। (शोर एवं व्यवधान) यदि आप इनको नेम कर देंगे तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। (शोर एवं व्यवधान) मुझे लगता है रात को इनकी खिंचाई ज्यादा हुई होगी इसलिए ये सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर * * * *

Mr. Speaker : Please take your seat. आपको बोलने का मौका दिया जायेगा, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर * * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर * * * *

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, इनमें से ज्यादातर तो बेचारे हरिजन भाई हैं । इनको हरिजन भाईयों की बात करनी चाहिए, बेकार की बहस में क्या रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठिये आपको बोलने का मौका मिलेगा। Please take your seat.

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर सर * * * *

श्रीमती रेखा राणा : स्पीकर सर * * * *

Mr. Speaker : Please take your seat. आपको बोलने का मौका दिया जायेगा आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

श्री रामफल चिड़ाना : स्पीकर सर * * * *

श्री ज्ञान चन्द ओढ : स्पीकर सर * * * *

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत मौका दे दिया है। अब श्री रामफल चिड़ाना गवर्नर डिस्कशन पर बोलेंगे। बोलिए चिड़ाना साहब। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छतरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दे दिया थे तब भी नहीं बैठ रहे, इस बात का क्या इलाज है ?

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, ये बेचारे कितने बदकिस्मत लोग हैं। ये ऐसे महकमे में दाखिल हो गये जो 10 हजार तो इनकी नौकरियाँ पी गया क्योंकि यह इनके समय में 10 हजार नौकरियों का बैकलॉग पी गया। जो एस०सी०बी०सी० की वैलफेयर का बजट था उसमें पहले कई करोड़ रुपये रखे हुये थे लेकिन मुख्य मंत्री बनते ही इन्होंने इसको घटा दिया। ये इनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। ये तो बहुत बदकिस्मत लोग हैं, एम०एल०ए० बनने के लिए ऐसे आदमी के साथ चले गये, इनको तो शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) आप का यह बिहेव ठीक नहीं है आप वैल में खड़े न हों और अपनी-अपनी सीटों पर जा कर बैठें। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, डॉक्टर साहब का सारा समय तो इनके नेता खा गए इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इनको बोलने के लिए समय दे दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) आपको बोलने का समय देंगे। Please take your seats. आपको बुलवाएंगे लेकिन आप अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप को बोलने का मौका देंगे लेकिन अभी आप अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी दरियादिली देखिये कि इनके इस प्रकार के व्यवहार के बावजूद भी आप इनको बुलवाना चाहते हैं लेकिन ये लोग हाउस की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दे रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप तो इनको बुलवाना चाहते हैं लेकिन ये लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। आप इनसे यह तो पूछें कि ये क्या चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपको बुलवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) Please take your seat. (Interruptions) आपको बुलवाएंगे, आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) ये लोग तो बन्धुआ हैं। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप देखें पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर खड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी) आप लोग अगर बन्धुआ नहीं हैं तो और क्या हैं ? (शोर एवं व्यवधान के साथ नारेबाजी)

Mr. Speaker : Now the House is adjourned for 5 minutes.

*11.25 hrs (The Sabha then *adjourned at 11.25 hours and reassembled at 11.30 hours.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नरज़ एड्रैस पर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : चौटाला जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार आई तो उस समय भी मैंने कहा था कि हम इस हाउस में सभी सदस्यों को बोलने का

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकार के वक्त में भी हाउस का सदस्य था और अपोजिशन का लीडर था। उस वक्त जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता था तो पांच मिनट के बाद इशारा कर दिया जाता था और मुझे बोलने नहीं दिया जाता था। उस वक्त चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामैंट में भी रहा हूं और मुझे पता है कि वहां पर किस तरह से कार्यवाही चलती है लेकिन मैं इनकी सब बातों को भूलकर सदन को आपकी इजाजत से अच्छी तरह से चलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर चौटाला साहब बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने का समय दें और जहां तक इनके बाकी सदस्यों का सम्बन्ध है तो यह आपने समय के अनुसार देखना है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप 10 मिनट में अपनी बात बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे 54 मिनट बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आप कल 1.30 घंटा बोले हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदन की प्रोसिडिंग्ज देख लें मैं कितनी देर बोला हूं। मुझे तो 5 मिनट का बोलने का समय मिला है। बाकी समय तो ये टोका-टाकी करते रहे हैं। यह सब तो रिकार्ड में आ जाता है। आप रिकार्ड चैक कर लें।

श्री अध्यक्ष : चलो, आप अपनी बात 15 मिनट में खत्म कर लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए बहुत समय चाहिए । एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा की जीवन रेखा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप इस प्वायंट को टच नहीं करें। यह मामला सब-ज्युडिस है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह मामला सब-ज्यूडिस नहीं है। इसमें तो केवल रैफरैंस दिए है।

Mr. Speaker : What is the definition of reference ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मेरी बात को सुन तो लें। पंजाब की सरकार ने 12 जुलाई, 2004 को जो जल समझौता निरस्त करने का ऐक्ट पास किया था उस बारे में केन्द्र सरकार ने उनसे रैफरैंस मांगा है। उनसे यह पूछा गया है कि क्या यह संवैधानिक है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि यह मामला सब-ज्यूडिस है कि नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं है।

Mr. Speaker : For the judgement of the Supreme Court, this case is pending.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह आपकी अपनी सरकार ने लिखा है S.C. has no jurisdiction over the water dispute. यह मैं नहीं कह रहा हूं यह हरियाणा सरकार कह रही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कहां से ले आए ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से भूल गए, हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब भी सदन में प्रवेश करें तो सत्य बोलना चाहिए। Supreme Court has the jurisdiction of everything. सच बात यह है कि एस०वाई०एल० कैनाल वाले मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनकी पार्टी पूरी तरह से दोषी है और इनको पता भी है। (विघ्न) इनकी आत्मा इनको अन्दर से दिन में भी और रात को भी कचौटती है। ये हरियाणा के किसानों के हितों पर कुठाराघात करते थे। जब पंजाब गवर्नमैंट ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट पंजाब की विधान सभा में पास किया था तो उस वक्त चौटाला साहब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने इस बारे में चुनौती क्यों नहीं दी थी ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई तो उसके बाद हम केन्द्र की सरकार के पास गए थे और उसके बाद ही यह मामला धारा 143 के अन्दर रैफरैंस में गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं और सदन में यह परिपाटी रही है कि जब भी कोई सदस्य प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा होता है तो दूसरे सदस्यों को सीट पर बैठ जाना चाहिए। अगर ये इस तरह से शोर शराबा करेंगे फिर तो सदन का समय नष्ट होगा ही। अगर आप बात कह रहे हैं तो आपके अंदर सुनने का भी माद्दा होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन की गरिमा रखी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने इन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इनके अपने नेता खड़े हों तो इनको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई प्वायंट ऑफ आर्डर हुआ है तो उनकी बात भी इनको सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस०वाई०एल० कैनाल का सवाल है मैं इस बारे में विपक्ष के कंस्ट्रक्टिव सुझावों का स्वागत करूंगा क्योंकि यह हमारे लिए जीवन रेखा है। अगर इस बारे में इनकी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैं भी जब विपक्ष का नेता था और जब ये प्रस्ताव लेकर आये थे तो उस समय भी मैंने कहा था कि आप इस मामले को लेकर जहां भी चलेंगे वहां हम आपके साथ चलेंगे और सबसे पहले कस्सी चलाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव ये लेकर आएंगे तो ये बोल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम जवाब देते वक्त उसका वाजिब जवाब भी इनको दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि खेतीबाड़ी तभी कामयाब हो सकती है जब उसके लिए पूरी बिजली मिले, पूरा पानी मिले, पूरा खाद मिले, अच्छे बीज मिले और अच्छे भाव मिलें। एस०वाई०एल० कैनाल हमारे लिए जीवन रेखा है उसके पानी की वजह से हमारे कृषि प्रधान प्रदेश की हालत सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन एक सम्मानित सदस्य ने तो यहां तक कहा था कि हमने इराडी ट्रिब्यूनल का विरोध किया था और उसको काले झंडे दिखाए थे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की ***** बातें इनको नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए क्योंकि यह शब्द अनपार्लियामैंट्री है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द बिल्कुल भी अनपार्लियामैंट्री नहीं है बल्कि यह शब्द पार्लियामैंट्री है। आप तो कम से कम इसकी स्टडी कर लिया करो। यह शब्द अनपार्लियामैंट्री बिल्कुल भी नहीं है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण (परिवहन मन्त्री द्वारा)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। सर, कल जो मैंने बात कही थी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसके बारे में ही जुड़ी हुई बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये अभी भी टीका टिप्पणी करेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अब ये बात नहीं सुनेंगे। इनको अब हमारी बात भी सुननी चाहिए। इनमें हमारी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अब ये छुपना क्यों चाहते हैं ? अब ये कुल्हड़ी के अंदर क्यों अपना मुंह देकर रोना चाहते हैं ?

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, अब ये किस तरह बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ये प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोल रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं। मैंने कल जो अपनी बात कहीं थी उसी से इन माननीय सदस्य की बात जुड़ी हुई है। स्पीकर सर, मुझे सदन के कानून के तहत, नियमों के तहत अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है। स्पीकर सर, मैं यह बात फिर सदन की जानकारी के लिए दोहराना चाहता हूं कि 24 मार्च, 1976 को इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिया था जिसके तहत 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया गया था। उस समय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आयी तो उस समय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। प्रकाश सिंह बादल की मदद करने के लिए इधर ये इस पूरे अवार्ड के मामले को न्यायालय में ले गये और उधर बादल साहब इसको न्यायालय में ले गए। जब इनकी सरकारें गयी तो 1981 में इंदिरा गांधी जी ने फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बुलाया क्योंकि वे उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और बुलाकर इनका समझौता करवाकर 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिलवाया। उसके बाद जुलाई, 1985 में राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ लेकिन इनके मित्र सरदार प्रकाश सिंह बादल ने उस समय मोर्चे लगाकर हमारी यह नहर नहीं बनने दी। इस काम में इनकी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सहमति थी। जब राजीव लौंगोवाल एकोर्ड में यह प्रावधान किया गया कि इराडी कमीशन का गठन होगा जो हरियाणा के पानी के हकों का निर्धारण करेगा और जब कांग्रेस की सरकार यह केस लड़ रही थी तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला और इनकी पार्टी ने इराडी कमीशन को जिसने हरियाणा को उसका हक दिया था, को साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी और उसको काले झंडे दिखाये थे। स्पीकर सर, इनको तो उस समय हरियाणा की कांग्रेस सरकार का समर्थन करना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि हम सारे भाई इस मामले में पार्टियों से ऊपर उठकर एक हैं और इस पानी पर हमारा हक है इसलिए आइये हम मिलकर यह पानी लेंगे। लेकिन ये पानी लेने के लिए नहीं गए क्योंकि इनको खतरा था कि अगर हरियाणा को पानी मिल गया तो इनकी वोटों की सस्ती राजनीति किस प्रकार से चलेगी ? स्पीकर सर, इराडी कमीशन ने हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया था। कल चौटाला साहब ने पहली बार यह बात मानी, चलो अच्छी बात है और मैं इसके लिए इनकी तारीफ भी करता हूं कि पहली बार इन्होंने जिंदगी में यह माना कि 24 मार्च, 1976 का अवार्ड श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कल इन्होंने यह भी स्वीकार किया हालांकि यह इन्होंने बड़े घबराते-घबराते हुए स्वीकार किया कि इन्होंने इराडी कमीशन को काले झंडे दिखाए थे और उसका विरोध किया था। स्पीकर सर, जून 1987 में इनकी सरकार बनी और पहले इनके पिता जी मुख्यमंत्री बने तथा उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। 1991 तक इनका शासन रहा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये क्या है, क्या यह इनका प्वायंट ऑफ आर्डर है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपनी बात कह रहा हूं। अगर बीच में सदस्य इस प्रकार से विरोध करेंगे तो यह सही नहीं होगा। अगर ये गलत बात बोलेंगे तो इन को सुननी भी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी आप जवाब दे सकते हैं। आप तो काफी तजुर्बेकार हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : जब भी इनके ढोल की पोल खुलती है तब-तब इनको तकलीफ होती है। 1987 में इन के पिताजी मुख्यमंत्री बने। बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाकर वे उपप्रधानमंत्री बने और श्री वर्मा को पंजाब का गवर्नर लगाया गया। 1987 से लेकर 1991 तक इनकी सरकार थी और इराडी कमीशन का फैसला 1986 में हमारे हक में आ गया था। अगर हरियाणा में इनको एस०वाई०एल० कैनाल का पानी लाना था तो उस समय ला सकते थे क्योंकि उस समय इनके पिता जी दिल्ली में उपप्रधान मंत्री थे, हरियाणा में इनकी सरकार थी और पंजाब में गवर्नर भी इनके थे लेकिन तब ये इसलिए सोये रहे कि कहीं बादल साहब के हितों पर कुठाराघात न हो जाए। 1995 में दोबारा कांग्रेस की सरकार ने इस बारे में मुकदमा दायर किया। ये उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा से एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का और वोट बटोरने का काम किया है। इनके हाथ तो किसानों के खून से रंगे हुए हैं। सर, आप रिकार्ड निकलवा कर दिखाइए, खुद चौटाला साहब ने माना है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सारी सीमाएं लांघकर कुछ लोग बात कर रहे हैं और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि आप भी उनको पूरी छूट दे रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब मैंने सारी बात ही तथ्यों के आधार पर कही है। आप सदन की कमेटी बनाइए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Indora, I warn you. (Noises & interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बात चल रही है उससे बिछुड़कर मुझे दूसरी बात कहनी पड़ती है। जो लोग अपने आपको हरियाणा प्रदेश का हमेशा हितैषी कहते हैं और दूसरों पर लांछन लगाते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं पंजाब के चुनाव में गया हुआ था। एक दिन मैंने वहां के दैनिक अखबार में छपी हुई जो खबर पढ़ी उसे मैं आपको भी पढ़कर सुनाता हूं। यह 9 फरवरी की बात है आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की स्टेटमैंट थी कि सानूं पाणी दी कोई लोड़ नहीं। ये बात इन्होंने बरेटा में कही है। यह आप रिकार्ड कर लें और मुझे भी यह अनुमति दें कि मैं इसे सदन की टेबल पर रखूं।

श्री अध्यक्ष : आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक अजीब इन्सान हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोल रहे हैं या और कुछ बात कह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पानी का मुद्दा चल रहा है माननीय सदन में कई माननीय सदस्य एस०वाई०एल० कैनाल की ठेकेदारी करते हैं। यह कहा गया कि हमारी सरकार द्वारा पानी की लड़ाई नहीं की गयी। माननीय सदस्य श्री रणदीप सुरजेवाला जी जब पंजाब के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट में वोट मांगने गये थे तब इन्होंने कहा था कि हमें पानी नहीं चाहिए। मेरे पास एक पंजाबी अखबार की कटिंग है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पानी नहीं चाहिए ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य सदन में झूठ बोलकर अपनी कही हुई सच्ची बात को छिपाना चाहते हैं। जब ढोल की पोल खुल रही है तो इनको ये बातें याद आती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है। फिर भी माननीय सदस्य बीच में टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपको गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया है और फिर भी आप सदन में कागज दिखा रहे हैं आपने यदि बोलना है और कुछ बात कहनी है तो आप अपने मुंह से बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन की वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे)

सदस्य का नाम लेना

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing to be recorded. (Interruption)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, please take your seat.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Sita Ram Ji, please take your seat.

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री ज्ञान चन्द ओढ़ : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji,I warn you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, I again warn you.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : I warn you Indora Ji. Please go to your seat, otherwise, I will have to name you.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, * * * * * * *

Mr. Speaker : I name Dr. Sushil Indora. He may please leave the House.

(Dr. Sushil Indora did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff took Dr. Sushil Indora out of the House.)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। आज वाकई में विपक्ष के साथियों ने जिस तरह का व्यवहार यहां सदन में किया वह प्रजातंत्र के इतिहास में बड़ा ही दुखद दिवस है। अध्यक्ष महोदय, आपने चौटाला जी को दोबारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और जिस तरह का व्यवहार यहां करके गये उसके बारे में सभी को मालूम है। स्पीकर सर, आपने दो बार सदन को एडजर्न किया लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने जिस तरह की अभद्र और गलत भाषा का प्रयोग सदन में किया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह सब उन लोगों ने अपनी सोची समझी बदनियती से किया और चेयर के प्रति बिलकुल भी आदर नहीं दिखाया। जैसे ही आज चौटाला जी सदन में आये उसके कुछ समय बाद वे अपने सभी मैंबरों को सदन के वेटिंग रूम में ले गये और सिखाकर लाये कि किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग सदन में करना है। इन सब बातों के बाद भी अध्यक्ष महोदय, आपने दो बार सदन को एडजर्न किया और जो भी प्रजातांत्रिक परम्पराएं हैं उनको निभाया लेकिन विपक्ष के साथियों ने उससे कोई सीख नहीं ली। वे बार-बार सदन की वैल में आकर नारेबाजी करते रहे। अध्यक्ष महोदय, चाहे पर्सनल एक्सपलेनेशन की बात हो या दूसरी कोई बात हो वे लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे और जब आपने सदन के नेता के आग्रह पर चौटाला जी को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दोबारा बोलने के लिए समय दिया तो भी वे नहीं बोले। स्पीकर सर, चौटाला साहब जाते-जाते ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए, जो अशोभनीय हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जायें।

श्री अध्यक्ष : वे शब्द उसी समय रिकार्ड से निकलवा दिए थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब इस तरह के शब्द इसलिए बोल गये कि वे भूल गये थे कि अब वे सत्तापक्ष में नहीं हैं। जिस समय वे सत्तापक्ष में थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वे प्रजातांत्रिक परम्पराओं को निभायें, परिपाटी को निभायें लेकिन उस समय भी वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अतिरिक्त वे ये शब्द भी कहा करते थे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हरियाणा के लोगों ने उन्हें नकार दिया है और इस तरह नकारा है कि वे विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं रहे। उनके सदन में इस तरह के व्यवहार के बावजूद भी

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

स्पीकर सर, आपने यह निर्णय लिया कि न केवल चौटाला जी को बोलने के लिए 15 मिनट और दिए जायेंगे बल्कि दूसरे विधायकों को भी 7-7 मिनट का समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए दिया जायेगा। यह समय उनके अलोटिड समय से तीन गुणा ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, आपने उनके एक सदस्य को नेम किया था लेकिन वे सारे के सारे ही चले गये। आपने तो चौटाला जी को समय इसलिए दिया था कि वे अपने ढोल की पोल यहां खोलने वाले थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोलते तो तब जब उनके पास बोलने के लिए कुछ होता। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा लोकदल के भाईयों में प्रजातंत्र के प्रति विश्वास ही नहीं है और पहले भी कभी नहीं रहा। यह बात पूरे हरियाणा की जनता भी जानती है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का व्यवहार वे यहां करके सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं वे इतना भी नहीं सोचते कि हरियाणा की जनता का कितना पैसा सदन चलने पर खर्च हो रहा है। कम से कम इस बारे में तो वे सोचें। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में बताया था कि छात्राएं जो हमारे देश की अगली पीढ़ी हैं वे भी यहां मौजूद हैं उनमें क्या इम्प्रैशन इस तरह के विपक्ष के व्यवहार का जायेगा। लोकदल के सदस्य इस सदन का हिस्सा हैं उनको भी कभी न कभी अपने अंतर मन की बात सुननी चाहिए और सदन में जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वह नहीं करना चाहिए था तथा सदन की जो परम्पराएं और परिपाटियां बनी हुई हैं उनका निर्वहन करना चाहिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब नरेश मलिक जी गवर्नरज़ ऐड्रेस पर बोलेंगे।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात है कि ओम प्रकाश चौटाला दो साल बाद सदन में आया और अपनी बात पूरी किए बगैर ही सदन से चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कभी सत्तापक्ष का विधायक नहीं रहा। हमें उम्मीद थी कि चौटाला जी ने 5-6 साल से प्रदेश पर राज किया है इसलिए 2 साल की सरकार की खामियों को, कारगुजारियों को वे हमारे सामने लायेंगे लेकिन बड़े दुख की बात है कि केवल सदन का समय खराब करने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सर, हम सत्ता पक्ष से भी यह उम्मीद करते हैं कि अगर विपक्ष सुझाव दे, हो सकता है हम किसी व्यक्ति के बारे में, पब्लिक हित में कोई बात करें तो सरकार का और माननीय सदस्यों का फर्ज है कि वह उसे सुनें। अगर कोई गलत बात हो तो वह अपने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी बात कह सकता है और अपना जवाब दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : हमने तो वही किया था।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के ऊपर कुछ बातें हमारी समझ से बाहर की हैं। मुख्य मंत्री जी ने सिरसा के अन्दर एक रैली की थी, माननीया श्रीमती सोनिया गाँधी जो यू०पी०ए० की चेयरपर्सन हैं वे भी इसमें आई थीं। उस समय पूरे प्रदेश ने टी०वी० पर देखा और मैं भी देख रहा था उस समय इन्होंने लगभग 770 करोड़ रुपये के ऋण के ब्याज की माफी की बात की थी लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया कि आज तक का ऋण कितना है। अगर 770 करोड़ रुपये ऋण है तो उसकी रूपरेखा तो होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वह बात बजट में आयेगी।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार ने पहले 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की थी। मैं खेद के साथ केवल मुख्य मंत्री के गांव की, मुख्य मंत्री के हल्के की, उनके विशिष्ट क्षेत्र की ही बात बता रहा हूँ। यह बात मेरी नहीं बल्कि 10 मार्च, 2007 के दैनिक भास्कर के रोहतक परिशिष्ट में लिखी थी कि किलोई, जो इस समय मुख्यमंत्री जी का हल्का है वहाँ पर 24 करोड़ रुपये यानि 89 प्रतिशत लोगों पर आज भी बकाया है। गाँव सांघी जो कि मुख्यमंत्री जी का गाँव है, पर 16 करोड़ रुपये यानि 70 प्रतिशत लोगों पर आज भी बकाया है। गाँव धामड़ में 12 करोड़ रुपये जो कि 85 प्रतिशत है, आज भी लोगों पर बकाया है। गाँव खिडवाली में 8 करोड़ रुपये यानि 73 प्रतिशत है, बकाया है, रुड़की में 8 करोड़ रुपये जो कि 62 प्रतिशत है लोगों पर आज भी बाकी है। सरकार कहती है कि हमने 1600 करोड़ रुपये माफ कर दिये। मैं मुख्यमंत्री के गाँव और हल्के की बात कर रहा हूँ मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ। यह 10 मार्च के दैनिक भास्कर अखबार की स्टेटमैंट है। सरकार कहती है कि हमने सारे कर्जे माफ कर दिये और हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं यह कह रहा था कि बिजली की घोषणा का जो हाल हुआ है कहीं वही हाल ब्याज मुआफी का भी तो नहीं होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका भी वही हश्र होगा ? मुख्यमन्त्री जी के हल्के किलोई के गांवों की बात मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में एक बात आई कि हमने सड़कें बहुत ही अच्छी कर दी। मैं भी मानता हूं कि रोडज़ में बहुत तरक्की हुई है, अच्छा काम हुआ है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि हमने ऐजुकेशन बहुत बढ़िया कर दी, बिजली भी बढ़ा दी है यानि हरेक सैक्टर में सुधार कर दिया है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह कहा गया है कि हर चीज में सुधार हुआ है लेकिन अगर कानून-व्यवस्था की बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने एक दिन अखबार उठाया तो लिखा था कि एम०एल०ए० की लाल बत्ती की गाड़ी चोरी, एक एम०एल०ए० के लड़के का अपहरण किया गया, उससे मारपीट की गई। स्पीकर साहब, यह बात मैं नहीं कहता। उसी सेम डे रोहतक के जिला पार्षद पर चाकुओं से हमला किया गया। इससे कुछ दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बलियाना के सरपंच पर गोलियां दाग दी गईं। अगर गुड़गांव के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति देखें तो 23-24 मर्डरज़ हुए और उसमें कई कत्ल तो मात्र 100-150 रुपये के कारण हुए। आम आदमी के मर्डर केवल इसलिए ही कर दिए गए। इसलिए कानून-व्यवस्था की जो बात हम कर रहे हैं वह सही नहीं है क्योंकि लोगों को सरकार की तरफ से कोई भय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप अभिभाषण के फैक्ट्स पर बोलें।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, मैं फैक्ट्स ही ब्यान कर रहा हूं, 23-24 मर्डरज़ हुए हैं और कई मर्डरज ऐसे हुए हैं जो मात्र 200-250 रुपये के लिए हुए हैं इन्हें चेन किलर कहते हैं ये 22-23 मर्डरज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, क्या ये सारे कत्ल एक ही दिन में हो गए हैं क्योंकि आपने कहा है कि मैंने एक दिन अखबार उठाया, क्या ये सारे मर्डरज़ उसी दिन हुए थे ?

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, एक एम०एल०ए० की गाड़ी चोरी हो गई, क्या गाड़ी चोरी हुई या नहीं हुई, क्या एम०एल०ए० के लड़के के साथ मार-पीट नहीं हुई, क्या उसने गलत

रिपोर्ट दर्ज करवाई ? मैं यह सारी बातें जो हाउस के अन्दर बता रहा हूं ये सारी बातें पेपर में लिखी है इसलिए मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, रोहतक के अन्दर चाकूबाजी हुई थी नहीं हुई, उसकी एफ०आई०आर० दर्ज हुई कि नहीं हुई, बलियाना के सरपंच पर गोली चली कि नहीं चली ? अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था का एक तरह से दिवाला पिटता जा रहा है। कहीं उग्रवादी अरैस्ट हो रहे हैं और कहीं आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं और मुझे पता है कि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, क्या आप ज्योतिष का काम भी करते हैं ?

श्री नरेश मलिक : थोड़ा-थोड़ा सीख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ज्योतिष दो तरह का होता है एक अच्छे वाला और एक भौंडे वाला, अगर सीखना ही है तो अच्छे वाला ज्योतिष ही सीखना! अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं अब स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बहन जी, यहां पर बैठी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर गए थे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मेरे सुनने में आया है कि बहन जी का गांव क्रोंधा है। वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक ही परिवार के 6 सदस्य मारे गए और एक आध परिवार का तो नामों-निशान ही मिट गया। खेद की बात है कि मैडीकल कॉलेज, रोहतक के अन्दर चार आदमी 24 से 36 घण्टे तक बेहोश पड़े रहे लेकिन उनकी एम०आर०आई० नहीं हुई क्योंकि होस्पीटल की एम०आर०आई० मशीनें ठीक नहीं थीं, न ही वहां पर न्यूरोसर्जन था। मैं रोहतक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मुख्यमन्त्री जी का गृहजिला है। बहन जी, मैंने खुद डायरैक्टर के पास जा कर पूछा था तो उसने बताया कि वहां पर दो मशीनें हैं और दोनों ही मशीनें खराब हैं। सी०टी० स्कैन मशीन भी खराब है। जिनका एक्सीडैंट हुआ था उनको वहां से एक पैसे की भी दवाई नहीं मिली थी। अस्पताल के बाहर रैडक्रॉस की दुकान से इन घायलों को दवाई दिलवाई गई। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बी०पी०एल० कार्ड की बात करता हूं। पिछली सरकार इस मामले में काफी तेज थी जब कि यह सरकार बहुत ही लेट-लतीफी से चलने वाली सरकार है। आप याद करें, दो साल पहले इस हाउस में यह कहा गया था कि बी०पी०एल० कार्ड का सर्वे दोबारा होना चाहिए लेकिन दो साल के बाद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी हाउस में आ गए हैं मैं उनका ध्यान क्रोंधा गांव में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमन्त्री वहां पर नियमों के तहत दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा करके आए थे। वे बेचारे इतने दिनों से यहां वहां घूम रहे हैं मुझे पता नहीं कि उनको वह पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे जिले की हालत है। हर चीज में तो तरक्की हो रही है लेकिन पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों है। दो साल पहले मैंने अपने हल्के में पीने का पानी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था। मन्त्री महोदय, मैं खुद दस रुपये की पानी की केन ले कर पानी पीता हूं। पौने दो साल हो गए हैं आज भी सांपला में मैं मोल लेकर पानी पीता हूं। (विघ्न) जब तक वहां पर कड़वा पानी आएगा और जब तक आप साफ पानी नहीं देंगे तो आप ही बताएं कि मैं पानी कहां से पीऊं ? अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस सरकार ने 25-30 गांवों में पानी बढ़ाने के लिए 3 इंच की पाईप लगवाई थीं। लेकिन वहां पर रोड़ पड़ने की वजह से वे पाईप्स दबकर टूट गई जब हमने इस बारे में अधिकारियों से पूछा तो वे कहने लगे कि ये पाईप्स घटिया किस्म की आ गई थीं इसलिए हमने सारा माल वापिस कर दिया है और नई अच्छी पाईप्स मंगवाई हैं। लेकिन

[श्री नरेश मलिक]

अध्यक्ष महोदय, जो पाईप्स दोबारा डाली गई थीं वे भी कुछ समय बाद टूट गई थीं और आज वहां पर पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है । मैं यह बात मुख्यमंत्री जी के जिले की बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने यहां पर बोलते हुए कहा कि वे 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हैं। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आप अच्छी बात कर रहे हैं और अगर आपको बिजली 8 रुपए के हिसाब से भी मिले तो आप लें और किसानों तथा उद्योगों को बिजली दें। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 13 नम्बर में जो कहा गया है, उस बारे में अगर मैं सदन में चर्चा न करूं तो ठीक न होगा। इसमें कहा गया है कि "मेरी सरकार सतलुज यमुना योजक नहर के माध्यम से रावी ब्यास के पानी का हरियाणा का पूरा हिस्सा लेने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती है।" अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह तो इन्होंने ही कहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि आज तक बहुत से लोगों ने इस बारे में राजनीतिक रोटियां सेकी हैं लेकिन आने वाले समय ऐसा नहीं होगा कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। चाहे कांग्रेस पार्टी, बी०जे०पी० या इनैलो पार्टी ही क्यों न हो। अब इसमें वोट की राजनीति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी हाउस में यह बात कही थी कि जिस तरह से पंजाब ने हमारे साथ नाइन्साफी की है तो उसी तरह से हमें भी सदन में कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बारे में यह कहा गया है कि हम एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में गम्भीर नहीं हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 15-12-2002 को फैसला हुआ था कि एक साल के अन्दर पंजाब सरकार इस नहर को बनाएगी और अगर पंजाब सरकार नहीं बनवाती है तो उसके बाद 15-1-2003 से केन्द्र की सरकार उसको अपनी एजैंसी के थ्रू बनवाएगी। उस वक्त केन्द्र में बी०जे०पी० की सरकार थी लेकिन इनकी पार्टी की सरकार ने भी यह नहर नहीं बनवाई। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने ही सी०पी०डब्ल्यू०डी० को उसका काम सौंपा था। हम तो सीरियस हैं लेकिन आपकी गवर्नमैंट ही इस बारे में सीरियस नहीं थी।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साल का समय पंजाब सरकार को दिया था और अगर पंजाब सरकार एक साल में नहीं बनवाएगी तो उसको केन्द्र की सरकार बनवाएगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है कि जब पंजाब सरकार ने समझौता रद्द किया था तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने उस समझौते को रद्द करने की सबसे पहले निन्दा की थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई काम नहीं किया लेकिन जब हमारी सरकार आयी थी तभी इसका काम सी०पी०डब्ल्यू०डी० को दिया गया था। स्पीकर सर, इनकी एन०डी०ए० की सरकार भी केन्द्र में रही लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने गांवों के विकास की भी घोषणा की है और कहा है कि हर गांव का हुडा की तर्ज पर विकास किया जाएगा। मुझे उनकी इस बात पर खुशी है। अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 50-55 लाख रुपये के ऐस्टीमेट्स बनाकर गांवों के विकास के लिए दिए थे। लेकिन इसमें चार गलियों को बनाने के लिए ही पैसा गया। ऐस्टीमेट्स तो पूरी

गलियों के बने लेकिन हुआ कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भ्रष्टाचार की बात बताता हूं। ये गलियां आधी अधूरी ही बनायी गयी। 18 फुट बनाने की इनकी पैमाइश हुई थी लेकिन बनायी 12 फुट की ही गयीं। अगर एक हजार मीटर तक गली बननी थी तो बनी सिर्फ 500 मीटर तक ही। मैंने डायरैक्टर, पंचायत को इस बारे में चिट्ठी लिखी और डी०सी०,रोहतक को भी कहा लेकिन उन्होंने कह दिया कि मलिक साहब, जे०ई० हमारे वश में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितनी कंक्रीट की गली बनी हैं या जो स्कूल के कमरे बने हैं अगर उनमें से एक के भी सैम्पल ठीक आ जाएं तो आप बता देना। मैं सदन के सामने इस बात को लेकर चैलैंज करता हूं। आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए आपको वहां पर रेती ही लगती हुई मिलेगी। सरकार ने पंचायत को बाउंड कर दिया है कि उनको तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं देंगे। सारा फंड्ज ठेकेदार के माध्यम से जा रहा है। मैंने ठेकेदार से भी इस बारे में पूछा था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस्माइलाबाद गांव के अंदर स्वयं जाकर देखा था और इसके बारे में डी०सी०, रोहतक को भी बताया था और कहा था कि आप क्यों नहीं ठीक काम करते ? अध्यक्ष महोदय, इत्तिफाक से मैं वहां से सीमेंट का एक कट्टा भी भरकर लाया था।

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) : Speaker Sir, I would like to know from the Hon'ble member as to which room and in which school the material is not up to the mark ? He is just misleading the house and making false allegation against the government. Everything is being checked if you point any draw back. You can bring it to the notice we will get it checked.

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपको बोलते हुए 14 मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप कंक्लूड करें।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर सर, मैं इस्माइलाबाद गांव की बात कर रहा हूं। उस समय वहां पर पूरा गांव मौजूद था। आप चाहें तो वहां का सैम्पल भरवा सकते हैं। इसी तरह से आप करौंथा, खेड़ी सांपला गांवों के अंदर भी चले जाइये वहां पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि गली तो बना दी लेकिन उसके साथ ही जो एक-एक फुट के नाले बनने थे, वह नहीं बनाएं। चूंकि मैं अपोजीशन का एम०एल०ए० हूं इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह हल्का मेरे से ज्यादा तो मुख्यमंत्री जी का एरिया है। इसी तरह से वहां पर बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गयी। इसको बनाने के लिए वहां पर पंचायत करोड़ों रुपये की जमीन क्यों दे ? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब बता दें कि पंचायत दो करोड़ रुपये की जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए क्यों दे, क्या रोड़वेज अपना व्यवसाय नहीं करती ? रोड़वेज को अगर हम दो करोड़ रुपये की जमीन देंगे तो क्या तभी वहां पर हमारा बस स्टैंड बनेगा ? आप 60-60 लाख, 40-40 लाख या 30-30 लाख रुपये की बसिज तो खरीदते हैं लेकिन यदि हम दो करोड़ रुपये की जमीन देंगे क्या तब ही आप हमारा बस स्टैंड बनवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। आप तो सयाने आदमी हैं इसलिए आप सयानी बात करें।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मै एक सयानी बात कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरी यह बात हाउस के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की व्यवस्था के लिए भी है। हमारी

[श्री नरेश मलिक]

एक बहन ने बोलते हुए बार-बार कहा कि पहले अनपढ़ आदमी यहां के मुख्यमंत्री और एम०एल०ए० थे जबकि हमारी पढ़ी लिखी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। क्या अनपढ़ आदमियों के इनको वोट नहीं चाहिए क्या केवल पढ़े लिखें आदमियों के ही इनको वोट चाहिएं ? क्या यह उन आदमियों का अपमान नहीं है ? अनपढ़ भी तो वोटर हैं इसलिए अनपढ़ एम०एल०ए० भी हो सकते हैं क्योंकि उनको लोगों ने चुना है। लेकिन बार-बार यह कहना कि हमारी पढ़ी लिखी सरकार है, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि अनपढ़ आदमी को भी वोट देने का अधिकार है। क्या कानून के तहत अनपढ़ आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है ? इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाना सदन की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। यहां पर यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी को पंजाब के मुख्यमंत्री ने तलवार दी। बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको सही तरह से यूज करना नहीं तो वे आपको चलाना सिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कहता। मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप अब कंक्लूड करें। आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गये हैं। आप अपने वायदे के हिसाब से ही चलें।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो इनको तलवार दी है उसको ये देखकर ही चलाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० छतर पाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, आपको बोलने के लिए दस मिनट का समय दिया जाता है।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो एक-एक शब्द से हरियाणा की जनता को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : यदि इतने ही इम्पोर्टेंट सुझाव हैं तो आप लिखकर भिजवा दें। सरकार उन पर जरूर गौर करेगी। आप दस मिनट में कंक्लूड कर दें।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल से जो यहां पर माहौल बना हुआ है वह बहुत ही चिंता का विषय है। जब ये लोग जो आज विपक्ष में बैठे हैं जो कि अपनी पूरी संख्या में भी नहीं हैं, दुर्भाग्य से जब इनको हरियाणा की जनता को सत्तापक्ष में फेस करना पड़ा था तब ये लोग अपनी पूरी मनमानी करते थे और लोगों पर जुल्म ढाने के फैसले यहां पर लिया करते थे लेकिन आज विपक्ष में बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। सर, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और जनता के लिए अच्छे फैसले लेना चाहती है और समय का सदुपयोग करना चाहती है। वह यह चाहती है कि हरियाणा में विकास हो और उसका फायदा हरियाणा की जनता को हो तथा हरियाणा के नौजवानों के चेहरे पर रंगत आए। यदि उनकी बात में कोई गहराई रही होती और यदि वे कोई और बैटर सुझाव देते तो अच्छा रहता। हरियाणा सरकार के तो दरवाजे सदा खुले हैं। जो फैसले इन दो सालों में हरियाणा सरकार ने लिए हैं।

जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में भी है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनंद सिंह डांगी चेयर पर पदासीन हुए।) सभापति महोदय, दाद देने वाली बात यह है कि हरियाणा के देहात को दिमाग में रखकर, हरियाणा के शहरों को दिमाग में रखकर, हरियाणा के गरीब लोगों को दिमाग में रखकर विकास की राह पर लाने के लिए किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वे बातें जेहन में रखकर ही हमारी सरकार ने ये फैसले लिए हैं। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार के चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हैं। वे 36 बिरादरियों को, हर धर्म को, हर मजहब को समान अधिकार देकर और मायनौरिटी को ध्यान में रखकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, देश को और प्रान्त को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी यहां पर किसान की बात की गयी। यहां पर काफी बहस छिड़ी कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। लेकिन किसानों की हितैषी तो यह सरकार है जिसने सबसे पहले किसानों की भलाई के फैसले लिये। बहुत लम्बे अर्से से यह बात तय हो चुकी है कि हरियाणा की जिम्मेदार पार्टियों ने बिजली के बिल माफ करने का नारा देकर, लालच देकर सत्ता को हथियाने का काम किया जिसके कारण वह जमींदार आज उस पैसे को भरने में असमर्थ है। हरियाणा की सरकार ने किसानों के उस बोझ को समझते हुए 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए। यह एक अमन और चैन की बात है। जबकि इनैलो पार्टी ने उनको गलत शिक्षा देकर सत्ता हथियाने का काम किया। उसके जवाब में, उस पैसे की रिकवरी के लिए उन्होंने पुलिस का दवाब दिया। हर महकमे में कोई भी काम होता था तो पहले किसान से बिजली के बिल का पैसा भरने की रसीद देखी जाती थी उसके बाद ही कोई काम हो पाता था। पहले तो ये किसानों को गलत आदत डालकर उनको लालच देते हैं और फिर सत्ता हथियाने के बाद उन पर उस पैसे को वसूल करने के लिए दबाव डालते हैं। सत्ता हथियाने बदले किसानों की हत्या करने से भी यह बाज नहीं आये। लेकिन यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है। चेयरमैन सर, इसी बात की नाजुकता को समझते हुए इस सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं दे पा रहा है तो उस व्यक्ति को कम से कम सरकार की पुलिस नहीं पकड़ेगी, न ही किसी किसान को लोन न देने की सूरत में उसको जेल में डाला जायेगा। यह फैसला साबित करता है कि किसानों के दर्द को यह सरकार ही समझती है। चेयरमैन सर, आपको मालूम है कि किस तरह से पिछली सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी कि किसानों के ऋण माफ किए जायेंगे लेकिन किया कुछ नहीं जबकि वर्तमान सरकार ने पहले कोई वायदा नहीं किया था कि कोई ऋण माफ किया जायेगा। इनैलो पार्टी ने तो देश की उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद भी सिर्फ कोआप्रेटिव बैंक के जो दस हजार तक के लोन माफ किए थे वह तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात थी। जबकि इस सरकार ने कभी कोई वायदा नहीं किया कि हम किसानों के लोन माफ करेंगे लेकिन फिर भी किसानों के लोन माफ किए, बिजली के बिल माफ किए। वर्तमान सरकार ने इस बात को जहन में लेते हुए किसान और मजदूर जो रोजी-रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है, अपने घर को चलाने में असमर्थ है जिसने 50 हजार रुपये लोन लिया था, आज वह लोन डेढ़ लाख या दो लाख, दो गुणा या तीन गुणा हो चुका है, यानी उन किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा है के बारे में फैसला लिया। इस संवेदनशील कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने श्रीमती सोनिया गांधी की मन्शा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया कि एक निश्चित तारीख तक अगर वे अपना मूल पैसा जमा करा देते हैं तो उनका ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इसका मतलब यह है कि इस सरकार ने उन किसानों को एक टैरिफ दिया है। उनको यह

[प्रो० छतर पाल सिंह]

कहा कि इस समय तक कर्जे की अदायगी करेंगे तो उनको यह छूट मिलती चली जायेगी। इससे किसान काफी प्रोत्साहित हुए और उनकी तरफ से पैसा भी आना शुरु हो गया है। अब किसानों का लोन का काफी बोझ भी इससे हल्का हो जायेगा और सरकार की रिकवरी भी हो जायेगी। जो किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग हैं उनको इस फैसले से काफी राहत मिली है। सर, इसके बारे में इस सरकार ने कभी कोई वायदा नहीं किया था लेकिन इसके बावजूद सारी व्यवस्था को देखते हुए, सरकार ने अपनी माली हालत को देखते हुए किसानों, मजदूरों, कमजोर वर्गों और दुकानदारों और छोटे वर्ग के पक्ष में फैसला किया है। सभापति महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। हमारी सरकार हांसी-बुटाना लिंक नहर बनाने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो खाले 25-30 साल पहले बने थे जिनकी अब तक न सफाई हुई थी, न मरम्मत हुई थी लेकिन अब हमारी सरकार उनकी सफाई और मरम्मत का काम करवा रही है। इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे प्रधान मंत्री डॉ० मन मोहन सिंह जी से और सोनिया गांधी जी से अनुरोध करें कि हमारे प्रदेश में यमुना पर बांध बनवाया जाये ताकि उसमें पानी एकत्रित करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। सभापति महोदय अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के बारे में जो फैसले लिये हैं वे बड़े ही सराहनीय फैसले हैं। सभापति महोदय, जब मैं टैक्नीकल एजूकेशन का वजीर था उस समय मैंने 24 पेज की रिकमंडेशन की बुक लिखी थी। जिसमें रोजगार देने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त साईंस एंड टैक्नालोजी में बहुत बड़ा कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। सभापति महोदय, खानपुर को महिला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करके हमने महिलाओं को पूरी शिक्षा देने का काम किया है। देश और प्रदेश के हर नागरिक का 100 प्रतिशत हक है कि उसे पूर्ण शिक्षा मिले। प्रदेश के सभी नागरिकों को पूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया है और जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं थे उन स्कूलों में अतिथि अध्यापकों की भर्ती भी की गई है। सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने जो मॉडल स्कूल बनाये हैं उन्हीं की तर्ज पर हरियाणा के हर सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि हमारे स्कूलों के परिणाम इतने बेहतर हो जितने प्राईवेट स्कूलों के हैं। सभापति महोदय, बिजली के बारे में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए एक लाईन शुरू की थी। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1200 मैगावाट की बिजली का प्लांट मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव खेदड़ में लगाने के बारे में फैसला लिया गया था। सभापति महोदय, उस समय आप और मैं वजीर हुआ करते थे। उसके बाद दो सरकारें आई और चली गई। एक तो माननीय चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई और दूसरी चौटाला जी की सरकार आई लेकिन उस 1200 मैगावाट के प्लांट पर एक ईंट रखने का कार्य भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके प्रयासों से 36 महीनों के अंदर-अंदर वह 1200 मैगावाट का थर्मल प्लांट प्रोडैक्शन करना शुरू कर देगा क्योंकि अब इस पर इस समय काम चल रहा है। इस तरह से हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए हैं। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 3500 रुपये मिनीमम वेजिज गरीबों के लिए लागू किए हैं। यह बात हमारी सरकार की गरीब और छोटे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को जाहिर करती है। सभापति महोदय, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था उन कर्मचारियों को हमने दोबारा से नौकरियां दी हैं। यह बात हमारी सरकार के प्रेम और आस्था को जाहिर करती है और उनसे यह अपेक्षा

रखती है कि ये कर्मचारी बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। पिछली सरकार ने तो एक कलम से उनको नौकरी से निकाल दिया था। सभापति महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी के पिता श्री ने जितने भी कार्यक्रम चलाये उसका फायदा चौटाला जी ने इस बात के बावजूद ले लिया कि उन्होंने अपना बेटा होने के बावजूद चौटाला को बेटा मानने से मना कर दिया था। इस बात के बारे में कल विस्तार से माननीय सदस्य राम कुमार गौतम जी ने बताया था। मुझे कल शाम से एक चिन्ता सता रही थी कि एक तरफ तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा नहीं है और दूसरी तरफ सत्ता का सारा फायदा उसे मिलता चला गया और हरियाणा की जनता को तमाम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ी क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत ही क्रूर फैसले हरियाणा के अन्दर लिये। चेयरमैन सर, जब ये सिरसा में ताश खेलते थे तो इनको हेराफेरी करने की आदत थी। इसी बात से तंग आकर क्लब वालों ने इसकी एन्टारी बन्द कर दी थी। चेयरमैन सर, ये इतनी कंजूसी के साथ चलते थे।

श्री सभापति : प्रोफैसर साहब, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वह आदमी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ऐसी बातें कहने का कोई तुक नहीं है। आपका समय समाप्त हो रहा है आप बैठ जाईये।

प्रो० छतर पाल सिंह : सर, मुझे थोड़ा समय और दीजिए ताकि मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर सकूं। चेयरमैन सर, मैं जो बात कह रहा था उसको पूरा जरूर करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : ठीक है, दो मिनट में आप अपनी बात को पूरा कीजिए।

प्रो० छतरपाल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं जो बात कह रहा था ये तो चौटाला साहब ही बता सकते हैं कि यह मजाक है या सत्यता है। आज तो वे आये नहीं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वे कल इन बातों का स्पष्टीकरण जरूर देंगे। वे उन बातों को एडमिट भी करते हैं क्योंकि उन्होंने उन बातों को छोड़कर दूसरी बातों को शुरू कर दिया। जो आदमी मौजूद हैं उसको पर्सनल एक्सपलेनेशन जरूर करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब चौटाला जी रिक्शा में बैठकर जाते थे तो किसी के साथ बैठकर जाते थे ताकि थोड़े पैसों में बस स्टैण्ड या रैस्ट हाऊस पहुंच जायें। एक दिन ये अकेले रिक्शा में बैठे जा रहे थे तो इनकी पार्टी के किसी साथी ने पूछ लिया कि ओमप्रकाश जी आज तो शालम रिक्शा कर रखी है किल हाथ मार रहे हो ? शालम का मतलब हरियाणा में अपनी अलग से करना होता है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस माली हालत के अन्दर इतना इजाफा कैसे हो गया ? यदि पिछले 5-6 साल इनकी सरकार न रही होती तो इतना इजाफा उस माली हालत में नहीं होता। हरियाणा के लोगों को यदि बहकाया नहीं जाता, देश के उप-प्रधानमंत्री का ओहदा इनके पिताश्री को नहीं मिलता तो इस माली हालत में इतना इजाफा नहीं होता। चौधरी देवी लाल के नाम से जो ट्रस्ट इन्होंने बनाये हैं पूरे हरियाणा के अन्दर आज उन्हीं ट्रस्टों में इंडियन नैशनल लोकदल के दफ्तर चलने लग गये हैं। करोड़ों रुपये इन्होंने बना रखे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि ट्रस्ट के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है तो इस सदन में इस बात का हिसाब होना चाहिए कि पिछले 10 सालों के अन्दर, जब से यह ट्रस्ट बना है इनकी सरकार रहते उस ट्रस्ट में कितना पैसा आया और यह सरकार आने के बाद इन दो साल के अन्दर कितना पैसा ट्रस्ट में आया है ? हम हरियाणा की जनता के सामने यह बात स्पष्ट करेंगे कि उस ट्रस्ट में सरकार की फाईलों के माध्यम से जो काला पैसा, जो घूस का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा आता

[प्रो० छतर पाल सिंह]

था, वह ट्रस्ट के माध्यम से फेयर करने का प्रयास किया जाता था। यदि आज भी उतनी श्रद्धा लोगों के अन्दर उस ट्रस्ट के प्रति है तो फिर इन दो सालों में उतना पैसा क्यों नहीं आया ? यदि कोई ट्रस्ट बेईमानी की नीयत से बनाया जाता है तो सरकार को उसको टेकओवर करना चाहिए। ये जो ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक अखाड़े शहरों के अन्दर बना रखे हैं जिला मुख्यालय के ऊपर बना रखे हैं इनके ऊपर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। चेयरमैन सर, आज इस बात की आवश्यकता है कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक प्रतिनिधि ईमानदारी से कार्य करें, संवेदनशीलता के साथ काम करें, जिम्मेवारी को महसूस करके काम करें ताकि हरियाणा की जनता का भला हो सके। चेयरमैन सर, मुझे अच्छी तरह से याद है हालाँकि चौ० देवीलाल जी आज स्वर्ग में हैं वे यह बात कहा करते थे कि काम करने से सत्ता नहीं मिलती, नौकरियाँ लगाने से सत्ता नहीं मिलती बल्कि लोगों की नब्ज को पढ़ो और लोगों की नब्ज को पकड़ो तथा वही नारा दो ताकि लोग भावुकता में आपको सत्ता में ले जायें। लेकिन अब इनको भुगलनी पड़ रही है और आगे भी ये भुगतेंगे। गरीब, कमजोर मजदूर और किसान हरियाणा के अनपढ़ और भोले लोगों की कमजोरी की, अनपढ़ता की नब्ज को पकड़ करके भावावेश में बहाकर उसके वोट के साथ ठगी करके सत्ता पाना और फिर उनके ऊपर लाठी और गोलियाँ चलवाना और उसी सत्ता का सारा सदुपयोग अपने परिवार के पक्ष में करना क्या यह सही था ? यह देखने वाली बात है कि कितना बड़ा दुरुपयोग यह बनता है, कितना बड़ा ओफैंस यह बनता है। चेयरमैन सर, इस बात को जेहन में रखना चाहिए क्योंकि आज हरियाणा की जनता इस बात को देख रही है। आज बिजली की एक-एक यूनिट इस्तेमाल हो रही है। चेयरमैन सर, सरकार को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि कहीं ये लोग सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के निर्माण कार्य को दोबारा से लोगों के बीच मुद्दा बना कर या कोई और ऐसा मुद्दा खड़ा करके सत्ता में न आ जाएं। हालांकि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं और हरियाणा की जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि हरियाणा की पब्लिक में ये लोग अब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और हमारी सरकार की पापुलैरिटी इस कद्र बढ़ती जा रही है कि लोग सरकार में पूरी निष्ठा जताने लगे हैं। चेयरमैन सर, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले तीन साल तक जनता को यह बात बता कर रखेंगे। लोग कहते हैं कि जनता की मैमरी शॉर्ट होती है लेकिन जनता की मैमरी शॉर्ट नहीं होती बल्कि हरियाणा की जनता की मैमरी 100 फीसदी सही रहेगी। हम लोग जनता को यह बात निश्चित तौर पर बताएंगे कि ये वही लोग हैं जो हरियाणा की जनता की नब्ज को, हरियाणा की जनता की भावुकता को कैश करके सत्ता में आये थे। हमने लोगों को यह बताया कि हमारी सरकार विचारधारा की पार्टी की सरकार है। यह उस मुख्य मन्त्री द्वारा हैडिड सरकार है जिसके जेहन के अन्दर पार्टी की विचारधारा और देश प्रेम, हरियाणा की जनता का प्यार है। दो साल के इस सरकार के शासन के दौरान कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी एक व्यक्ति पर भी किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता है। चेयरमैन सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, के प्रस्ताव के पक्ष में अपना पक्ष देता हूं और सारे सदन से यह गुजारिश करता हूं तथा यह उम्मीद भी करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा और हम तरक्की करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह अभिभाषण तैयार किया है इसके अन्दर सभी वर्गों का भला

करने का प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है कि **सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।** यह अभिभाषण हमारा नया बजट कैसा होगा उसका एक विजन है। यह जो अभिभाषण है वह आने वाले बजट की एक तरह से प्रतिछाया है जो यह दर्शाता है कि हर वर्ग इस समाज का एक अंग है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, इन सबके लिए प्रयास किया गया है कि इन सबका भला इस अभिभाषण के माध्यम से हो। चेयरमैन सर, सबसे पहले जो महिलाओं की बात कही गई है मैं उस पर ही अपनी बात कहना चाहूंगा। एक समय था जब हमारे ऋषि-मुनि यह कहा करते थे **यत्र नारियस्ते पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।** लेकिन बीच में एक ऐसा अंधेरा युग आया जब नारी को केवल अबला कहा जाने लगा। घर की चारदीवारी के भीतर ही हर तरह के सम्मान से उसको वंचित किया गया। लेकिन वक्त बदला, समय ने करवट ली, प्रजातन्त्र के इस युग के अन्दर महिलाओं के विकास की, महिलाओं के भले की बात की गई। चेयरमैन सर, हमारी बहन जी बैठी हुई है, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इनके लिए बहुत काम किए हैं। चाहे शगुन व्यवस्था हो, चाहे लड़कियों को वजीफा देने की बात हो, चाहे लड़कियों को फ्री शिक्षा देने की बात हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बढ़िया और बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है वह है शिक्षा के विस्तार का। उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर के अन्दर स्थापित किया गया। इसके लिए इस सरकार ने प्रस्ताव पास करके एक कानून पास किया है और अब इस विश्वविद्यालय को बना रहे हैं। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकार जब महिलाओं के विकास के लिए इतनी बातें कर रही हैं तो नारनौल में एक महाविद्यालय है उसके अन्दर साईकॉलोजी और फिजिकल ऐजुकेशन के विषय नहीं है जिनकी मांग वहां के लोग बार-बार करते रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन विषयों को हमारे महाविद्यालय के अन्दर चालू करवाया जाए। इसके साथ ही साथ मेरा एक निवेदन और है कि हमारे इलाके महेन्द्रगढ़ के अन्दर हमारी लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के अन्दर जाती हैं, इन्टर यूनिवर्सिटी के जो कम्पीटीशन होते हैं उनके अन्दर उन लड़कियों का बहुत अच्छा योगदान है, उनको वजीफा मिलता है, वे मैरिट पर आती हैं इसलिए यदि खानपुर में जो महिला विश्वविद्यालय आप बना रहे हैं, उसका एक रीजनल सैंटर महेन्द्रगढ़ या नारनौल में भी बना दें तो यह बहुत अच्छा होगा। मैं सरकार से इसके लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि नारनौल के अन्दर स्पैशल तरह का वातावरण है और नारनौल राजस्थान का दक्षिणी पार्ट भी है और इस प्रदेश का गेटवे भी है। वहाँ पर दूसरे जो लोग आते हैं तो उनको लगे कि कैसी शिक्षा, कैसी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश के अन्दर की जा रही है। इसी के साथ ही साथ चेयरमैन महोदय, नांगल चौधरी में जो बस अड्डे की कल मंजूरी दी गई है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन महोदय, बहन जी भी यहां पर बैठी हुई हैं मैं आपके माध्यम से इनका स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बहन जी से कहना चाहता हूं कि पिछली बार सदन में बात आई थी कि सरकारी अस्पताल में जो दवाईयां थीं उन दवाईयों को गटर में और नदियों में डाल दिया गया था और आफिसर्ज ने बड़ी मुश्किल से उनको वहां से निकलवाया था। इस विषय में सदन में वायदा किया गया था कि इसके लिए जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होंगे उनको सजा दी जाएगी। लेकिन उनको सजा देने में नीचे के स्तर पर ढील हुई है जिसके कारण उनके हौंसले बुलंद हो गए थे। अब उन्हीं में से कोई तो बी०जे०पी० के और इनैलो के कार्यकर्त्ता को सरकारी अस्पताल में बुलाकर रिबन कटवाता है कोई कुछ और करता है। यह ठीक नहीं है, इस बारे में मेरे पास फोटो भी है और मैं वह बहन जी को दिखा दूंगा। वे कर्मचारी

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]

किसी भी पार्टी की विचारधारा से सम्बन्धित हों, इससे हमें कुछ नहीं लेना है यह उनकी अपनी मर्जी है लेकिन हमारा यह कहना है कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए।

चेयरमैन सर, सिंचाई के लिए दादूपुर नलवी नहर और हांसी बुटाना नहर बनाने के लिए इनका उद्घाटन किया था। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी बनवाएं। इसके अलावा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से मसानी के बांध को पानी से भरने का जो काम किया उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन सर, मेरे अपने इलाके में हमीदपुर का बांध बनाने की भी मांग थी क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी, उसकी मांग को लेकर हमारे इलाके के 25 गांव के लोगों ने चुनावों के दौरान वोट डालने का भी बहिष्कार किया था। सरकार ने इस बांध से बनने वाली नहर के लिए 242 लाख रुपए मंजूर किए हैं और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है और उसके बारे में घोषणा भी की है कि वह जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएगी। चेयरमैन सर, हमारा यह बहुत बड़ा हल्का है और उसकी भौगोलिक स्थिति का धरातलीय आकार भी भिन्न-भिन्न है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे जोरासी के बांध को भी नहर से जोड़ा जाए और उसको भरने का काम किया जाए। इसके साथ ही मेरे हल्के में बायल और मूसनौदा के जो छोटे-छोटे बांध हैं उनको भी बरसाती पानी से भरने के लिए नहरों के साथ जोड़ने का काम करें। चेयरमैन सर, इसके साथ ही वहां पर दो नदियां और हैं जो राजस्थान से निकल कर आती हैं लेकिन राजस्थान वालों ने उन नदियों पर बांध बना दिये हैं जिसकी वजह से वे नदियां भी सूख गई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार इन नदियों मे पानी डालकर वहां पर छोटे-छोटे बांध बनवाए जिससे वहां पर पानी का प्रबन्ध किया जा सके। चेयरमैन सर, इसके अलावा हमारे यहां पर पब्लिक हैल्थ का जो लेटेस्ट ट्यूबवैल लगाया गया है उसमें पीने का पानी 900 फीट नीचे जाकर मिला है। चेयरमैन सर, आपके पास भी इसकी रिपोर्ट आई होगी। अगर इन नदियों में पानी डाला जाएगा तो वहां पर जमीन में पानी का लैवल ऊपर आ जाएगा। चेयरमैन सर, माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि यह पूरा हो जाएगा, मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगा।

चेयरमैन सर, इसके साथ ही यहां पर खेती के बारे में बात आई। कल यहां पर सदन में अढ़ाई बजे खबर आई कि हरियाणा में ओलावृष्टि हुई है और उसकी वजह से फसल खराब हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने रात को ही गिरदावरी करने के आर्डर दे दिए। यह बात ठीक है कि वहां पर किसानों का नुकसान हुआ है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रात में ही गिरदावरी के आर्डर दे दिए थे। इस बात के लिए मैं लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन सर, साथ ही साथ मैं किसानों के लिए एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके का जो किसान है वह सरसों की बहुत ही बढ़िया फसल पैदा करता है। सर, वर्ष 1996-97 के अन्दर सरकार ने वहां पर एक सर्वे करवाया था कि हिसार में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उसका एक रीजनल केन्द्र वहां पर बढ़िया बीज बनाने का खोला जाएगा। इसके लिए हमारे हल्के में चिंदालिया और महरमपुर गांवों के अन्दर जमीन देखी गई थी लेकिन वह कार्यवाही कागजों में ही रह गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस फाईल को निकाला जाए और जिस तरह से यह सरकार हर काम को पूरा करती है और कर रही है उसी तरह से इस अधूरे पड़े काम को भी पूरा करने का कष्ट करें ताकि किसानों को फायदा मिल सके। सर, आज सदन में जो कुछ भी दृश्य देखने को मिला यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आदमी अगर

कोई बात किसी को कहता है तो उसमें अपनी आलोचना सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैंने सदन में इतनी जो बातें कहीं है अगर इनमें से कोई गलत बात मैंने सदन में कही होगी तो मुझमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि बाद में आलोचना सुनने की हिम्मत भी हो। हम केवल किसी भी बात का विरोध करने के लिए ही आलोचना करें तो यह अच्छी बात नहीं है। ये आलोचना के लिए आलोचना करें तो यह एक अच्छी निशानी नहीं है। चेयरमैन साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद आप मुझे बजट पर बोलने का समय दे पाएंगे या नहीं लेकिन जब आप इधर बैठे हुए थे तो आपने एक बात कही थी और आपकी बात पर मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये सबसे ऊपर हो जाते हैं। सरकार ने इतना बढ़िया अभिभाषण तैयार किया है कि लोगों की चिंताओं, लोगों के कष्टों का इसमें ख्याल रखा गया है। समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त की गयी है और किस तरह से उनका भला हो सकता है, किस प्रकार से उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा किया जा सकता है उसके लिए इसमें प्रयास किया गया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो संतुलित और व्यवहारिक अभिभाषण तैयार किया गया है और जिस तरह से सरकार ने अपनी नीतियों को इसके अंदर दर्शाया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने अपने हल्के की अधूरी बातों के लिए सरकार से प्रार्थना की है उनको भी पूरा किया जाएगा। आपका धन्यवाद।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : धन्यवाद चेयरमैन सर, मैं गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। इससे पहले कि मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण पर कुछ कहूं मैंने संक्षिप्त में सिर्फ दो बाते कहनी हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने कल बोलते हुए यह कहा कि हरियाणा में एक बूंद भी पानी कांग्रेस के राज में नहीं बढ़ा है और न ही एक यूनिट भी बिजली की बढ़ी है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूं कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं इनका ऐसा विश्वास है कि अगर झूठ कहते ही रहो, कहते ही रहो तो उस पर लोग विश्वास करने लग जाएंगे लेकिन अब उनका यह भ्रम टूट चुका है। उनको ज्ञान नहीं है कि लोगों ने खासकर किसानों ने जिनकी गर्दन पर पांव रखकर ये मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इनको इतना दुत्कार दिया है कि इनकी पार्टी को उन्होंने हरियाणा में केवल 9 ही मैम्बर दिए हालांकि इनकी पार्टी आल इंडिया लेवेल की है। आल इंडिया की इनकी पार्टी के पूरे हिन्दुस्तान में केवल 9 ही मैम्बर हैं और इनमें से भी सबसे ज्यादा हमारे हरिजन भाई ही चुनकर आए हैं। जिनके पास एक भी किल्ला जमीन हो वह तो केवल ओम प्रकाश जी चौटाला ही हैं। चेयरमैन साहब, अगर वे यहां पर होते तो मैं उनको बताता लेकिन मै समझता हूं कि मैं अब आपका समय खराब नहीं करना चाहता। जब उन्होंने यह बात कही कि कांग्रेस के राज में एक बूंद पानी नहीं बढ़ा और एक यूनिट बिजली की नहीं बढ़ी तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि यह सावन के अंधे वाली बात है जिसको हरा हरा ही नजर आता है। इनकी पार्टी का जो निशान है वह भी ऐनक ही है और इनकी पार्टी का झंडा भी हरे रंग का ही है इसलिए इन पर इसका असर है क्योंकि इनको सही बात नजर नहीं आती। उस समय साढ़े पांच साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता होगा जब इन्होंने यह न कहा हो कि अगले महीने की पहली तारीख से हरियाणा में 24 घंटे बिजली चलेगी लेकिन वह पहली तारीख कभी नहीं आयी। चेयरमैन सर, यह बात रिकार्ड पर है और सब अखबारों में छपी है। इन्होंने बहुत झूठ बोले थे। मैं इस विषय पर और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कहने को तो

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

बहुत कुछ है पर अब जब वे बैठे ही नहीं हैं तो कहने का कोई फायदा नहीं है। जो मैमोरैंडम कांग्रेस पार्टी ने तैयार करवाया था उसमें उनके बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। ये सब उनकी आदत का हिस्सा है। वर्तमान सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने थोड़े से समय में ही बहुत बड़े कीर्तिमान कायम किए हैं। मैं कई सरकारों में रहा हूं और तीन मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमण्डल में मंत्री भी रहा हूं। मैं राव बीरेन्द्र सिंह, चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल की कैबिनेट में मंत्री रहा हूं। चौथे मुख्य मंत्री यह हैं जिनको मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जिसके मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हों, इतने रहम दिल हों, जिनको काम करने की इतनी लगन हो। जो कुछ भी किसी ने कहा चाहे वह विपक्ष का हो या सत्तापक्ष का हो जो भी जैनुअन बात लगी, बिना कोई टाइम लिए उस बात को ये मान जाते हैं। यह बड़ा भारी गुण होता है। ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं जो हां तो कह देते थे लेकिन काम नहीं होता था। लेकिन ये हां कह देते हैं तो ईमानदारी से कोशिश भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनके अधिकारी इनकी कोशिशों को सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। सरकार को भय, भ्रष्टाचार और अपराध विरासत में मिले थे। उन्होंने पिछले साढ़े पांच साल में विधान की धज्जियां उड़ाई और कानून को ताक पर रख दिया तथा जो भी ह्यूमन राइट्स थे उनका सबका पूरी तरह से हनन कर दिया था। जो जर्नलिस्ट थे उनको मरवाया। इन्होंने अपने शासन काल में भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्टेट भ्रष्टाचार का नमूना थी। ये स्वयं हाई पॉवर परचेज कमेटी के चेयरमैन थे। जब भी कोई खरीद फरोख्त करते थे या वर्क अलौट करते थे तो नैगोसिएशन के नाम पर अपना हिस्सा तय करते थे। जब कोई अधिकारी यह कहता था कि यह ठीक है ऐसा कर लो तो ये यह कह कर मना कर देते थे कि ये स्टेट के इंट्रस्ट में नहीं है। लेकिन हमारी इस सरकार ने हर तबके को, किसान को, मजदूर को, दलित को, महिलाओं को, सभी लोगों को सम्मान दिया है और सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों को सुविधायें दी हैं। 2006-07 का जो बजट था वह केवल 3300 करोड़ का था लेकिन उसको बढ़ाकर 2007-08 के बजट में 5300 करोड़ रुपये कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा वृद्धि किसी और स्टेट को प्लानिंग कमीशन ने दी होगी। यह चालीस प्रतिशत वृद्धि है। इसका क्रेडिट सरकार को जाता है। सरकार ने किसान के बिजली के बिल माफ किए, कर्ज निपटारे के लिए बोर्ड बनाए, गिरफ्तारी के काले कानून को खत्म किया, फसल का मुआवजा दुगुना कर दिया और जमीन अधिग्रहण के चार गुने रेट कर दिये। पहले यह 3 से 5 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था जबकि अब वह 15 से 25 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। गन्ने, गेहूं और धान इनकी कीमतें पिछले पांच साल में 50 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से बढ़ी। जीरी के भी दस रुपये बढ़ाए लेकिन कांग्रेस के राज में हमारी सरकार ने गेहूं के एक साल में 100 रुपये और जीरी के 50 रुपये बढ़ाए। इस बार गेहूं की बहुत अच्छी फसल थी लेकिन बरसात और ओलों की वजह से इस बार फसल को नुक्सान हुआ है। लेकिन गेहूं जब मण्डियों में आयेगा तो सरकार इसकी कीमत को 50 रुपये या 100 रुपये और बढ़ायेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। किसानों का ब्याज सरकार ने माफ किया। पिछले दिनों मजदूरों और दिहाड़ीदारों की मजदूरी को 2600 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह किया जो कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। पंचायती राज के ओहदेदारों जैसे नम्बरदार, चौकीदारों और विधवाओं का मानदेय बढ़ाया है और छोटे तबके के वजीफे को बढ़ाया है। नहरें भी निर्माणाधीन हैं। हम हरियाणा के हिस्से का पानी भाखड़ा लाईन से लेकर आयेंगे। नये बिजली घर बनाये जा रहे हैं। विदेशी पूंजी निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा है।

एक्सप्रेस हाईवे बनाये जा रहे हैं। आर०ओ०बी०, इन्फ्रास्ट्रक्चर को सरकार तैयार कर रही है। चेयरपर्सन महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहूंगा कि आल इण्डिया फार्मर्स कमीशन ने किसानों की परिभाषा को एक नया रूप दिया है। पहले तो जिसके पास जमीन होती थी उसी को किसान का नाम दिया जाता था और बाकी जो जमीन पर काम करते थे दलित, बैकवर्ड, हरिजन और दस्तकार, उनको किसान नहीं कहा जाता था। लेकिन आल इण्डिया फार्मर्स कमीशन ने किसान की परिभाषा को इस प्रकार किया है कि जो भी खेत में डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली काम करता है चाहे वह मजदूर हो, चाहे मच्छी पालने वाला है, चाहे मुर्गी पालने वाला है, चाहे दरख्त लगाने वाला है, चाहे हार्टीकल्चर ऐटसैट्रा में काम करने वाला है, चाहे वह मालिक है या नहीं, वे सभी किसान हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन सर, इसके अलावा मैं तो यही कहूंगा कि जो गांवों में छोटे-छोटे काम करने वाले छोटे आढ़ती, दुकानदार और छोटे-छोटे धन्धे करने वाले जिनका संबंध किसानों से जुड़ा हुआ है जिनके पास छोटी पूंजी है, आज उनको भी बड़ी भारी थ्रेटनिंग मिल रही है क्योंकि बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियां अमेरिका, यूरोप की या और देशों की यहां पर आकर बड़े-बड़े मार्ट बना रही हैं और उन छोटे आदमियों का रोजगार छीन रही हैं। उन कम्पनियों ने एग्रीकल्चर सैक्टर में भी अपना बेस बना लिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को इन छोटे-छोटे लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के सभी जिलों में कर्जा निवारण बोर्ड बनाये हैं अभी उन बोर्डस् ने काम करना शुरु कर दिया है। मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके लिए वे कोई समय सीमा निर्धारित कर दें और कम से कम समय में इन कर्जों का निपटारा करवायें। हालांकि सरकार के पास कर्जों के बारे में डायरेक्ट रिकार्ड नहीं था लेकिन आज भी यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लैण्डलैस वर्कर्ज और स्माल फार्मर्ज हैं जिनके पास 4-5 किले तक जमीन हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए, किसी मद के लिए जैसे ट्रैक्टर या टयूबवैल के लिए लोन लेते हैं और उस लोन से सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करें क्योंकि वे ऐसे लोन लेकर अपने सामाजिक खर्जों का निर्वहन करते हैं क्योंकि गांव में किसी के पास न घर में पैसा है, न बैंक में पैसा है इसलिए इस तरह के प्रावधान करने की आवश्यकता है। गांव के लोगों को कन्जंमशन लोन के नाम से लोन दिया जाना चाहिए जिससे गांव के गरीब लोग अपने सामाजिक खर्चे वहन कर सकें। इस तरह का लोन 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए और उसके लिए किसी तरह की गारंटी भी नहीं लेनी चाहिए। सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है, खाद मिलावटी आ रही है, बीज नकली आ रहे हैं और कीड़े मारने वाली दवाईयां भी नकली आ रही हैं जिसके कारण किसानों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, आप भी किसान हैं इन सब बातों की आपको पूरी नॉलेज है। किसान खेती के यूज के लिए जो मशीनरी खरीदता है उसकी कीमतें भी बहुत अधिक ली जाती हैं यानि की हर तरफ मिलावट और धोखाधड़ी किसानों के साथ होती है। यदि किसान फसल पर दवाई का स्प्रे करता है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, बीज बोता है तो उगता नहीं है। यह सब इसलिए हो रहा है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ जो कानून बना हुआ है वह बहुत पुराना है। मैं अनुरोध करूंगा कि अब इस कानून में चेंज करने की आवश्यकता है। इस तरह की चेंज इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो भी दुकानदार मिलावट करेगा या नकली सामान बेचेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा दी जायेगी। ऐसा करने पर ही हम किसानों को सही खाद, बीज और दवाईयां उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे अधिकारी चैकिंग भी करते हैं

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

और उन लोगों को पकड़ा भी गया है जो नकली बीज, खाद और दवाईयां बेचते हैं। लेकिन इसके लिए सजा बहुत कम है। कई अधिकारी तो दुकानदारों से मंथली भी लेते हैं। इसलिए इस कानून में बदलाव करना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक बात और सदन में कहना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी और उन्होंने उस पर गौर करने के लिए भी कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो किसान बैंक का कर्जा नहीं लौटा पाते, बैंक उनकी जमीन की डिक्री करके उस जमीन को बेच देता है और अपनी वसूली करता है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस जमीन के कारण आज किसान की यह हालत हो गई कि वह बैंक का कर्जा नहीं लौटा पा रहा और यदि किसान की उस जमीन को भी उससे छीन लिया जायेगा तो किसान कहां जायेगा ? मैं कई दफा गुस्से में अपने हल्के में बैंक वालों को यह कहता हूं कि तुम जिस किसान की जमीन बेचने जाते हो उस किसान के परिवार वालों के लिए एक-एक सल्फास की गोली भी ले जाया करो क्योंकि उनकी जमीन बिकने के बाद उन्हें सलफास ही खानी पड़ती है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि किसानों की जमीन बेचकर वसूली की जाने वाले इस काले कानून को भी मुख्य मंत्री जी समाप्त करने का काम करें। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से सिक इण्डस्ट्रीज का पहले वाला कर्जा माफ करके दोबारा से कर्जा देकर उन्हें एस्टेबलिश करती है तो किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता ? एग्रीकल्चर सैक्टर पूरे देश में सिक है। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षा सोनिया गांधी सभी कहते हैं कि पूरे देश में कृषि की हालत बहुत खराब है। सभापति महोदय, जब 1996 के बाद सैंटर में गैर कांग्रेसी सरकारें आई उस समय से ही कृषि की हालत खराब होनी शुरु हो गई थी। उन सरकारों ने एग्रीकल्चर सैक्टर की तरफ किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खेती के यूज में आने वाले यंत्र, बीज, खाद, दवाईयों आदि के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए थे। यही कारण हैं कि आज खेती टोटे का धन्धा बनकर रह गया है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इण्डस्ट्री की तरह ही हमें एग्रीकल्चर सैक्टर की भी मदद करनी चाहिए और किसानों की जमीन बेचकर उनसे कर्जा वसूल नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह के प्रावधान हम करेंगे तभी एग्रीकल्चर सैक्टर का फायदा हो सकता है। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे हरियाणा में शिक्षा का बहुत अधिक अभाव है, क्वालिटी एजूकेशन हमारे यहां नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं वे भी अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो फिर वे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं ? हमारे यहां साईंस और दूसरे टैक्नीकल सब्जैक्टस हिंदी में पढ़ाये जाते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे दूसरी अच्छी जगहों पर दाखिले और नौकरियों के कम्पीटीशन में पीछे रह जाते हैं। सभापति महोदय, भारत सरकार का जो बजट प्रस्ताव आया है उसमें वित्त मंत्री जी ने 34 प्रतिशत की इन्क्रीज शिक्षा के क्षेत्र में और 23 प्रतिशत की इन्क्रीज हैल्थ के क्षेत्र में की है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। अगर वो शिक्षित नहीं है और उसकी सेहत ठीक नहीं है तो वह अच्छा किसान नहीं हो सकता वह अच्छा इन्सान नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं इसके बारे में संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला ने सर्वे किया कि साईंस में और कौमर्स में टेकनिकल सबजैक्ट्स में गाँवों से आये हुए स्टूडैंट्स केवल 6 प्रतिशत थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर का यह सर्वे है वहां यह संख्या 4 प्रतिशत है जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ में यह संख्या केवल 2 प्रतिशत

हैं। कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना में भी 96 प्रतिशत वे स्टूडैंट्स जो हैं वो नोन एग्रीकल्चरल हैं वे गांवों के नहीं अर्बन ऐरियाज से हैं। जो नोन एग्रीकल्चर प्रोफैशन में हैं, वे उनके ही बच्चे हैं। हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज इनसे अच्छी नहीं हो सकती। इस देश में 25 प्रतिशत लोग जो हैं उनके बच्चे माडर्न, बढ़िया अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और 75 प्रतिशत लोगों को कोई एक्सैस नहीं है। गांवों के रहने वालों को अपने बच्चे सरकारी स्कूलों, लोकल स्कूलों में भेजने पड़ते हैं। कई जगहों में तो वे इन स्कूलों में भी नहीं भेज सकते। इसका नतीजा यह होता है कि बाद में न तो वे किसी बढ़िया अच्छे संस्थान में दाखिल हो सकते हैं और न ही उनको कोई फ्रूटफुल नौकरी मिलती है। ऐसी सूरत में सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए क्योंकि प्रांतो के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। जो बी०एस०एन०एल है या उस जैसी और भी अगर कोई पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज है तो उनको बेचकर पैसा अरेंज किया जा सकता है। BSNL एक लाख करोड़ रुपये में बिक सकती है। मैं समझता हूं कि जब तक एक सुश्त रुपया शिक्षा में नहीं लगायेंगे, टैक्नीकल एजुकेशन में नहीं लगायेंगे या रूरल ऐरियाज में नहीं लगायेंगे तब तक हम बहुत पीछे रह जायेंगे। आज यह जो हिन्दुस्तान है इसके दो हिन्दुस्तान बन गये हैं इसमें एक तो वे अनपढ़ गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं जो गांवों में रहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो शहरों में बहुत तरक्की कर रहे हैं। हैल्थ के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त विभिन्न सर्वेज की जो रिपोर्ट आई हैं उसमें पूअर न्यूट्रीशन और सेहत की खराबी की वजह से बच्चों में लर्निंग ऐबिलिटी, ज्ञान सीखने की, शिक्षा लेने की ऐबिलिटी जो है वह बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी माताएं हमारे बच्चे जो हैं स्पेशली उनकी तरफ ध्यान दिया जाये। गांवों के 80 प्रतिशत लोगों को कोई न कोई बीमारी अवश्य है। लेकिन उनकी सेहत के लिए जो भुख्य एड उनको चाहिए उसके लिए उनके पास रुपये नहीं होते। सरकार के अस्पताल और डिस्पैंसरियां जो हैं वे पूरी तरह से दवाईयों से लैस नहीं हैं और दवाई आजकल बहुत ज्यादा मंहगी हो गई हैं इसलिए गरीब आदमी के लिए जहां शिक्षा की बात है वहां सेहत की भी बात है। मैं एक बात कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जिस देश का बच्चा भूखा हो उसकी जवानी क्या होगी ? अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी ने भी एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि आपकी जी०डी०पी० कितनी भी क्यों न हो, आपकी इकोनोमिक ग्रोथ कितनी भी क्यों न हो लेकिन जो आपकी सोशल रिस्पौंसिब्लिटी है जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय नहीं देंगे, गरीब आदमी को हर बात के लिए तरक्की करने के मौके नहीं होंगे तक तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूं कि हरियाणा में भी जो बहुत गरीब आदमी हैं उनके लिए कानून में कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे कुम्हार हैं या दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, कानून में उनको सामाजिक न्याय देने का प्रावधान होना चाहिए। कुम्हारों को पंचायतें एक-दो किल्ले जमीन दे सकती हैं ताकि वे लोग वहां से मिट्टी निकाल कर बर्तन आदि बना सकें। इसी तरह से दलित हैं, उनके लिए रिहायशी प्लॉट्स की भारी कमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इसके बारे में पहल कदमी करेगी। चेयरमैन सर, इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहां पर पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देती हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय चौधरी

[श्रीमती सुमिता सिंह]

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देती हूं जिन्होंने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर हरियाणा राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं जिन्होंने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के लिए खर्चों में बढ़ोत्तरी करते हुए घटते राजस्व और वित्तीय घाटे पर काबू पाने के कठिन कार्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। सभापति महोदय, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमन्त्री जी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करके, गन्ने का मूल्य सबसे अधिक दे कर, ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए सबसे ज्यादा मुआविजा देकर सच्चे मायनों में हरियाणआ में 'जय जवान जय किसान' के नारे को बुलन्द किया है। हरियाणा राज्य में सहकारी समितियों के लोन देने के लिए जो लोग कर्ज की किश्तें देने में असमर्थ रहते थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता था जिसके कारण बहुत से हमारे भाई इससे अपमानित महसूस करते हुए आत्महत्या तक कर लेते थे। उनके सम्मान की रक्षा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके लोन की ब्याज की दर में कमी की है और ब्याज की दर 10% से घटा कर 7% की है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। सभापति महोदय, किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, छोटे जमींदारों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोग जिन्होंने सहकारी समितियों से ऋण लिया था उनका ऋणभार कम करने के लिए 30 जून, 2007 तक जो लोग अपना देय मूल ऋण चुकाएंगे, उनके ब्याज में मुआफी करके सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम किया है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं। सभापति महोदय, अभी तक महिलाओं की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिला सहकारी समितियों की ओर विशेष ध्यान दिया है जिससे उनकी संख्या 600 से बढ़ कर 950 हो गई है। हमारी सरकार एस०वाई०एल० नहर के माध्यम से रावी-ब्यास के पानी का हरियाणा का पूरा हिस्सा लेने के लिए वचनबद्ध है। मैं इस बारे में विपक्ष को सलाह देना चाहूंगी कि वे जल की राजनीति से ऊपर उठ कर एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर प्रदेश सरकार का पूरा साथ दें क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दादूपुर-नलवी नहर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। बाढ़ की रोकथाम, भूमिगत जलस्तर तथा सिंचाई के काम में सुधार के लिए एक नई पहल की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता यह भी जानती है कि बिजली की कमी पिछली सरकारों की देन है। पिछली किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि आगे आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी, किन्तु आज हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और अगले तीन वर्षों में बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता में 5000 मैगावाट का उत्पादन करने की योजना है ताकि बिजली की मांग और आपूर्ति के स्तर को मिटा सकें। बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण आज उद्योगपति हरियाणा में आना चाहते हैं, आज हरियाणा उद्योगपतियों की पहली पसन्द बन गया है सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों में 22 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 5300 करोड़ रुपये का निवेश प्रक्रियाधीन है। राज्य में जो सबसे पहला इकोनॉमिक जोन है वह मुख्यमंत्री जी स्थापित कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1 करोड़ 75 हजार रुपये का निवेश किया गया है जिससे 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। विपक्ष के लोगों को चाहिए कि विकास के मुद्दों पर वे सरकार का साथ दें नहीं तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी जिससे हमारे अनएम्पलॉयड यूथ को बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारी सरकार औद्योगिक विकास में नई ऊंचाईयाँ छूने के लिए

अग्रसर है। इसी तरह से शिक्षित बेरोजगारों के लिए 'बेरोजगारी भत्ता-2005' नामक स्कीम शुरु की गई है। इसी तरह से 'ओवरसीज प्लेसमैंट ब्यूरो' की स्थापना की गई है। श्रमिक कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 3510 रुपये प्रतिमास की है जोकि देश भर में सर्वाधिक है। यह भी इस सरकार का एक एतिहासिक कदम है। अब दूसरे प्रदेशों को भी फिक्र हो गयी है कि उनको भी न्यूनतम रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने करनाल की बेटी 'कल्पना चावला' की याद में कुरूक्षेत्र में एक 'कल्पना चावला स्मृति तारा मण्डल' की स्थापना की है और उसका कार्य भी पूरा होने वाला है। मैं मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करती हूं कि वे करनाल में भी उसकी स्मृति में कुछ न कुछ जरूर बनवाएंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो नई आबकारी नीति अपनाई है उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस नीति के तहत अब ड्रा सिस्टम अपनाया गया है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। पिछली सरकार के वक्त में यह देखने में आता था कि मुख्यमंत्री या जो बहुत ही इन्फलुएंस वाले लोग होते थे, उनके रिश्तेदारों को ही ठेके मिल जाते थे। परन्तु आज हमारी सरकार के अन्दर ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। शिक्षा के स्तर पर आज हरियाणा बहुत ही आगे निकल चुका है। शिक्षकों का सशक्तिकरण करने और बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए यह जो सैमैस्टर प्रणाली शुरु की गई है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से सरकार को बधाई देती हूं और धन्यावाद करती हूं। हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी संस्थानों में सीटों को बढ़ाकर 33 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा छोटू राम इंजिनियरिंग महाविद्यालय, मुरथल का दर्जा बढ़ाकर दीन बन्धू छोटू राम विज्ञान प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया गया है। सरकार ने तकनीकी और कम्प्यूटर संकाय के पाठ्यक्रमों में आवश्यक प्रावधान किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और आभार प्रकट करती हूं कि इन्होंने हरियाणा में 31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित किया है।

आज खेलों में भी हरियाणा पीछे नहीं है। हर ब्लाक में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग में नौकरी के लिए कुछ पद आरक्षित किए हैं।

ग्रामीण विकास में भी हरियाणा पीछे नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज प्रणाली को भी सशक्त किया है अब 3 लाख रुपये हर पंचायत के पंच को दिए जाते हैं ताकि यह पंच अपने गांव में सही तरीके से काम करवाए। इसके अलावा इस सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नया सर्वे करने का निर्णय लिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमें विश्वास है कि यह सर्वे पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने शहरी विकास के लिए भी पैसे दिए हैं और हर शहर में सीवरेज और पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा काम हुए हैं। शहरों की हर कालोनियों में पीने के पानी के लिए नए ट्यूबवैल्ज लगाए गए हैं। लोक निर्माण के कामों को करने में भी हमारी सरकार

[श्रीमती सुमिता सिंह]

पीछे नहीं है। हर शहर में नई सड़कें बनाई जा रही हैं। स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने जो इन्दिरा गांधी पेय जल योजना लागू की है इसके लिए मैं इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 8 लाख अनुसूचित जाति के लोगों के निजी घरों में पानी के कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

श्री सभापति : मैडम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी बोलेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : सर, मैं थोड़ा और समय लेना चाहूंगी। मैं इसलिए ही जल्दी-जल्दी अपनी बात को समाप्त करने लग रही हूं। चेयरमैन सर, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं, बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों और समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन सबका खास तौर से ध्यान रखा गया है। इन सभी के लिए पेंशन शुरु की गयी है और यदि इनमें से किसी की पेंशन कम थी तो उनकी पेंशन बढ़ा दी गयी है। इस तरह से परिवहन के क्षेत्र में भी हरियाणा नम्बर वन राज्य है। एक समय ऐसा था जब हरियाणा रोडवेज की बसिज में कोई भी बैठना नहीं चाहता था किन्तु आज सारथी, वोल्वो ए०सी०, हरियाणा गौरव और उन्नत सी०एन०जी० की बस सेवा जैसी उन्नत तकनीक की नयी बस सेवाएं हरियाणा में शुरु कर दी गयी हैं। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति भी संतोषजनक है। पिछली सरकार ने जिन कर्मचारियों को छंटनीग्रस्त किया था, उन सभी को हमारी सरकार ने वापस नौकरी पर लगाकर उनको रोजगार दे दिया है। महिलाओं की तरफ से भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की भर्ती में 33 परसैंट उनको आरक्षण दिया है। चेयरमैन सर, पहले गांवों की हमारी बहनों को शौच जाने में बहुत दिक्कत होती थी लेकिन हमारी सरकार ने हर गांव में सुलभ शौचालय बनाये हैं इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं। एक और काम हमारी सरकार ने अभूतपूर्व किया है वह काम यह है कि जो अपराधी हैं उनके बारे में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अपराध को रोकने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और यही कारण है कि आज प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो गया है और यदि कुछ रह भी गये हैं तो या तो वे जेल के अंदर चले गये हैं या फिर वे परमात्मा को प्यारे हो गये हैं। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में जंगल राज था, गुण्डा राज था लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समाप्त किया है और हरियाणा में राम राज्य, सक्रिय, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैडम सुमिता जी, आपका टाईम हो गया है अब आप बैठें। आप पढ़ रही हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : सर, मैं पढ़ नही रही हूं। बोलने के लिए प्वांयट्स बनाने पड़ते हैं। सर, मैं मुख्यमंत्री जी को सिरसा रैली के लिए भी बहुत बधाई देती हूं। वहां पर जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं वे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में इतने अच्छे काम हुए कि हरियाणा की जनता हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बहुत खुश थी इसलिए हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिरसा रैली में पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे

पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो पानीपत की त्रासदी हुई थी वह बहुत ही दु:खद घटना थी, चाहे इस घटना में हमारे हरियाणा प्रदेश के आदमी नहीं थे लेकिन हर आदमी ने इस घटना की गहराई को समझा है और कहा कि यह गलत हुआ है। इसके अलावा अभिभाषण में यह बात भी कही गयी है कि भय व भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री का शुरु से ही यह नारा रहा है। इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र के अंदर पूरे देश का आदमी रहता है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पर चलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा रैवेन्यू भी सरकार को वहीं से मिलता है। आज एक बात बड़े गौरव और फख्र से कही जा सकती है कि आज प्रशासन पर मुख्यमंत्री जी की पकड़ है हालांकि विपक्ष ने कई बार कहा कि प्रशासन पर मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है। लेकिन आज मैं इस सदन में सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की पकड़ क्या है ? आज डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के बारे में मैं बड़े फख्र से यह कह सकता हूं कि विपक्ष या कोई और आदमी अगर एक सिंगल केस भी बता दें कि किसी आदमी को किसी प्रकार की धमकी मिली हो या किसी आदमी को एक सिंगल नया पैसा हफ्ता या मंथली के रूप में देना पड़ता हो या किसी इंडस्ट्री को चलाने कि लिए पांच या दस लाख भिजवाना पड़ता हो कि जब तक आप इतना पैसा नहीं देंगे तब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तो मैं उसके लिए जबाबदेह हूं। एक सिंगल केस कोई भी बता दें। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि अब भ्रष्टाचार को काफी कुछ कंट्रोल किया गया है। मैं यह बात तो मान सकता हूं कि यह पूर्णत: खत्म नहीं हुआ है लेकिन चालीस साल का भ्रष्टाचार दो साल में खत्म नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आज इस बात को बड़े फख्र से कहा जा सकता है कि किसी थाने या तहसील में एक आम आदमी भी अपनी बात को वहां पर जाकर रख सकता है। यदि वह वहां पर जाकर तेज आवाज में बोल दें कि मेरी एफ०आई०आर० लिखनी है या नहीं लिखनी है तो वहां पर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वह एफ०आई०आर० लिखने से मना कर दें। अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए चले जाएं या पटवारी के पास मूटेशन करवाने के लिए चले जाएं तो किसी पटवारी या तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं कि वह यह कह दें कि आप एक परसैंट या आधा परसैंट पैसा दो। आज तुरन्त उसको ये काम करने पड़ते हैं। इसलिए यह मुख्यमंत्री जी की प्रशासन पर पकड़ की बात मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इज्जत और भाव से बात करते हैं लेकिन शायद लोग यह मानते हैं कि यदि वह इज्जत से बात करते हैं तो उनकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है। लोगों का मानना शायद यह है कि यदि वह गाली दें या डंडा दिखाएं तभी उनकी प्रशासन पर पकड़ होगी लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो लोग इस बात को महसूस करते थे आज वह सोचने पर मजबूर हो गये हैं। गुड़गांव के अंदर पहले गऊ मांस का बहुत बड़ा व्यापार चलता था और सरेआम टैम्पो में इसको भरकर ले जाते थे लेकिन प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाता था। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़े गौरव के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज न तो रात को गायों की चोरी होती है और न ही गऊमांस की तस्करी होती है। मैं इस बात के लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी की पकड़ इस बात को सिद्ध कर रही है कि ये चीज हो रही हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended upto 2.30 p.m.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the House is extended up to 2.30 p.m.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फसलों में ओलावृष्टि का पहले 10 से 15 परसैंट तक नुक्सान था लेकिन कल रात को जो बारिश हुई है और ओले गिरे हैं उससे यह नुकसान और ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने हालांकि रात को ही राहत की घोषणा कर दी है कि ठीक ढंग से गिरदावरी हो और जायज मुआवजा मिलना चाहिए। सर्वे की बात आई है तो उसके बारे में एक बात का सुझाव देना चाहूंगा। मेरे हल्के में एक 'रोज का गुजर' गांव है वहां पर दस हजार एकड़ लैंड है वह गैर मुमकिन पहाड़ कहलाता है उसके बारे में मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह जमीन ऐक्वायर की जाए। उस जमीन का रेट 2 से ढाई रुपये पर एकड़ के हिसाब से है। उस एरिया को ऐक्वायर करके उसको एस०ई०जैड० को दे दिया जाए। इस सरकार ने जमींदार का इन्ट्रस्ट रेट भी कम किया है हालांकि बैंकों ने यह रेट बढ़ा दिया है, इससे जमींदारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जो छोटे-छोटे हाथ के दस्तकार थे उनको भी सरकार ने राहत दी है। सिरसा रैली में कई साथियों ने कहा कि कोई छूट नहीं दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि जिस ने 20-30 हजार रुपये का लोन लिया हुआ था और उसको किसी कारणवश वापस नहीं दे पाए थे और उस पर इंट्रस्ट लगाकर 50 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक हो गया, उनके लिए सिरसा रैली में यह फैसला किया गया है कि अगर वे 30 जून तक अपना मूल ऋण 20 हजार रुपया जमा करा देंगे तो उनका उस लोन से छुटकारा हो जाएगा और उनको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार इस सिरसा रैली से सिर्फ मेरे हल्के के किसानों को ही 3 करोड़ 53 लाख रुपये का रिलीफ मिला है, जो छोटे हाथ के दस्तकार थे उनको फायदा मिला है। मेरे क्षेत्र से संबंधित जो एस०ई०जैड० है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं ताकि इस बारे में लोगों को पता लगे कि जो जमीन पिछली सरकार ने ऐक्वायर की थी उस समय उसका 2 लाख 60 हजार, 3 लाख 60 हजार व 5 लाख 75 हजार रुपये हाईएस्ट रेट था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो 25 हजार एकड़ लैंड दी है उसमें से 21 हजार एकड़ लैंड ऐसी है जो खारे पानी की है। मैं आपके सामने इस बात को कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास पटवारी की रिपोर्ट है यह ऐसी ही रिपोर्ट नहीं है, यह ऐसे ही बनाई हुई नहीं है। चार हजार एकड़ जमीन जिसके नीचे मीठा पानी और मरमरा पानी था उस जमीन को बाहर की कम्पनियों ने कभी नहीं खरीदा। गुड़गांव के बड़े जमींदार भी वही जमीन खरीदते थे जिसके नीचे मीठा पानी होता था। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुलतानपुर झील गांव के आस-पास एक-एक गांव में जाकर जमींदारों से मीटिंग की है और उनसे पूछा है कि क्या आप एस०ई० जैड० का विरोध करना चाहते हो तो उन्होंने कहा, नहीं जी, क्योंकि इस जमीन को आज से पहले कोई भी दो लाख प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं पूछता था और आज यह जमीन 20-25 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव में बिक रही है इसलिए हम

क्यों एस०ई०जैड० का विरोध करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लाखों परिवारों को राहत दी है जिन्होंने सैक्शन 4 लागू होने से पहले बसासत से लगते हुए अपने छत के मकान बना रखे हैं अब उनके मकान नहीं तोड़े जायेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पर छोटी-छोटी ढाणियां बनी हुई हैं उस जमीन के बदले एस०ई०जैड० के लिए दूसरी जमीन एक्सचेंज कर ली जाए ताकि वे लोग भी बसे रहें। जैसा कि देहली गवर्नमैंट ने किया है कि एक्सटैण्डिड लाल डोरा के अन्दर कोई बाई-लॉज लागू नहीं होगा। उसके लिए 15 मीटर हाईट और 10 मीटर कवरेज का पैरामीटर फिक्स किया गया है। जिन जमींदारों की जमीन एस०ई०जैड० के लिए ऐक्वायर हो गई है वे जमींदार छोटे-छोटे कॉमर्शियल शैड बनाकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। कभी तो हुडा आफिस के इस्टेट आफिसर और कभी डी०टी०सी०पी० आफिस के अधिकारी उनको नोटिस देकर उनके मकान तोड़ना शुरु कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : जौनपुरिया जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। स्पीकर सर, अब से पहले सुलतानपुर झील के गांव की जमीन जो एस०ई०जैड० के लिए एक्वायर हो गई है उस जमीन की अब तक जो रजिस्ट्री हुई है उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1,92,000 रुपये से लेकर 8,50,000 रुपये की हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है। जबकि आज उस जमीन का मुआवजा अब सरकार 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक दे रही है, मुबारिकपुर गांव में वर्ष 2006 में 2,95,000 रुपये की रजिस्ट्री हुई है, गोपालपुर गांव में 2,30,000 रुपये से लेकर 13 लाख रुपये तक की हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, हरसुखगढी गांव में 4.48 लाख रुपये की रजिस्ट्री हुई है, गढी गांव में 13,33,000 रुपये की रजिस्ट्री हुई है, साडराना गांव में 4,40,000 रुपये से 17,46,000 रुपये की हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, बुढाडा गांव में 3 लाख से लेकर 6,55,000 रुपये तक की रजिस्ट्री हुई है, बन्दु गांव में 7,23,000 रुपये की रजिस्ट्री हुई है। मकडौली गांव में 6,37,000 रुपये की रजिस्ट्री उस गांव की जमीन हुई है। इस जमीन की रजिस्ट्री की डेट, अमाउंट और प्रति एकड़ की कीमत इस रिपोर्ट में दी गई है। सरकार का जो रिलायन्स के साथ समझौता हुआ है यह एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वे इस बात का भी विरोध करना चाहते हैं तो उनके पास इससे अच्छा ऑप्शन है उसको भी बता दें। इस बारे में मैंने 14-6-2006 को एक अखबार में ऐड भी दी थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी ऑप्शन है तो कृपया बता दें। आज अगर जमींदारों के हित में कोई प्रावधान किया है तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इससे पहले किसी ने ऐसा प्रावधान नहीं किया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस जमीन में अपने मकान बना रखे हैं अगर उनके मकान न तोड़े जाएं तो वे लोग वाकई ही राहत की सांस लेंगे। स्पीकर सर, अब मैं सिरसा रैली में जो दिहाड़ीदार लोगों की दिहाड़ी 2600 रुपये से 3500 रुपये प्रति मास करने की घोषणा की है, उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। मैं उस हल्के का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां 1 लाख 86 हजार लोग रोजाना दिहाड़ी पर काम करते हैं। इस फैसले से वहां पर प्रति आदमी एक हजार रुपये प्रति माह का फायदा हुआ है। इस तरह से 186 करोड़ रुपये प्रति मास के हिसाब से गरीब आदमियों के घर में जायेगा। जिन लोगों को आटे-दाल का ज्यादा महंगा रेट महसूस होता था उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीधा फायदा पहुंचाया है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सदन से चले गये। महंगाई के विरोध में अभय चौटाला गुडगांव गये थे, वहां

[श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया]

पर वे आज भी धमकी देकर आये हैं और अपनी पार्टी के वर्कर्स से कह कर आये हैं कि डी०सी० का नाम लिख कर रखना और एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिख लेना, उनको मैं बाद में देख लूंगा स्पीकर सर, इनकी तानाशाही में अभी भी कमी नहीं आई है। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे आज जमींदारों के हितैषी बनते हैं जबकि वे जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड की बात आज भी दोहरा रहे हैं। मैं इस बारे में सदन को बताना चाहता हूं कि झाड़सा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में वायदा किया था। वहां पर सैशन कोर्ट ने 189 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया था। उसके बाद हुडा हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट ने मुआवजा 106 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से कर दिया था। इस हिसाब से 83 रुपये हुडा ने किसानों से वापस जमा करवाने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री ने उस समय कहा था कि यदि हमारी सरकार आयेगी ते वे किसानों का यह पैसा वापस नहीं लेंगे। इसी बात पर 12 गांवों ने एक मत होकर उनको वोट दिए। उनकी सरकार भी बनी और वे मुख्य मंत्री भी बने लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग इसी बात को लेकर कई बार पूर्व मुख्यमंत्री से मिले भी लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लोगों ने नाराज होकर उनके खिलाफ झाड़सा गांव में सर छोटूराम भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने इनके विधायकों को कहा कि तुम जाकर चौटाला जी को बोल दो कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें बर्बाद कर दिया है और हमारे रिश्तेदारों से भी हमारी दुश्मनी हो गई है। जिस समय उन्हें 189 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया था उस समय हुडा ने उनसे गारंटी मांगी थी। उनका कहना था कि उनकी अपनी जमीन तो सरकार ने एक्वायर कर ली थी इसलिए उन्होंने गारंटी के रूप में अपने रिश्तेदारों की जमीन की जमाबंदी दी थी। जो वायदा चौटाला जी ने हमारे साथ किया था वह पूरा नहीं किया। उस विरोध प्रदर्शन में 20 हजार से भी ज्यादा आदमी मौजूद थे। चौटाला जी ने राजा-महाराजाओं की तरह अपने वजीरों से पूछा कि झाड़सा गांव में क्या हो रहा है। प्रशासन ने उनको बताया कि वहां पर लोग आपके खिलाफ इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने जो वायदा चुनावों से पहले उनके साथ किया था वह पूरा नहीं किया। इस पर चौटाला जी ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं। इस पर प्रशासन ने बताया कि सर, पुलिस है, पुलिस के घोड़े हैं, बंदूकें हैं। चौटाला जी ने आदेश दिया कि जाओ पुलिस फोर्स और घोड़े ले जाओ और उस विरोध प्रदर्शन को रूकवाकर आगे, चाहे किसी भी सूरत में रूकवाना पड़े लेकिन उसको रोको जरूर। अध्यक्ष महोदय, यही कारण रहे कि चौटाला ने उस समय किसानों पर गोलियां चलवाई जिसमें बहुत से किसान मारे गये। उस समय 90-90 साल के किसानों की पगड़ियां घोड़ों की नालों नीचे दबवाई गई, पानी के फव्वारे लोगों पर चलवाये गए और आज वे प्रजातंत्र की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय मेन रोड़ से आधा कि०मी० अंदर तक जाकर लोगों पर गोलियां चलाई गई यहाँ तक कि दूसरी तरफ सोहना तक के लोगों को नहीं बख्शा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि जब बिजली, पानी या कोई और समस्या होती है तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। गुड़गांव में भी 10-12 बार लोगों ने जाम लगाये और 8 बार मैं स्वयं मौके पर गया और लोगों की समस्याओं को सुना। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रजातंत्र में सभी को अपना विरोध करने का हक है। चूंकि हम सरकार में हैं इसलिए हमें उनकी समस्याओं का निपटारा करना है। हमारे मुख्यमंत्री पिछले मुख्यमंत्री की तरह नहीं हैं कि यदि लोग विरोध प्रदर्शन करें तो उन लोगों पर कोड़े चलवायें और घोड़ों की नालों तले कुचलवायें।

श्री अध्यक्ष : सुखबीर जी, अब आप वाईड-अप करें।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के कुछ बातें कहकर अभी वाईड-अप करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश का आदमी एन०एच०-8 पर से होकर निकलता है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि धौलाकुआं से लेकर राजीव चौक तक कई ओवर ब्रिज बन गये हैं और गुड़गांव तक जाने में केवल 15 मिनट का समय लगता है लेकिन गुड़गांव में हीरो-होंडा लाईटों पर ट्रैफिक का बहुत जाम लगता है। यह लाईट एन०एच० -8 पर पड़ती है। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने सब-वे एप्रूव कर दिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सब-वे न बने तब तक वहां कोई और प्रबन्ध किए जायें ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त पलवल से रिवाड़ी एन०एच० 71 का भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मेरा कहना है कि उसको भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मलित किया जाये। इसके अतिरिक्त सोहना से पलवल रोड़ राजस्थान को जोड़ती है। इस रोड़ पर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है इसलिए इस रोड़ को 8 लाईन बनाया जाये। इसी तरह से सोहना से फरीदाबाद रोड़ की हालत बहुत खराब है इस कारण इस रोड़ पर ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो गया है। चूंकि इस रोड़ पर खौरी माईन है इसलिए यह सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस रोड़ को भी बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त गुड़गांव से फरीदाबाद रोड़ को भी चौड़ा किया जाये क्योंकि इस रोड़ पर भी ट्रैफिक बहुत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, अभी कल उद्घाटन करने के बारे में बात हो रही थी। मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले मुख्यमंत्री ने सोहना में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। वहां पर स्टेडियम के नाम पर उन्होंने 100 गज जगह में घास उगवाकर चौधरी देवी लाल की मूर्ति लगवा दी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बाकी और एरिया में आज भी धूल उड़ती रहती है। उसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग विकास की बात कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष : जौनपुरिया जी, आप लिखवा कर भिजवा दीजिए हम उसको मान लेंगे।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, 1980 से गुड़गांव बसा हुआ है। आज 27 साल हो गये लेकिन 27 साल में कभी सिवरेज की, ड्रेनेज की समस्या की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए 776 करोड़ रुपये दिये हैं। जो काम 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे वे आज करने पड़ रहे हैं। सर, आप खुद सोच कर देखिए उस ढांचे के बारे में आप क्या अंदाजा लगायेंगे क्योंकि उस ढांचे में सब कुछ भ्रष्ट हुआ पड़ा है। ये प्रजातंत्र की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो विजिलैंस डिपार्टमैंट का एक काम था कि विरोधियों को तंग करो। आज के मुख्यमंत्री ने उस डिपार्टमैंट को ड्यूटी दे रखी है कि जहां भी कोई भ्रष्ट ऑफिसर हो कोई एम०एल०ए० हो उसका पीछा करो, उसे देखो ताकि गरीब जनता परेशान न हो लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस डिपार्टमैंट की एक ड्यूटी लगा रखी थी कि विजिलैंस की तलवार जो है उसको जिसने भी सांस लेने के लिए मुँह उठाया उसके ऊपर लटका दो। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे ये साथी आज तानाशाह के नारे लगाकर गये हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि तानाशाह होते क्या थे, तानाशाह क्या चीज है ? मेरे एक साथी हैं, वे अब चले गये हैं, ने यहां तक कहा था कि आपका मकान तोड़ दिया इसलिए आप कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उस समय लोगों की त्राहि -त्राहि मचवा दी थी। सर, जिन लोगों ने गांव में बुला-बुलाकर हाथ जोड़-जोड़ कर माला डाली कि ये हमारे मकान हैं इनको

[श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया]

न गिरायें लेकिन उस समय मुख्य मंत्री कहते हैं कि क्या कह रहे हैं ये तो तोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि जमींदार का बेटा हूं किसी के मकान नहीं टूटने दूँगा। इन्होंने सैक्शन 4 से पहले बने मकानों को न तोड़कर लाखों परिवारों को राहत की साँस दी है। वे लोग अब कहते हैं कि भगवान इनका भला करे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हमारे लिए भगवान हैं जिन्होंने हमें ये मकान दे दिये नहीं तो ये टूट ही रहे थे। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ढाणियां हैं उन ढाणियों को शिफ्ट किया जाये जो जमीन एक्वायर की जा रही है उनको लेकर किसी को ऐतराज नहीं है लेकिन उनका तो केवल यही कहना है कि मेन रोड की जो जमीन है उसका मुआवजा थोड़ा तेज हो जाये। अध्यक्ष महोदय, वे बदले की भावना की बात बार-बार कह रहे थे लेकिन उनके समय में एक-एक आदमी को इस तरह से कुचला जाता था जिसकी कोई हद नहीं। आज अगर मुख्यमंत्री को किसी को बदले की भावना से कह भी दिया तो भी किसी को तू कह कर भी नहीं हटाया जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तानाशाही या लोकतंत्र क्या होता है। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मेरे साथियों ने जो स्टेट में किए गए कार्यों के बारे में बताया है वह बहुत ही सराहनीय है। सरकार के हाथ में स्टेट का प्लान करने के जो काम हैं वह बहुत ही सराहनीय रहे हैं। आज अफसोस इस बात का है कि विपक्ष के हमारे साथी यहां मौजूद नहीं हैं जबकि कई बातें उनको आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। जब किसी सरकार के कामों की चर्चा करते हैं और उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करते हैं तो तुलना तो अपने आप हो जाती है। हमारे वे साथी जिनको पिछली सरकार ने रगड़ा लगाया था वे इस बात का इन्तजार भी कर रहे थे कि कब चौटाला जी हाउस में आयें और कब उनको इस बात का एहसास करायें कि आपने ज्यादतियाँ की थी। उनके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया और न ही किसी ने उनको डण्डा मारा उनको तो सिर्फ महसूस करवा रहे थे कि जो आपने ऐसा किया वह नहीं करना चाहिए था। अब उनके पास न तो कोई बात कहने की थी और न ही वह खुलकर सरकार के कामों की तारीफ करना चाहते थे, वे तो सिर्फ एस०वाई०एल० कैनाल का मुद्दा उठाना चाहते थे जिसको उन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। जब गन्ने के भाव की बात आई तो फिर उन्होंने चीनी का गणित निकाल लिया कि पहले यह 7 रुपये किलो थी। इस तरह की बात करके वह असल बात को काबू में नहीं आने देना चाहते थे। सत्य यह है कि जो भी 8-9 मैम्बर उनके बैठे हैं वे भी इसलिए जीत गये कि उनके सामने उम्मीदवार कमजोर थे इसलिए काम बन गया नहीं तो वह स्वयं ही अकेले रोड़ी से जीत कर आते। नरवाना में तो ये श्री रणदीप सुरजेवाला से हार भी गये थे। तो जैसे काम किये थे वैसा ही लोगों ने इनके साथ कर दिया। जब श्री बंसी लाल की सरकार गई तो इनको तो लोग भूल गये थे लेकिन पता नहीं किस तरह से इनका काम बन गया। उसके 8 महीने बाद लोगों ने तो गुस्से में मोहर लगाई। अनेक अनाप-शनाप बात कह कर इन्होंने लोगों से वोट लिए थे। हर आदमी का इन्होंने कार्ड लेकर रख लिया कि हम आपके गुलाबी कार्ड बना देंगे। इनके घर बण्डल के बण्डल पड़े थे। लोगों से ऐसी बातें करके उनको फुसलाया बहलाया। उनसे ऐसी बात की कि लोगों की भावनाएं भड़क गयीं। इसी कारण इन लोगों को राज करने का मौका मिला। स्पीकर सर, सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनके डर के मारे उद्योगपति अपने कारखाने इस स्टेट से दूसरी स्टेट्स में ले गए। इस बात को कौन झुठला सकता है कि सारे जहान के बदमाशों ने तेजा

खेड़ा में अपने अड्डे जमाए हुए थे। स्पीकर सर, किसानों की जो दुर्दशा थी वह सब को पता है। किसानों के नाम पर इन्होंने हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी । किसानों के प्रति इनको कितनी चिन्ता थी इसका सबको पता है। इन्होंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी समस्याओं के मामले में इनके कान पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। इन लोगों को लूट-खसूट से ही कभी कोई फुर्सत नहीं मिली। यदि कभी फुर्सत भी मिली तो कभी तो ये यू०पी० के चुनावों में चले गये, कभी राजस्थान में चुनाव लड़ने चले गए और अब पंजाब के चुनाव में गए हुए थे। इनका यही काम रहा। इन लोगों ने तो इस स्टेट का नाम बिगाड़ रखा था लेकिन हुड्डा साहब ने स्टेट का नाम बिगड़ने से बचाया और इस राज्य की साख को बहाल किया है। स्पीकर साहब, हुड्डा साहब ने इस प्रदेश को हिन्दुस्तान की नम्बर वन स्टेट बनाने का दावा किया और उसके लिए उन्होंने प्लान भी बनाये हैं। यह सरकार इस तरफ अग्रसर है। यही नहीं कितने ही कारखानेदारों को ये यहां पर लाए हैं और बहुत भारी इन्वैस्टमैंट बाहर से अपनी स्टेट में लेकर आए हैं। स्पीकर सर, गुण्डे बदमाशों के लिए आज इस स्टेट में कोई जगह नहीं है। स्पीकर सर, जब बिजली की बात करते हैं तो यह बात सत्य है कि इस सरकार ने यमुनानगर, हिसार और झज्जर में पावर प्रोजैक्ट्स पर पैसा खर्च किया और वे प्रोजैक्ट्स कम्पलीशन के नजदीक हैं। यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट बनने जा रहा है उसके बारे में ये कहते हैं कि हमने पिछली टर्म में बनाया। पिछली टर्म में ही क्यों यह कारखाना तो 1987 में ही बनना चाहिए था। यह कारखाना इनकी पहली टर्म में ही बनना चाहिए था लेकिन उस वक्त इन्होंने वहां पर रफेदे लगवा दिए। अगर वह प्रोजैक्ट उस वक्त लग गया होता तो देखा कहां कहानी बनती लेकिन इतना समय निकल गया। अब जब सरकार की दिल इस कारखाने को लगाने की है और इस बात पर ध्यान दिया गया है तो ये इस तरह की बात करते हैं अब ढाई तीन साल में ही यह प्लांट काम शुरु करने जा रहा है। यह बात तो सच्ची है कि दिन-प्रति-दिन बिजली की डिमांड बढ़ी है उसको कम्पीट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारियां थीं कि वे बिजली पैदा करने के कारखाने लगाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उनको कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, सन 1982 में मैं इसी हाउस में था। उस वक्त स्पीच करते वक्त मैंने बिजली की पैदावार बढ़ाने की बात कही थी। उस दिन हरियाणा के पास 56 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध थी। ये लोग कह रहे थे कि अगर हमारे पास 80 लाख यूनिट बिजली हो तो पूरे हरियाणा को चौबीस घंटे बिजली दी जा सकती है लेकिन अगर आज हम देखें तो 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा प्रदेश को दस करोड़ यूनिट बिजली की आवश्यकता है। बिजली की बहुत डिमांड बढ़ गई है लेकिन इन बातों की तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। यदि ऐसा किया गया होता तो आज यह हालात पैदा नहीं होते। यह पहली सरकार है जिसने इसको गम्भीरता से लिया और बिजली उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी। इसी सरकार के प्रयत्नों से डोमैस्टिक बिजली के सिस्टम को भी अलग करने जा रहे हैं। जल्दी ही इस समस्या पर काबू पा लिया जाएगा इसमें कोई शक नहीं है। यह कहना कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक नहीं है। इन लोगों ने कोई भी ठीक बात की तरफ तो जाना नहीं है। स्पीकर सर, यह बात कौन छिपायेगा कि इनके राज में न तो कनक बिकी और न ही जीरी बिकी, इनका भाव बढ़ाने की बात तो ये लोग भूल ही गये थे। इनके राज में तो यह नारा लगा करता था कि चौटाला तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। किसान सारी-सारी रात मण्डियों में तड़पते थे ताकि उनका अनाज बिक जाए लेकिन आज तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दैड़ दे सी अपना अनाज बेचो और पेमैंट लो। स्पीकर सर, इनके समय में गन्ने का तो यह हाल था कि हरियाणा के किसान गन्ने की

[श्री निर्मल सिंह]

खेती छोड़ गये थे। (विघ्न)इसके कारण क्या थे ? वही खेती है वही मिल्ज हैं वही बातें हैं लेकिन अब होती बात नहीं है। सही बात तो यह थी कि इन मिल वालों से इनकी मिलीभगत थी जिसके कारण किसी जमींदार की पेमैंट टाईम पर नहीं होती थी। पेमैंट न होने से अब लड्ड बज रहा है। इनकी सरकार के वक्त के पुराने बिल अब इस सरकार के आने के बाद क्लीयर हुए हैं। (विघ्न) क्या नारायणगढ़ मिल में घटनाएं नहीं घटीं और क्या यमुनानगर मिल में लड्ड नहीं बजा ? जब भी गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में आई तो यह ख्याल पैदा हुआ कि अनाज की पैदावार कम होनी चाहिए। स्पीकर सर, मुझे 1977 की बात याद है। उस वक्त प्राईम मिनिस्टर का ब्यान आया था कि किसान अपनी कणक और जीरी देख कर पैदा करें क्योंकि हम सारी कणक और जीरी नहीं खरीद सकते, हम इसको खरीदने की गारन्टी नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह प्रोग्राम 1980 में शुरु किया था और सपोर्टिंग प्राईस इन्ट्रोडयूस की थी। इनकी निगाह इस बात पर रही है कि किस प्रकार से इनको ऊपर नीचे कर दें। (विघ्न) इनके राज में जब अटल बिहारी बाजपेयी प्राईम मिनिस्टर थे तो ये लोग उनको कुरुक्षेत्र में ले कर आये और वहां पर इन्होंने ब्यान दिया कि फूलों की खेती शुरू कर दो क्योंकि हमारे पास अनाज खरीदने की क्षमता नहीं है और कोई अनाऊसमैंट तो वहां पर स्टेट के बारे में ये नहीं करवा पाए थे। वहां पर इन्होंने सिर्फ एक मांग रखी थी कि शताब्दी ट्रेन कुरुक्षेत्र में रूका करेगी। ये देश के प्रधान मंत्री को हरियाणा में लेकर आए और यह सब स्टेट में करवाते रहे थे।

इसके साथ ही मैं सदन में यह बात बताना चाहूंगा कि पापूलर की खेती करने का अल्टरनेट भी किसानों ने ही ढूंढा था। उन्होंने सोचा था कि अगर जीरी, कणक खतरे में पड़ने वाली है और गोदामों में बहुत ज्यादा अनाज हो गया है तो हम पापूलर की खेती ही शुरु कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के राज में 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पापूलर बिका था। इसके बाद किसानों ने तो कसम खा ली थी कि वे पापूलर की खेती कभी नहीं करेंगे। जबकि उस समय किसानों को यह समझाया जा रहा था कि जीरी और कणक की फसल को छोड़कर किसी और काम में भी हाथ डालें। उस वक्त किसान पापूलर की खेती की तरफ बढ़ा लेकिन इसमें भी उसका बुरा हाल कर दिया गया था लेकिन आज की हुड्डा सरकार ने उसके लिए कोई भी कानून नहीं बनाया और पापूलर का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। यह इसलिए है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने अच्छे दाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज इनकी कारखानेदारों से कोई मिलीभगत नहीं है। ये किसानों के हितों के बारे में सोचते हैं इसलिए किसान को अच्छे दाम मिल रहे हैं। आज की तारीख में किसानों ने पापूलर दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अब ये यहां पर कहते हैं कि कणक बाहर से मंगवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश 110 करोड़ की आबादी वाला देश है, इतनी आबादी के लिए अनाज का इन्तजाम करने के लिए हमारी सरकार को चिन्ता रहती है कि कहीं लोगों के लिए अनाज की कमी न पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज 100 रुपये प्रति क्विंटल कनक के रेटों में इजाफा भी हुआ है। किसानों को खुशी होती है अगर मण्डियों में कणक महंगी है। इसकी वजह से किसान अपनी मर्जी से जब चाहे कणक बेच सकता है। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्टिंग प्राईस पर पिछली सरकार ने एक बार तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया था लेकिन हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कह दिया था कि स्पोर्टिंग प्राईस पर कोई कम्प्रोमाईज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं कर्जा माफी के बारे में बोलना चाहता हूं।

ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1987 में पहला राज कर्जा माफी के नारे पर ले लिया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए छोटे बड़े लोन देने के लिए मेले लगा रही थी। उस वक्त इन्होंने कर्जे माफी के सिस्टम को ऐसा धक्का लगाया कि उस सिस्टम को बिल्कुल ही ध्वस्त करके रख दिया। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो किसी का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। हमें हमारे किसान भाइयों के दु:ख दर्द का अहसास है, क्योंकि हम भी किसान हैं। किसानों ने हमेशा दिक्कत में जीवन व्यतीत किया है। उसने सारी दुनिया का पेट भरा है और खुद भूखा सोया है। स्पीकर सर, खेतीबाड़ी कभी भी तरक्की और आमदनी का साधन नहीं रहा है। खेती किसान का गुजारा मात्र ही काम चलाती रही है। जब से सृष्टि बनी है तब से किसान यह काम कर रहा है लेकिन किसान हमेशा दिक्कतों में रहा है क्योंकि यह धन्धा कोई मुनाफे का धन्धा नहीं है। लेकिन दुनिया में आज भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है और इसके बिना कोई काम नहीं चलता है। स्पीकर सर, मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे सरकारी खजाने में गुंजाईश हो तो यह सरकार कभी भी किसानों की मदद कर सकती है। सरकार उसको बोनस दे दे, सबसिडी दे दे और कहीं पर कोई रियायत देने की जरूरत हो तो वह भी दे। जब हम कर्जा माफी की बात करते हैं तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को बहुत धक्का लगता है क्योंकि एक तरफ तो हम आसान तरीके से छोटी दरों पर लोन मांगते हैं और दूसरी तरफ कर्जा माफी की बात करते हैं। काफी समय पहले किसान 2 रुपये और 5 रुपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज भरते थे, लेकिन अब यह ब्याज दर बहुत ज्यादा हो गई थी। हमारी सरकार ने उस ब्याज दर को अब कम किया है। हमारी सरकार इसको 7 से 6 और 6 से 5 रुपये प्रति सैंकड़े पर ले आई है और मुझे उम्मीद है कि ये उसको और कम लेकर आएंगे। स्पीकर सर, अब ये कहते हैं कि इनके वक्त में किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि जो आदमी कर्जे लेकर वापिस ही न करे तो उनका तो माफ ही है। स्पीकर सर, बहुत ही मुश्किल है किसी किसान की जमीन को कुर्क कर देना और उसको जमीन से बेदखल कर देना।

श्री अध्यक्ष : निर्मल सिंह जी, आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। आप कन्कलुड करें।

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर सर, बड़ी ही मुश्किल हो जाती है जब किसान की जमीन कुर्क हो जाती है। इसके बाद तो उसका लेन-देन ही बंद हो जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस तरह से इमदाद करनी चाहिए ताकि उसको लोन की किस्त देने में आसानी रहे और उसका लेन-देन चलता रहे। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं इरिगेशन से सम्बन्धित मामले के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर भाखड़ा से 27 क्यूसिक कपैसिटी का नाला बना रहे हैं और वह नाला कभी का मंजूर है। जब चौटाला साहब की सरकार आई थी तब से ही वहां पर यह काम पैंण्डिंग था। स्पीकर सर, उसका अर्थवर्क हो चुका है लेकिन अब उस नाले को दादूपूर नलवी से जोड़ा जा रहा है। स्पीकर सर, दादूपूर नलवी का प्रोजैक्ट बहुत ही लम्बा है और वह सीजनल है। स्पीकर सर, हमारा 27 क्यूसिक कपैसिटी वाले नाले का मामला है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको दादूपूर नलवी के साथ न जोड़ा जाए बल्कि इसको उसी तरह से बनवाया जाए जिस तरह से वह मंजूर हुआ था। स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली) : स्पीकर सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष : आप कितनी देर बोलना चाहेंगे ?

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी देर आप कहेंगे मैं उतनी देर ही बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप 6 मिनट बोल लें।

चौ० अर्जन सिंह : ठीक है जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है इसी तरह से कई लोग तो अपनी जिंदगी से भी खुश नहीं है। इसलिए आप इनकी परवाह न करें और जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। मैं आपकी भावनाओं की और आपकी सोच की दाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी के बाद अगर कोई अच्छा या सबसे बढ़िया मुख्य मंत्री आया है तो वह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हैं। सरकारें तो बहुत रहीं लेकिन वे सरकारें आठ-आठ आने के लिए किसानों को पीटा करती थीं। मुख्यमंत्री जी जिस किसान कैटेगरी पर रहम कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छी बात है। गैलरी में जो लोग बैठे हैं ये सारे इन बातों को देख रहे हैं। अखबार तो जिसके घर जाएगा वही ये बातें पढ़ेगा लेकिन ये लोग अपने-अपने यहां पर जाकर बताएंगे कि यहां पर क्या-क्या हो रहा है। आज हर आदमी अपना नफा नुक्सान समझता है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब की सरकार में कई-कई फुट लम्बें बोर्डज लगे लेकिन उनको पढ़ने के लिए किसी के पास टाईम नहीं था और न ही किसी को उनसे खुशी थी इसलिए उनको किसी ने नहीं पढ़ा। अगर उस समय वे इन बोर्डज की जगह सड़कों के गड्ढे ठीक करवा देते तो लोग अपने आप ही उनकी एडवरटाइजमैंट कर देते। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों का लोगों ने उनको रिजल्ट भी दे दिया है। जब तक जमींदार और किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक सारा देश या प्रदेश खुशहाल नहीं होगा। जब जमींदार के पास या किसान के पास पैसा होगा तभी दुकानें खुलेंगी और तभी कारखाने चलेंगे। जब इनकी हालत ठीक होगी तभी सारे काम ठीक होंगे। मैं चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अगर वे मौजूद होते तो उनके सामने ही कुछ कहने को अच्छा लगता। मुझे बी०जे०पी० के नरेश मलिक की बात भी ठीक नहीं लगी। हालांकि गौतम साहब ने ठीक बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश का नाश करने में चौटाला साहब के साथ-साथ इन लोगों का भी सहयोग रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो काम किए मुझे नहीं पता कि उनसे जनता की कितनी भलाई हुई ? उन्होंने केवल चौधरी देवीलाल के बुत ही बहुत तेजी से बनवाकर लगवाए। पता नहीं इससे पब्लिक का क्या हित हुआ ? इसी तरह से जो पेड़ थे उनको भी इन्होंने कटवा दिया। जिस सड़क से ये निकल गए उसी से इन्होंने पेड़ों को कटवा दिया। कितनी मेहनत से वे पेड़ सब जगह लगाए गए थे। मेरे एरिया में भी एक भी पेड़ इन्होंने नहीं छोड़ा।

श्री अध्यक्ष : इनको कौन ले गया ?

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यही लोग ले गए और कौन ले गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया छछरौली में इनका 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम था। लोग बड़ी उम्मीद से वहां पर गए थे। कोई वहां पर स्कूल की डिमांड लेकर गया, कोई वहां पर सड़क बनाने की डिमांड लेकर गया और कोई वहां पर धर्मशाला बनाने की डिमांड लेकर गया लेकिन इन्होंने किसी से डिमांड नहीं पूछी। ये कहने लगे कि क्या आपके यहां वृद्धावस्था आश्रम है, क्या शमशान घाट का रास्ता ठीक है ? ये उनसे डिमांड पूछने के बजाए अपनी तरफ से ही कहने लगे कि क्या शमशान घाट ठीक है ? पता नहीं इनकी क्या नीयत थी ? क्या ये सबको शमशान घाट पहुंचाना चाहते थे ? ये सोचते थे कि अगर किसी को गोली लगेगी तो वह शमशान घाट ही जाएगा। इसलिए इसका रास्ता ठीक

होना चाहिए। इसके अलावा ये आज पानी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी करते हैं कि पानी नहीं आया है। लेकिन जब आदमी की नीयत ठीक होती है तो उस पर भगवान भी दया करता है। आज जब भी पानी मांगो भगवान तभी बरसात कर देता है। इसी तरह से इन्होंने बिजली के बारे में भी कुछ नहीं किया। ये तो केवल अपने आप ही ऐश करते रहे। ये तो अपने जंगल के हाथ भी बिस्लरी के पानी से धोते थे। चाहे सारे देश या प्रदेश में कुछ भी होता रहे। इनके मंत्री जनता की 14.00 बजे परवाह नहीं करते थे। वे जनता की तरफ एक बार भी नहीं देखते थे। अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं कि ये कहां से अपना भाषण देना शुरू करते थे। लोग भी भोले हैं, सोचते हैं कि इसको भगवान ने अक्ल दे दी होगी। लोग यह भी सोचते हैं कि यह अपना पिछले कर्मों का खामियाजा भुगत रहा है । अब की बार सही हो गया होगा। यह अपना भाषण यहां से शुरू करता था कि चैत्र और बैशाख की तपती लू में, सावन भादों की अन्धेरी रात में, सांप और बिच्छुओं की परवाह न करते हुए धरती माता का सीना चीरकर जब किसान का बेटा खेत में अनाज पैदा करता है और बाद में उस उपज को मंडी में ले जाता है और यदि इस उपज का सही उसको दाम नहीं मिलता है, भाव नहीं मिलता है, बोली लगती है तो उसको बहुत दुःख होता है। वह कहता था कि बोली किसकी लगती है । जिसका कोई मालिक नहीं होता। इस तरह से साढ़े पांच साल तक यह किसानों का मालिक बना रहा लेकिन उसने किसी की ट्राली उठने नहीं दी। आज हुड्डा साहब की सरकार के समय में वही ट्राली 7500 की जा रही है। पहले पॉपूलर की 12 हजार की ट्राली जाती थी, उसमें खुंटे बचते थे उसमें चाय पीकर अपने घरां ने चले जाया करां थे लेकिन आज वही ट्राली 62 से लेकर 65 हजार रुपये तक बिक रही है जिसकी वजह से अब कोई नये ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, किसी के घर चिनाई लग रही है । जबकि पिछले पांच साल में किसी ने नलके का फर्श तक पक्का नहीं कराया था। पहले तो उनकी मोटर साईकिल बिकती थी, ट्रक बिका करते थे। ट्रैक्टर बिका करते थे मतलब कि सिर्फ बिकने का काम होता था लेकिन अब हर घर में रोज मोटर साईकिल आती है और किसी के घर अच्छी शादी हो रही है। पॉपूलर के जो पत्ते हैं उनसे ही आज इतने पैसे मिल जाते हैं कि गरीब की मजदूरी निकल आती है। ये कहते हैं कि दाल महंगी हो रही है। अगर पैसे होंगे तो कोई कुछ भी खरीद लेगा। अगर अठन्नी जेब में न हो तो कोई क्या खरीदेगा ? स्पीकर सर, हमारी पार्टी तो सौ परसैंट जीतकर आई है, सैंट परसैंट जीतकर आई है। इनेलो के साढ़े आठ रह गए, बी०जी०पी० के पहले 11 में से 6 आए थे लेकिन इस बार छह में से दो रह गए। आगे से तो लगता है कि परमात्मा लाएगा भी नहीं। (विघ्न) आज जैसे मैं विपक्ष का एम०एल०ए० हूं तो मेरे को एक भाई कहने लगा कि तू इतना चौटाला के खिलाफ क्यों बोलता है। मैंने कहा क्या कर लेगा तो वह बोला कि पता नहीं क्या कर लेगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा मार देगा। मरने से क्या डरना। मरने से तो वह डरता है जिसने मरना न हो। जब मरना ही है तो दस दिन पहले मर जाएंगे। मेरे से छोटी उम्र के भी कई मर जाते हैं। कोई जन्म लेते ही मर जाते हैं। पानी की धार पर तो मुर्दा भी बहकर चला जाता है पर पानी की धार का मुकाबला करना सीखो।

श्री अध्यक्ष : चौधरी अर्जन सिंह जी, अब आप बैठें।

चौ० अर्जन सिंह : सर, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की दो-तीन बातें बताना चाहूंगा। मेरे हल्के में थर्मल पावर प्लांट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2300 करोड़ रुपये की प्रोपोजल बनाई थी। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमाण्ड की कि इतने में गुजारा नहीं होगा क्योंकि जमीन से काफी नुक्सान लोगों को हो गया है तो माननीय

[चौ० अर्जन सिंह]

मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त 5000 करोड़ रुपये तक उसको बढ़ा दिया। इसी प्रकार से मैं बांध के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार ने अवैध गणना करके ऐसे जौन बनाये कि लोगों को बर्बाद करके रख दिया लेकिन आज की सरकार ने लोगों को बचाने के लिए बांध बनाये हैं। कैप्टन साहब और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी वहां पर खुद जाकर आये हैं और मुख्यमंत्री जी की दया से वहां पर पोजीटिव रिजल्ट आये हैं नहीं तो वहां के 25-30 गांव हर साल बर्बाद हो जाते थे। इसी प्रकार से मैं बस स्टैण्ड के बारे में बताना चाहता हूं। एक बस स्टैण्ड बनाने की डिमाण्ड मैंने माननीय श्री सुरजेवाला जी के सामने रखी थी। माननीय सुरजेवाला जी ने मुझे खुद टेलीफोन करके यह बताया कि आपके हल्के में जो बस स्टैण्ड बनना था उसके लिए 40 लाख रुपये मन्जूर कर दिये हैं। इसी प्रकार 8 सड़कें जो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनानी थी उनमें से 8 में से 6 सड़कें मन्जूर कर दी गई हैं और उनका 85-90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 70 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत हो चुकी है और जो सड़कें रह गई हैं वे सरकार की वजह से नहीं ठेकेदारों की कमी के कारण बची हुई हैं। इसी प्रकार एस०ई०जैड० के बार में बताया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय जिस आदमी के पास एक एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, हल है उसको आज 15-20 लाख रुपये का प्रोफिट है क्योंकि उसे न तो हल जोतना पड़ता है, न ट्रैक्टर चलाना पड़ता है और न ही पानी देना पड़ता है क्योंकि अब उसकी जमीन का भाव 15-20 लाख रुपये प्रति एकड़ है अब उस आदमी को काफी आमदनी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, आपका समय समाप्त हो चुका है।

चौ० अर्जन सिंह : सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा (मुंढाल खुर्द) : स्पीकर साहब, आपने मुझे जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह अभिभाषण अपने आप में इतना अच्छा अभिभाषण है कि इस हाउस का कोई सदस्य इसकी आलोचना नहीं कर सकता। इस अभिभाषण में सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। सरकार की मन्शा प्रदेश को नम्बर एक राज्य बनाने की है। इस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाये भी जा रहे हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं भी इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रत्येक फील्ड में आज जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी बाकी सदस्यों ने बहुत सराहना की है और मैं भी उनके विचारों से सहमति रखता हूं। मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों को माफ किया है और दूसरी स्कीमों से जिन लोगों को फायदा पहुंचा है वे लोग आज भी मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का गुणगाण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1968 में हरियाणा प्रांत में जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय प्रत्येक गांव में बिजली की तारें बिछाई गई थीं उनकी उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में काफी अंतर है। चाहे वह शहर हो, चाहे गांव हो, आज भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनमें मकानों के ऊपर बिजली की तारें निकल रही हैं जिनकी वजह से हर रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी दरिया दिली से 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ किए हैं उसी तरफ से मकानों के ऊपर से निकलने वाली इन तारों का भी प्रबन्ध किया जाये। मुख्यमंत्री जी कोई ऐसी स्कीम लेकर आयें जिसके तहत शहरों और गांवों के जिन मकानों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं उनको दूर किया जाये ताकि जो दुर्घटनाएं इन

तारों की वजह से हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी पदासीन हुए) सभापति महोदय, अब मैं बी०पी०एल० कार्ड के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि दोबारा से सर्वे होगा। लेकिन इस बारे में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बी०पी०एल० के कार्ड बनाने से जो हमारे लोग अब तक रह गये हैं उनके बारे में केन्द्र सरकार से बात की जाये कि वह कार्ड बनाने में कुछ रिलैक्सेशन दें ताकि इसका दायरा बढ़ जाये और जो 25-30 प्रतिशत लोग रह गये हैं वे भी इसका फायदा उठा सकें। सभापति महोदय, अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने मिनी स्टेडियम बनाने के बारे में जो घोषणा की थी वह स्कीम चल रही है। उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मिनी स्टेडियम बनाने से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको चाहिए कि जिस किसी भी स्टेडियम का नक्शा बनाया जाये और उसमें जिन-जिन सुविधाओं का प्रावधान किया जाये वह आने वाले 10-15 सालों को मद्देनजर रखते हुए किया जाये ताकि जो स्टेडियम बने वह आऊट डेटिड न हो और उसका पूरा यूज हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पोर्ट्स से संबंधित एक बात और करना चाहूंगा कि पिछले सैशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने ओलम्पिक्स गेम्ज में, कॉमन वैल्थ गेम्ज में और ऐशियाड गेम्ज में कौन-कौन सा मैडल अब तक जीता है और कौन-कौन से अधिकारी खिलाड़ियों के साथ गये। इसका जवाब आया कि विभाग के पास रिकार्ड नहीं है। सभापति महोदय, मेरी मंशा यह नहीं है कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं। मेरी मंशा तो केवल यही है कि स्पोर्ट्स विभाग अपना रिकार्ड पूरा रखे कि 1952 से लेकर आज तक ओलम्पिकस गेम्ज में, एशियाड गेम्ज में, कॉमन वैल्थ गेम्ज में और नेशनल गेम्ज में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता और किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, इस तरह का सारा रिकार्ड एकत्रित करके प्रदेश में एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि जब हरियाणा प्रांत बना था उसके बाद से हरियाणा के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स में क्या-क्या उपलब्धियां हांसिल की हैं ? इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ओलम्पिकस, एशियाड, कॉमन वैल्थ और नैशनल गेम्ज में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड देने की बात कही है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया जायेगा। मुझे पता चला है कि नेशनल गेम्ज में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 31,000 रुपये कैश अवार्ड के रूप में दिए जायेंगे। अवार्ड तो अवार्ड है चाहे वह एक रुपये का हो लेकिन आज के आधुनिक समय को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यह अवार्ड की राशि काफी कम है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि ओलम्पिक गेम्ज में अगर कोई गोल्ड मैडल लेकर आता है तो उसको कम से कम 10 लाख रुपये, एशियाड वाले को 7 लाख रुपये, कॉमनवैल्थ गेम्ज के लिए 5 लाख रुपये और नेशनल गेम्ज में जो गोल्ड मैडल लेकर आता है तो उसको 3 लाख रुपये का अवार्ड होना चाहिए यह मेरा सुझाव है अगर इसको कंसीडर किया जाता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। मील अलाऊंस की जहां तक बात है, जब से हरियाणा बना था तब से लेकर 50 रुपये डाईट चली आ रही थी लेकिन आज के महंगाई के समय को देखते हुए यह बहुत बहुत कम है। मैंने पिछली बार ऑन दा फलोर ऑफ दा हाऊस यह कहा था कि 50 रुपये बहुत कम हैं इसको बढ़ाकर 150 रुपये कर दीजिए तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि इसको अभी 100 रुपये कर देते हैं बाकी बाद में देख लेंगे। अब मेरी प्रार्थना है कि इसको बढ़ाकर 200 रुपये कर देना चाहिए क्योंकि आज मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जो मैडलस लेकर आते हैं उनके गाँवों को आदर्श गाँव बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे प्रान्त के लोग उन पर फख्र करते

[श्री रणधीर सिंह महेन्द्रा]

हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करूँगा कि 1952 से लेकर आज तक एशियाड में, ऑलम्पिक्स में, कॉमनवैल्थ गेम्स में या नैशनल गेम्स में अगर किसी ने मैडल लिये हैं तो उनके गावों को भी अगर आदर्श गाँव घोषित कर दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी। भ्रूण हत्या की बुराई को समाप्त करने के बारे में जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा गया है कि मेरी सरकार ने लिंगानुपात में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत करने की एक नई योजना भी शुरु की है। इस योजना के बारे में मैं सुझाव देता हूँ कि पुरस्कृत करने के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये जो कि वाकई में बड़ी लुभावनी हो और इफेक्टिव हो। आम तौर पर देखा गया है कि इस बारे में साल के अन्त में कोई न कोई शील्ड या कोई और चीज दे दी जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस बारे में एक्ट में एमैंडमैंट किया जाए और पंचायतों को 5 साल की बजाय 10 साल के लिए समय दिया जाये ताकि लिंगानुपात में जो कार्य किया जाये उसके बारे में लोग जरूर यह समझें कि इसमें जो इनसैंटिव मिलेगा वह बहुत अच्छा मिलेगा। महामहिम का अभिभाषण जैसा मैंने पहले बताया बहुत अच्छा है और मैं इसको स्पोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं अधिकारियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब उनकी आलोचना करना नहीं है। जब से यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक हरियाणा में लॉ एण्ड ऑर्डर में काफी सुधार हो चुका है जिसके कारण आज प्रत्येक इन्सान सुख की साँस लेता है क्योंकि उसको कोई भय नाम की चीज नहीं है। लेकिन इस अभिभाषण में सिर्फ एक बात लिखी गई है कि अपराध सुलझाने की संख्या में बहुत सुधार हुआ है। मैं यह समझता हूँ कि crime rate has gone down like anything. इसमें परसैन्टेज देनी चाहिए कि कितने परसैंट उसमें क्राईम डाऊन कर दिया। अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जब मेरे पूज्य पिता जी का इन्तकाल हुआ था उस समय हमने मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना की थी कि उनके स्टेट्स को देखते हुए उनकी यादगार में कोई ऐसी चीज हो जो उनके स्टेट्स के लायक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि जरूर कोई न कोई ऐसी चीज सोच-समझ कर की जाएगी जो ऐप्रिशियेटिव टू हिज स्टेटस होगी। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर वे एक बार गौर करें और in the memory of late Chaudhary Bansi Lal ji कोई न कोई ऐसी यादगार चीज जरूर हो जिसका स्टेटस न केवल नैशनल बल्कि इन्टरनैशनल लेवल का हो। चेयरमैन सर, इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह (बरवाला) : चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अभिभाषण में बताया गया है कि वार्षिक योजना 2006-07 के लिए स्वीकृत परिव्यय की तुलना में हमारी सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करके अब तक के सर्वाधिक खर्च के स्तर को प्राप्त किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि से उपजे समुचित विश्वास की बदौलत 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सरकार को भारतीय योजना आयोग से 35000 करोड़ रुपये के परिव्यय की मन्जूरी मिली है और वर्ष 2007-08 का वार्षिक योजनागत परिव्यय 5300 करोड़ रुपये है। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक खर्च से 40% अधिक है। यह रिकार्ड वृद्धि है और यह वर्ष 2004-05 के वास्तविक खर्च से अढ़ाई गुणा ज्यादा है। चेयरमैन सर, अब मैं कृषि क्षेत्र के ऊपर आ जाता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी

योजनाओं की घोषणाएं की और वे योजनाएं लागू भी कीं। पिछले वर्ष मुख्य फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का 44.98 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जो कि अब तक का रिकार्ड उत्पादन है। हमारी सरकार ने गन्ने की पिराई के सीजन में हरियाणा के किसान को 138 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे कर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। चेयरमैन सर, कल गन्ने के बारे में जो चर्चा हुई थी हमारे तत्कालीन मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा था कि मेरी सरकार के समय में 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के रेट्स दिये गये थे। ये रेट्स दिये तो गये थे लेकिन उस समय किसान की जो हालत थी यह सबको मालूम है। किसान ने उस वक्त जो गन्ना डाला था दो वर्ष तक उसकी पेमैंट नहीं की गई थी। आज हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने गन्ने का 138 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने के बाद भी किसानों को कैश पेमैंट की है जो कि एक सराहनीय कार्य है। चेयरमैन सर, अब मैं कृषि से जुड़े हुए पशुधन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश कृषि से जुड़ा हुआ प्रदेश है। मैं पशुधन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने मुंह-खुर बीमारी की रोकथाम, पशुओं की प्रजनन सुविधाओं का विस्तार करने और गौशाला में पशु चिकित्सा संस्थान खोलने जैसे कई काम चला रखे हैं। भिवानी, हिसार, झज्जर, जीन्द और रोहतक जिलों में पायलट आधार पर एक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत 50% भारत सरकार का और 25% हरियाणा सरकार का हिस्सा है जिससे एक लाख 20 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। मुर्राह नस्ल की भैंस के विकास के लिए भी सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। 554 करोड़ रुपये की एक परियोजना भारत सरकार को भेजी गई है। यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। 174 पंजीकृत गौशालाओं को एक लाख रुपये अनुदान देने की जो योजना है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। हरियाणा प्रान्त देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में दूसरे स्थान पर है। सौ से दो सौ लीटर दूध इकट्ठा करने वाले हमारे किसी भी साथी को 25 पैसे प्रति लीटर का कमीशन तथा 200 लीटर से अधिक दूध इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को हमारी सरकार पचास पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन देती है। यह हमारी सरकार बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है। महिलाओं को इसमें 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अधिक कमीशन दिया गया है। चेयरमैन सर, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में मुर्राह नस्ल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसके लिए मिल्क कम्पीटीशन करवाया जाता है और इस मिल्क कम्पीटीशन में हमारे किसान साथी भैंसों को ले कर आते हैं। वहां पर जो भैंस 12 लीटर दूध देती है उसको 1 हजार रुपये का ईनाम दिया जाता है, जो भैंस 15 लीटर दूध देती है उसको 5 हजार रुपये का ईनाम दिया जाता है जो भैंस 18 लीटर या उससे ज्यादा दूध देती है उसको कोई 6 हजार रूपए दिया जाता है लेकिन जो भैंस 20 लीटर या उससे ज्यादा दूध देती है उसको कोई ईनाम देने का प्रोवीजन नहीं है और न ही उस बारे में कोई कैटेगरी बनाई गई है। चेयरमैन सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बारे में चार कैटेगरीज बनानी चाहिए और ईनाम की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मुर्राहा भैंस की नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। चेयरमैन सर, कल सदन में बिजली के बारे में बहस चल रही थी, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए कहा कि इस सरकार के राज में हरियाणा में एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी का तकरीबन पौने 6 साल राज रहा है मगर उनके वक्त में कोई भी थर्मल प्लांट लगाने की या दूसरी कोई बिजली पैदा करने की योजना नहीं बनाई गई थी। बिजली के लिए उनके राज में कोई काम नहीं हुआ था। मैं आपके माध्यम से

[श्री रणधीर सिंह]

सदन में बताना चाहूंगा कि आज की सरकार के राज में 4-5 थर्मल प्लांटस हरियाणा में लगे हैं और आने वाले वर्षों में हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का वायदा भी किया है। इसके साथ-साथ मैं अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज एक्ट, 1984 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया है जिनके तहत कर्ज अदा न कर सकने वाले किसान को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2006 से कृषि ऋणों के ब्याज की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की गई है। यह भी इस सरकार का एक सरहानीय कदम है।

चेयरमैन सर, इसके अलावा हैफेड ने 2006 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की 4.62 लाख मीट्रिक टन सरसों की फसल खरीदी थी। इसी तरह से किसानों के हितों की रक्षा के लिए हैफेड ने रबी की फसल की खरीद के लिए भी 2007 के लिए पहले से एक समूचित व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 2007-08 में 26.56 करोड़ रुपए की एक गन्ना विकास योजना भी तैयार की है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है।

चेयरमैन साहब, सिंचाई व्यवस्था के बारे में मैं सदन में बताना चाहूंगा। इस बारे में ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि इस सरकार के कार्यकाल में सिंचाई की व्यवस्था का कार्यक्रम सही नहीं है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के वक्त में किसानों की जमीन का कुछ हिस्सा ही ऐसा था जहां पर पानी दिया जाता था लेकिन आज के हरियाणा के मुख्यमंत्री के वक्त में हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई भी हिस्सा हो, वे उसको समान समझते हैं और सभी जगहों पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए पानी के कार्यक्रम को समान रूप से चला रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार दादूपुर नलवी नहर बनाने के लिए 267 करोड़ रुपये दे रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने सिरसा रैली में किसानों के जितने भी वाटर कोर्सिस थे उनकी सफाई एवं छंटाई करने का एक साल का समय मांगा है यह इनका बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री सभापति : ठीक है, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यह 2068 एकड़ में स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही खानपुरा कलां में भगतफूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसके अलावा जींद में भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सैन्टर का कार्य चल रहा है। चेयरमैन सर, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने प्राईवेट अधिनियम लागू किया है। चेयरमैन सर, राजकीय

छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 50 हजार प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत करने की योजना है। अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 10+1 और 10+2 के अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सराहनीय प्रोग्राम है। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से पूछना चाहता हूं कि सन 1987 में इन्होंने एक चन्दा इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया था। उस समय कहा गया था कि इससे गाड़ियां दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ उस समय 'जन संदेश' नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला गया था। इसके लिए भी हरियाणा की जनता से चंदा इकट्ठा किया गया था। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यह पैसा कहां गया ? चेयरमैन साहब, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि चौटाला साहब के उस समय के कार्यकाल में जब आपके ऊपर तथा श्री तेजेन्द्रपाल मान, चौधरी जय प्रकाश, श्री कर्ण सिंह दलाल, श्री चरणदास शोरेवाला आदि के खिलाफ जो राजनीतिक केस दर्ज किए गए थे तो इस बात की भी मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी करवाएं कि क्या ये केस सही दर्ज किए गए थे या नहीं और अगर वह झूठे साबित होते हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मिसयूज ऑफ पावर के लिए केस दर्ज करवाया जाए। चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj (Bhiwani) : Thank you Sir, First of all, I would like to express my heartfelt condolences for the victims of Samjhauta Express. I am happy to know that the activities of Government are taking the State forward and trying to transform it into No. 1 State in the Country. It is a matter of pride for all Haryanavis that our Government has got the approval of Planning Commission of India for an outlay of Rs. 35,000/- crores for 11th Five Years Plan. In agriculture, early sowing of wheat and treatment of seeds before sowing has brought positive results. Increasing forest and trees cover in the State by 10 per cent by 20 per cent will improve the Eco-system. Waiving off of interests on the loans of cooperative societies will go a long way to help the farmers, petty shop-keepers and Scheduled Castes & Backward Classes of the State who have taken loan from Co-operative Societies. Our State is a milk producing State and Haryana Dairy Development Federation has launched a number of new products. But in this regard, I would like bring to the notice of this august House that Milk Plant at Bhiwani needs due attention. It used to manufacture condensed milk and ghee but now it is reduced to a chilling plant only. So, I would like to request to the Government that it should also come to function in full swing. I would also request the Government to start the veterinary hospital at Village, Rajgarh because there is lot of animals in that area and attention in this regard is also needed. As far as irrigation is concerned, it is nice to note that 109 k.m. long BML-Hansi-Butana Branch carrying 2,000 cusecs of water to South Haryana is getting ready to this year. In my area there are three scheme, which have been sanctioned, one is Paluwas Minor, second is Sanga Minor and another is Pump House at Rupgarh, R.D. 7000. I would request the Irrigation Minister that these schemes should also be started at an early date. Drainage of Bhiwani city needs to be improved as water-logging starts and becomes a great problem even in small and little rains and work on

[Dr. Shiv Shankar Bhardwaj]

Bhiwani-Ghaggar Drainage needs to be expedited because this project has been approved by the Irrigation Minister, it is in a pipeline and it needs to be expedited. As far as power is concerned, I would like to bring to the notice of the House that augmentation of MVA capacity of 220 KV at Bapora, is needed. It supplies electricity to the city and till 132 KV station is commissioned at Halwas, something must be done in this regard. 133 KV station is also needed at Village Dhareru. Most of the new transformers are trapping. Either additional transformers should be installed or transformers of increased capacity should be installed there. As far as industry is concerned, Bhiwani needs special attention because many factories have been closed like Mohta factory, Century Tubes, Rama Fiber, Saraswati factory and Kiran Ghee factory. There were about 7000 workers in TIT but now they have reduced to 500. In this regard, it is nice to note that new industrial model townships are being initiated at Faridabad, Rohtak, Jagadhari & Kharkhoda. Bhiwani should also be included in this. We have an oldest college of textile in the State and I would request to the governmet that textile-hub be set up at Bhiwani. As far as excise policy is concerned, the allotment by draw of lots has eliminated monopoly and it has brought about positive results and transparency as well. As far as education is concerned, the EDUSAT and smesterisation will go a long way in ensuring regularity and will decrease stress on children. Regional centres have been opened in Jind and Mirpura but one such centre is needed at Bhiwani as well. Sir Chottu Ram College of Murthal has been upgraded to University of Science and Technology and like on the same pattern the Institute of Textiles and Science at Bhiwani should also be upgraded to Pt. Neki Ram Sharma University of Science and Technology. One TIT is also needed in my area in village Nandgaon in Bhiwani constituency, Hon'ble Chief Minister Sahib has already approved a girls school in Bhiwani. There is only one girl school in Bhiwani and there are 2500 students and it runs in 2 shifts. Hon'ble Chief Minister has already sanctioned this school, I will just request that the matter should be expedited so that girls child could be provided the educational facility. It is very nice to note that fresh survey for BPL has been ordered and it will bring justice to the deserving people of the State. As far as Urban Development is concerned, I feel lot of money has been flown to M.Cs in the State. My only concern is that it should be properly utilized and there should be strict control on quality. HUDA has brought about Asiana Scheme and ISDPC *i.e.* Integrated Slum Development Project of Centre and it has given hope to the homeless people to get a home in the State. I would like to thank, Madam Seiija Ji, who is from Haryana and who has sanctioned Rs. 29 crores for Bhiwani. I think this is the first time that such lot of money is coming to eliminate slums in our State and specially for Bhiwani. Here, I would also request to the government that Bhiwani has so many Ex-Army people, so there should be a defence colony and few more sectors of HUDA should come up in Bhiwani. I am thankful to our Chief Minister for sanctioning two Railway Over-Bridges in Bhiwani and I would like to mention here my special thanks to Mr. Depeender Hooda, Member of Parliament from Rohtak as he was very instrumental in getting the sanction from the Centre. I would like to bring to the notice of the Govt.

that two more bridges are in fact required in Bhiwani, one at Meham road near the Air Strip, and another at Jituwala Phatak. There should be one Bye-pass also in Bhiwani which should connect Rohtak road to Hansi road. As far as Public Health is concerned, I must congratulate C.M. for providing 340 crores for Indira Gandhi Drinking Water Scheme for individual water connection to the S.C. families. I would like to mention here that I have seen smiles on the faces of females of S.C. families when I visited the Constituency and water was flowing in the houses of these S.C. families and they were feeling very happy. I must congratulate our Commissioner Sh. Dalip Singh Ji also for taking keen interest in this regard and providing water to these families. Sir, as far as Health is concerned, it is a very nice matter that PGIMS Rohtak has been declared as Centre of Excellence but I would be failing in my duty if as a doctor, as a surgeon, as a past student of the Medical College Rohtak and a member of this House, I would not bring ground realities to the notice of all. Neuro Surgery Department used to function quite well but at present there is no Neuro Surgeon in Medical College, Rohtak. Sir, any patient coming with head injury or tumor in the head that needs to be referred to Delhi or other Centres. Likewise, we do not have a dedicated Gastrology Centre in Rohtak. If some patient has a stone in the Gall Bladder and if that stone goes into the common Bile duct, it canot be removed endoscopically at Rohtak. The patient has to be referred to a higher Centre. Likewise, we do not have any Retinal Surgeon at Rohtak and this being one of the best Centres in our State, Renal transplant has not yet started. I feel that these specialties should be developed. In this regard, I would like to bring to your notice that there are many vacancies in Bhiwani Hospital also, which should be filled up. I had already been telling that Bhiwani has got full infrastructure for coming up as a Medical College and something should be done in this regard also. My only concern is that infrastructure already exists but we have to just bring about functional competence in this regard.

As far as road safety is concerned, we must do little more in this. I am happy that Mr. Surjewala is doing a lot because the loss of young lives is quite more in these accidents and whatever has been done in female foeticide. I must congratulate the Government to bring about a multi-pronged strategy and I must congratulate the Haryana Legal Authority. I must congratulate Shri H.R. Bhardwaj, Union Law Minister, Justice Vijender Jain, Justice Adarsh Goel, Justice Dhawan Ji and Justice Santosh Yadav for organizing such an emotionally touching meeting at Kurukshetra. I feel if such meetings are organized in every District, a radical change is about to come. I have seen tears in the eyes of our Union Law Minister Mr. Bhardwaj. His throat was chocked and everybody was touched emotionally in that meeting. I must congratulate the Government for looking after the welfare of the employees and most of the retrenched employees have been re-employed on humanitarian grounds but few are left. I would request the Government that one such employee is Mr. Parkash from village Dhareru. He was working in the Forest Department. He has won his case from the lower Court and he must also be given employment because he is a poor and deserving man. In the end, to bring Haryana No. 1 State, to make

[Dr. Shiv Shankar Bhardwaj]
it healthy, educated, beautiful and prosperous, we have to address the basic issues. I have a four-point programme, which I have been telling everywhere. We should supply clean drinking water to every house. We should have sanitary latrines in every house. We should educate every child upto 12th standard and that education should be job-oriented. There should be stoppage of corruption then these things, I am sure, will be developed simultaneously. In the end, I would say that what I have learned as a student of medicines is that health of the nation is more important than the wealth of the nation. Whenever we are talking of health, we must talk of public health. Thank you.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति : मक्कड़ साहब, आप अपनी बात दस मिनट में खत्म कीजिए क्योंकि बहुत से और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : ठीक है जी । सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि क्या चौटाला साहब इस बात को भूल गये कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो जो विधायक थे उनको उन्होंने परवाणू के एक होटल में ठहराया था और उनके पास खर्चा देने के लिए पैसे नहीं थे ? उन विधायकों को परवाणू के होटल में ठहरा कर चौटाला साहब ने खुद मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी बाद में जिन विधायकों ने होटल में ठहरने के पैसे नहीं दिए थे उनका सामान रख लिया गया था। आज चौटाला साहब अरबों खरबोंपति हैं तो यह पैसा कहां से आया है इसके बारे में बतायें ? उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे इनका होटल का बिल दे सकें। उस समय उनकी हालत क्या थी ? आज वे कानून व्यवस्था की बात करते हैं। सभापति महोदय, अब मैं अपने हल्के के बारे में बताना चाहता हूं। हांसी शहर में एक कालोनी में चौटाला साहब की सरकार के मंत्री ने अपना एक पैट्रोल पम्प लगाया था जबकि उस महकमें के अफसरों ने तो यह कह दिया था कि यह पैट्रोल पम्प इस कालोनी में नहीं लग सकता। लेकिन उस मंत्री जी ने अधिकारियों पर इतना दवाब बनाया कि वहां पर पैट्रोल पम्प खोलने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। उस पैट्रोल पम्प का म्यूनिसिपल कमेटी से कोई नक्शा पास नहीं करवाया हुआ। इसकी शिकायत मैं पहले भी सैशन में कर चुका हूं। वह पैट्रोल पम्प सरकारी जमीन पर गलत तरीके से लगाया हुआ है। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि उस पैट्रोल पम्प की इन्क्वायरी की जाये और जिस पूर्व मंत्री ने गलत तरीके से सरकारी जमीन पर पैट्रोल पम्प लगा रखा है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाये। सभापति महोदय, पिछली सरकार में इस तरह से कानून को नजरअंदाज किया जाता था। जबकि आज हुड्डा साहब की सरकार चारों तरफ विकास के कार्य कर रही है। सिरसा की रैली इस बात का उदाहरण है उस रैली में प्रदेश की जनता ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस तरह से प्रदेश की सरकार ने जो अच्छे कार्य किए उन पर जनता ने मोहर लगाई है जबकि पिछली सरकार के समय में जब भी कोई रैली की जाती थी तो सभी अधिकारीगणों को मजबूर किया जाता था कि वे गाड़ियां पकड़ कर रैली में भेजें। उस समय जब भी कोई रैली सरकार की तरफ से होती थी तो दो दिन पहले लोगों की गाड़ियां पकड़ ली जाती थीं और उनमें थोड़े बहुत लोग जबरदस्ती बिठाकर रैली में भेजे जाते थे जबकि सिरसा रैली में लोग अपनी मर्जी से गये। सिरसा रैली में प्रदेश के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वे हुड्डा साहब के साथ हैं। उसका कारण यह रहा है कि हुड्डा साहब ने पूरे प्रदेश में

विकास कार्य करवाये हैं। सभापति महोदय, हुड्डा साहब की सरकार में हर शहर में, हर नगर में और हर गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर सड़क को पक्का बनवाया जा रहा है और गांवों में आर०सी०सी० की सड़कें बनाई जा रही हैं। सभापति महोदय, हुड्डा साहब का जो हरियाणा प्रदेश को नम्बर-1 प्रदेश बनाने का ऐलान है वह जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है सभी को मालूम है कि हुड्डा साहब का प्रदेश में एजूकेशन के विस्तार के प्रति कितना ज्यादा रूझान है। कहीं पर महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और कहीं पर राजीव गांधी एजूकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। सभापति महोदय, कोई प्रदेश तभी नम्बर-1 प्रदेश बन सकता है जब वहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हों इसलिए हुड्डा साहब शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार ने शिक्षा के लिए योजनागत बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके कुल 2180 करोड़ रुपये किया था और वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 2432 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी तरह से वर्ष 2004-05 में शुरू किये गए "सभी के लिए शिक्षा" मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय को 2005-06 में बढ़ाकर दो गुणा किया और वर्ष 2006-07 में उसमें 85 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 365 करोड़ रुपये किया। सभापति महोदय, समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बातें संक्षिप्त में ही कहूंगा, विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और मेरे क्षेत्र हांसी में भी हो रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र हांसी की तरफ हुड्डा साहब विशेष ध्यान दें क्योंकि पिछली सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। (विघ्न) सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सड़कों के बारे में बहुत सी अच्छी स्कीमें चला रखी हैं। बहुत सी सड़कों का विस्तार किया गया है और बहुत सी सड़कों को पक्का किया गया है। मैं भी अपने हल्के की दो-चार सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा जिनको बनवाना बहुत जरूरी है। एक सड़क डाणा से जमावड़ी तक की कच्ची है जिसको पक्का बनवाना है। (इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य संसदीय सचिव जी इस सड़क की घोषणा भी करके आये थे लेकिन आज तक उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त हांसी से डेपल-रामायण सड़क, जी०टी० रोड़ से रामायण और जी०टी० रोड़ से रामपुरा तक की सड़कों की हालत खराब है। इनके अतिरिक्त और भी कई सड़कें हैं जिनको बनवाने के बारे में मैंने लिखकर दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे हल्के की जो सड़कें कच्ची हैं उन्हें पक्का करवाया जाये और जो सड़क टूटी हुई हैं उनको ठीककरवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में विदेशों से लोग हरियाणा में आ कर इण्डस्ट्री लगा रहे हैं जबकि एक समय ऐसा आ गया था जब पिछली सरकार के समय में उद्योगपति हरियाणा से पलायन कर रहे थे। उसका कारण यह था कि पिछली सरकार के मुखिया चौटाला उद्योगपतियों से पैसे मांगा करता था। उस समय लोग हरियाणा छोड़कर भाग रहे थे लेकिन अब हरियाणा को लोग सबसे पहले सलेक्ट कर रहे हैं और आज हरियाणा में इन्डस्ट्री लगाने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हरियाणा में अमन है, चैन है और शान्ति है। हाँसी के बारे में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हाँसी में स्पीनिंग मिल जो थी वह 30 साल पहले बहुत बढ़िया थी उसका धागा बहुत बढ़िया था लेकिन पिछली चौटाला सरकार ने उस मिल की 45 एकड़ जमीन, उसकी मशीनरी बेचकर पैसा कमाने के लालच में उस इन्डस्ट्री को बन्द करा दिया जिसके कारण हजारों मजदूर आज बेकार होकर सड़कों पर फिर रहे हैं और वे दुहाई दे रहे हैं। हुड्डा

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

साहब से और हरियाणा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हाँसी में उस जमीन पर दोबारा इन्डस्ट्री लगाकर उन सभी मजदूरों को दोबारा काम दिया जाये जो बेकार फिर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब आप वाईड अप करें। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा समय बाकी है। इसके साथ मैं बिजली के बारे में भी यह कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब ने सही में किसान का बेटा होने का सबूत दे दिया है। सबसे पहले 1600 करोड़ रुपये का कर्जा बिजली के बिलों का हुड्डा साहब ने माफ किया। हुड्डा साहब को जैसे ही पता चला कि किसान परेशान हैं उन्होंने एक दम एक कलम से उनका यह पैसा माफ करके हरियाणा के किसानों को लाभ पहुँचाया। मेरी एक प्रार्थना हाँसी के बारे में और है कि हाँसी हल्के में बिजली की जो कमी है उसको पूरा करवा दीजिए ताकि यह दिक्कत दूर हो सके। इसके साथ ही साथ मेरी एक प्रार्थना पीने के पानी के बारे में भी है। यह बात भी ठीक है कि हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा को बराबर का पानी का हिस्सा देने के लिए हाँसी बुटाना नहर, दादूपुर नलवी नहर का काम शुरू करके पूरे हरियाणा को पानी देने का प्रावधान किया है लेकिन मेरे हल्के में अभी भी समस्या है। मेरी एक प्रार्थना हाँसी में सीवरेज के बारे में है। वहां सिवरेज की हालत बहुत ही खराब है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। आपका धन्यवाद।

श्री सोमबीर सिंह (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार को अभी बने 2 साल हुए हैं। इस दो साल के अरसे में सरकार ने जो वायदे किये हैं वह तो पूरे किये ही किये हैं लेकिन उनसे भी हटकर और काम भी किये हैं जबकि इनके बारे में चुनाव के समय कभी कहा नहीं था। इसमें सबसे बड़ा काम जो पूरा किया है वह बिजली के बिलों की माफी का है हालाँकि चुनाव के समय इसके लिए कभी नहीं कहा था। इस बात के लिए चौटाला साहब ने तो सरकार बनाई थी लेकिन बाद में जब उनकी सरकार आई तब वे इस बात को भूल गये। 1600 करोड़ रुपये का कर्जा माफ हो जाने से मेरे अपने जिले में और खास तौर से मेरी कंस्टीच्यूंसी को इसका बहुत फायदा हुआ है। इसी तरह से सिरसा की रैली के अन्दर छोटे दुकानदारों, किसानों, हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों ने जिन्होंने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लिए हुए थे उनका ब्याज माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके बारे में भी चुनाव के समय कभी नहीं कहा था। इससे करीब 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का आम आदमी को फायदा हुआ है। हर क्षेत्र के अन्दर चाहे कृषि का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे रोड का हो, इस सरकार ने काम किये हैं। कृषि के सुधार के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। स्पीकर सर, मैं बिजली के बिलों के रेट्स की बात करना चाहूंगा। पहले बागवानी तथा मछली पालन के लिए बिजली के रेट्स किसान को देने पड़ते थे लेकिन इस सरकार ने 50% बिजली के बिलों के रेट्स इनके लिए कम किये हैं जिससे बागवानी के अन्दर बहुत ही बढ़ौतरी हुई है तथा अब किसान ज्यादा क्षेत्र के अन्दर बागवानी पर ज़ोर दे रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गन्ने के भाव की बात है। हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा गन्ने का भाव आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर मिल रहा है। हमारी सरकार ने पशुधन बीमा एक नई योजना शुरू की है जो कि पांच जिलों के अन्दर शुरू की गई है। एक लाख बीस हजार किसानों को इस योजना का लाभ होगा। इसी तरह से हरियाणा को-आपरेटिव एक्ट, 1984 के

अन्दर कुछ प्रावधानों में चेन्जिज़ की गई हैं। पहले यह होता था कि यदि कोई व्यक्ति लोन की अदायगी में डिफाल्टर होता था तो उसको अरैस्ट कर लिया जाता था लेकिन इस सरकार ने इस एक्ट में चेंज करके आम आदमी को अरैस्ट से राहत दिलाई है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज की अदायगी में डिफाल्टर हो जाता है तो अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जमींदार की हिफाज़त करने के लिए कृषि ऋणों पर जो ब्याज पहले 10% होता था उसको कम करके इस सरकार ने 7% किया है। ओलावृष्टि के कारण पिछले महीनें फसलों का जो नुक्सान हुआ था और कल भी वर्षा के कारण फसलों का जो नुक्सान हुआ है इस सरकार ने उस नुक्सान की भरपाई करने के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस हुए नुकसान के लिए स्पैशल गिरदावरी करने का आदेश दिया है और किसानों को उनके हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने के बारे में कहा है। स्पीकर सर, जहां तक मुआवजे की बात है, इस सरकार ने मुआवजे की राशि को रिवाईज किया है और सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा के अन्दर दिया जा रहा है जो कि सराहना के काबिल है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर सिंचाई की बात है, मेरा अपना एरिया जो कि दक्षिणी हरियाणा में जिला भिवानी के अन्दर पड़ता है। स्पीकर सर, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की इस सरकार ने जो सबसे बढ़िया काम किया है वह पानी के समान बंटवारे का है। सरकार ने इस काम से मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी को विशेष लाभ होगा। जो हांसी-बुटाना लिंक कैनाल बनाई जा रही है उम्मीद है कि वह इस साल के आखिर तक कम्पलीट हो जाएगी। इसी तरह से शाहबाद-दादूपुर नलवी नहर का निर्माण कार्य इस सरकार ने शुरू किया है जिससे तीन-चार जिलों अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों को विशेष फायदा होगा। इसी तरह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर तथा जैनरेशन में इस सरकार ने काफी सुधार किये हैं। 36 जगहों पर नये सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं और ऑलरैडी जो सब-स्टेशन्ज़ थे उनकी क्षमता हमारी सरकार ने बढ़ाई है तथा नये ट्रांसफार्मज़ भी लगाए गए हैं। इसी तरह से जहां तक बिजली के प्रोटक्शन की बात आती है, अब तक हरियाणा के अन्दर चार हजार मैगावाट बिजली पैदा होती है और आगे आने वाले समय के लिए सरकार ने मन बनाया है कि पांच हजार मैगावाट बिजली पैदा करेंगे। इसके लिए यमुना नगर का जो थर्मल प्लांट है, उससे इसी साल 300 मैगावाट बिजली मिल जाएगी। इसी तरह से हिसार के अन्दर भी 1200 मैगावाट के पावर प्रोजैक्ट का काम शुरू हो गया है तथा झज्जर में भी एन०टी०पी०सी० के साथ 1200 मैगावाट का ज्वायंट वैंचर के अन्दर प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें करीब साढ़े सात सौ मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। स्पीकर सर, इसी तरह से उद्योग तथा रोजगार की बात लेते हैं, इस सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है। इसी प्रकार से कायदे-कानून में सुधार की वजह से प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है कि बाहर का इण्डस्ट्रियलिस्ट हरियाणा में आना पसन्द करता है। राज्य के अन्दर एस०ई०जैड० की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप वाईंड अप करिये। आपका समय सिर्फ दो मिनट बचा है इसलिए आप वाईंडअप करें।

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं अपनी कांस्टीच्यूंसी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो खेल, ग्रामीण विकास, पब्लिक हैल्थ की बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उन बातों को छोड़ कर अपनी कांस्टीच्यूंसी की बातों का जिक्र करना चाहता हूं विशेष तौर पर मैं रोड्ज का जिक्र करना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्यूंसी के अन्दर कुछेक ऐसी रोड्ज हैं जो कि पिछले करीब आठ-नौ साल

[श्री अमीर चन्द मक्कड]

से रिपेयर नहीं हुई हैं। मैं आपके माध्यम से उन सड़कों का जिक्र करना चाहता हूं सबसे पहली जो रोड़ है वह ईसरवाल से सुदिवास है जो वाया बहल हो कर जाती है, इस रोड़ पर पिछले आठ-नौ साल से कोई काम नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रोड़ को दूसरी रोड़ज की बजाए परैफरैंस दिया जाएगा। इसी तरह से सिगनाऊ से सेहर पहाड़ी नांगल रोड, डिगावा से बहल वाया नक्कीपुर रोड़, डिगावा से बरदूधीरजा रोड़, बहल से सोरदाजादीद सड़कों को भी बनाया जाए। स्पीकर साहब, इसी तरह से मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी लोहारू प्रोपर के अन्दर दो कॉलेज हैं एक तो पोलिटैक्निक कॉलेज है और दूसरा चौधरी बंसी लाल गवर्नमैंट कॉलेज है। लोहारू राजस्थान के साथ बिल्कुल सटा होने के कारण वहां पर स्टाफ की बड़ी कमी है। ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब इस समय हाउस में नहीं हैं। आपके माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगले शैक्षणिक सत्र के अन्दर कम-से कम स्टाफ की पूर्ति जरूर की जाए। इसी तरह से लोहारू के अन्दर कॉलेज में करीब 500 लड़कियां हैं, इनका अलग से विंग है लेकिन वहां पर जो बिल्डिंग है वह किराये की बिल्डिंग है जो कॉलेज के लिए बहुत छोटी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर इस विंग के लिए बिल्डिंग बनाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। चौधरी साहब, बाकी की जो बात रह गई है वह आप लिखवा कर भिजवा दीजिए, वह पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा।

Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 14th March, 2007.

* 15.00 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 14th March, 2007.

42840—H.V.S.—H.G.P., Chd.